सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

19 फरवरी, 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना ।

अष्टादश विधान सभा — वृहस्पतिवार, तिथि 19 फरवरी,2026ई0
द्वितीय सत्र — 30 माघ,1947(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय – 11:00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे । माननीय सदस्य श्री आई0पी0 गुप्ता ।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : आप जीरो आवर में ले लीजिएगा, अच्छा रहेगा ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है महोदय । कल माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी ने सदन में कहा कि जिन माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव लाया है उसके क्षेत्र में काम नहीं होगा । यह अखबारों में बयान छपा है ।

अध्यक्ष : ठीक है, आपने बातों को रख दिया है ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : श्री आई0पी0 गुप्ता ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, यह आपके नियमों में लिखा हुआ है महोदय, यह आपके नियमों में नीचे जुड़ा हुआ है...

अध्यक्ष : आपने बातों को रख दिया ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यहां पर हैं...

(व्यवधान)

(इस अवसर पर ए0आई0एम0आई0एम0 के माननीय सदस्यगण बैनर लेकर वेल में आ गए)

अध्यक्ष : कृपया बैनर नहीं लायें । बैनर हटाइये, यह एलाउ नहीं है ।

(इस अवसर पर ए0आई0एम0आई0एम0 के माननीय सदस्यगणों ने आसन ग्रहण किया)

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, अनुच्छेद 14 में महोदय, 38–39 जैसे निर्देश सिद्धांतों में राज्य को सम्मान न्याय क्षेत्रीय असमानताओं को घटाने और पूरे देश राज्य में कल्याण को बढ़ावा देने की बाध्यता दी गई है । किसी एक क्षेत्र या वहां की जनता को दंडित करने की नीयत से विकास कार्य रोकना यह मनमाना राज कार्य माना जायेगा...

अध्यक्ष : अब बैठिए । अब हो गया ।

श्री कुमार सर्वजीत : जो कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है महोदय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्लीज बैठ जाइये, सारी बात आ गई । आप कहानी में मत ले जाइये ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, माननीय मंत्री जी जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे, आपकी भी जिम्मेवारी थी कि प्रोसीडिंग में वह शब्द नहीं आना चाहिए था । यह प्रोसीडिंग में आया...

अध्यक्ष : यह प्रोसीडिंग से हट जायेगा, बैठ जाइये ।

श्री कुमार सर्वजीत : यह नियम का उल्लंघन है महोदय ।

अध्यक्ष : अब सरकार का जवाब सुन लीजिए ।

श्री कुमार सर्वजीत : सांसद विधायक को सदन के भीतर कही गयी बातों के लिए अगर कुछ भी मिलती है तो आर्टिकल 105, 194 लेकिन इसका, अगर दुरुपयोग की छूट नहीं दी गई है महोदय...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, बैठ जाइये।

श्री कुमार सर्वजीत : इस तरह की बात, यह केवल बाहरी...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कहानी कहने के लिए है । हमने सुन लिया है ।

श्री कुमार सर्वजीत : सदन कार्रवाई कर सकता है महोदय ।

अध्यक्ष : ठीक है, माननीय मंत्री जी ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्यों ने कल हमारे एक मंत्री जी के बयान के बारे में आज सदन में चर्चा की है और उसके बारे में स्पष्टीकरण चाहते हैं तो महोदय, यह सदन और पूरे बिहार के लोग और बिहार की जनता इस बात से वाकिफ है कि हमलोगों की एन0डी0ए0 सरकार, हमारे नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में किसी भी तरह का भेदभाव, पक्षपात नहीं करने के लिए 20 वर्षों से ज्ञात रही है । इसलिए हमलोगों का महोदय, ट्रैक रिकॉर्ड है 20 वर्षों का, परीक्षित रिकॉर्ड है, टेस्टेड है और इसीलिए बिहार की जनता हमको आर्शीवाद देकर इस सदन में बहुमत से भेजती है । हमलोग किसी प्रकार का भेदभाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एन0डी0ए0 सरकार न कभी की है, न कभी करेगी । यह हम सदन के सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहते हैं, बिहार के लोगों को भी आश्वस्त करना चाहते हैं । महोदय, आप भी साक्षी रहते हैं, कभी–कभी सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के हमारे माननीय सदस्य कभी–कभी हास्य–व्यंग्य में कुछ आदान–प्रदान करते हैं और ऐसी परंपरा रही है कि उस तरह के मामलों को इस तरीके से गंभीरता से नहीं लिया जाता है । जहां तक सरकार की बात है, सरकार किसी भी हालत में, किसी प्रकार का विपक्ष के माननीय सदस्यों, ये तो हमलोगों का रिकॉर्ड जनता ने देखा है, कोई हमको वोट दे न दे, हमलोगों ने सबके हित में काम किया है और बिहार के समाज के सभी वर्ग के लोग इस बात के साक्षी हैं कि हमलोग उनके मतदान के व्यवहार से निरपेक्ष होकर, बिल्कुल निरपेक्ष होकर हमलोग

विकास का काम करते हैं और संविधान के जिन अनुच्छेदों का आपने हवाला दिया है, हमारी सरकार, अगर हमारे कार्यशैली काम–काज को आप उसमें से किसी अनुच्छेद पर आप परखिएगा तो हम सिर्फ न उस पर खरा उतरते हैं बल्कि उन मानकों पर सर्वोच्च दिखाई पड़ेंगे, हमारी सरकार सबसे ऊंचा दिखती है महोदय । ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है ।

अध्यक्ष : बात आ गई ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अब इस तरह के विरोध की बात का कोई औचित्य नहीं है।

अध्यक्ष : सरकार का जवाब हो गया, सरकार ने स्पष्ट कह दिया कोई भेदभाव सरकार नहीं करेगी । माननीय सदस्य, आई0पी0 गुप्ता जी ।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय, प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बने, मैं तो इतना ही आपसे आग्रह करता हूं ।

अध्यक्ष : ठीक है, हो जायेगा ।

श्री कुमार सर्वजीत : सदन नियमावली से चलती है ।

अध्यक्ष : बिल्कुल सही ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह तो आसन के अधिकार की बात है । जो कुछ असंसदीय या कोई वैसी बात होगी जिससे प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन होता है, कोई भी ऐसी बात होगी तो आसन सक्षम है निर्णय लेने के लिए।

अध्यक्ष : निश्चित तौर पर प्रोसीडिंग से हटाया जायेगा उन शब्दों को । आई0पी0 गुप्ता जी ।

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न संख्या– ''क''–16, श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र सं0–75, सहरसा)

श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल तालाबों से अतिक्रमण हटाने से संबंधित था जिसका जवाब ऑफलाइन, ऑनलाइन अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष : नहीं हुआ है । माननीय मंत्री जी ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : जवाब नहीं मिला है ।

श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता : नहीं सर ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, इनका जो प्रश्न है महोदय अस्वीकारात्मक है । माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी परियोजना जल–जीवन–हरियाली मिशन के पोर्टल के अंतर्गत राज्य में अवस्थित तालाबों पर हुए अतिक्रमण की समीक्षा की जाती है । वर्तमान में राज्य के 38 जिलों में कुल तालाबों की संख्या 2 लाख 62 हजार 892 है जिसमें अतिक्रमित तालाबों की संख्या 17 हजार 496 थी । उक्त अतिक्रमण तालाबों

में से 17 हजार 491 तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है । ज्ञातव्य हो कि दरभंगा जिले में 2, गोपालगंज में 1, मुंगेर में 1, पटना में 1, कुल 5 तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाना शेष है, जिसे शीघ्र नियमानुसार अतिक्रमण मुक्त कराया जायेगा ।

श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता : महोदय, मेरे पास जो जानकारी है तो नवादा जिला में सिसवा गांव का खाबा पोखर, नवादा जिले के समाय पंचायत के समाय पोखर, औरंगाबाद जिले के गोह बाजार के दुर्गा मंदिर के समीप उसका लिस्ट में वह नाम नहीं है सर । ये वैसे तालाब नहीं हैं जो वर्षों से नहीं हो पा रहे हैं, इसका कारण सिर्फ यह है कि कुछ लोगों का, दबंगों का कब्जा है । हमारे आपके पास घर, मकान, कोठी, बंगला होते हैं उधर जिसको घर बोलते हैं उसको हमलोग झोपड़ी बोलते हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है, अब सुन लीजिए ।

श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता : उनलोगों को हटा दिया गया है । इनलोगों को क्यों नहीं हटा रहे हैं, हम यह सरकार से जानना चाहते हैं । एक बार वेरिफाई करवा लीजिए कि क्या स्थिति है, अगर है तो सरकार उसको हटाए, बस इतना कहना है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो भी इनका है, ये लिखकर के दे देंगे, हम फिर से जांच करवा देंगे और कार्रवाई भी करेंगे ।

श्री अमरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, वहां के जिलाधिकारी ने भी स्वीकारा है कि गरीब–गुरबा, उन्होंने कहा है कि अतिक्रमण है और जवाब में भी आया है ।

अध्यक्ष : सरकार ने कहा है कि हटायेंगे उनको ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : दे दीजिएगा लिख कर ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या–51, श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र सं0–15, केसरिया)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री राम कृपाल यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. स्वीकारात्मक। एग्री स्टैक परियोजना अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री के कार्य में प्रगति लाने के उद्देश्य से राज्य में विशेष अभियान के तहत प्रथम चरण में दिनांक 06.01.2026 से 11.01.2026 तथा द्वितीय चरण में दिनांक 17.01.2026 से 21.01.2026 तक कैम्प का आयोजन किये जाने हेतु प्रधान सचिव, कृषि विभाग द्वारा सभी जिला पदाधिकारी को उक्त पत्र के माध्यम से निदेशित किया गया।

2. स्वीकारात्मक। राज्य में विशेष अभियान के तहत प्रथम चरण में दिनांक 06.01.2026 से 11.01.2026 तथा द्वितीय चरण में दिनांक 17.01.2026 से 21.01.2026 तक कैम्प का आयोजन किया गया है। तृतीय चरण में दिनांक 02.02.2026 से 06.02.2026 तक राज्य के सभी अंचलों में विशेष अभियान के तहत कैम्प का आयोजन किया जा रहा है, जिसका अवधि विस्तार दिनांक

11.02.2026 तक किया गया है ताकि अधिक–से–अधिक किसानों का फार्मर आई.डी. बनाया जा सके।

3. आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य के 38 जिलों में 85,53,570 पी0एम0 किसान सम्मान के पंजीकृत लाभार्थी हैं। राज्य के अब तक पी0एम0–किसान के कुल 25.28 प्रतिशत लाभुकों का फार्मर आई.डी. बनाया जा चुका है।

4. भारत सरकार के एग्रीस्टैक परियोजना अंतर्गत राज्य के सभी रैयत किसानों का फार्मर आई.डी. बनाया जाने हेतु कृषि विभाग तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य के सभी अंचलों के सभी राजस्व ग्रामों में विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। प्राथमिकता के आधार पर, वैसे सभी किसान जो पी0एम0–किसान योजना का लाभ प्राप्त कर रहे है, उनका फार्मर आई.डी. बनाया जा रहा है। वैसे किसान जिनकी जमाबंदी उनके पूर्वजों के नाम पर है, उन सभी किसानों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से स्वयं के नाम से जमाबंदी हस्तांतरित कराने तथा इसके उपरांत फार्मर आई.डी. बनाये जाने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार किया जा रहा है। साथ ही पी0एम0–किसान सम्मान निधि योजना के ऐसे लाभुक, जिनकी जमाबंदी उनके पूर्वजों के नाम पर है, वैसे लाभुकों के नाम से जमाबंदी कायम करने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा किया जा रहा है तथा उनका फार्मर आई.डी. भी बनाया जा रहा है।

अध्यक्ष : इस प्रश्न के लिए माननीय सदस्य श्री मंजीत कुमार सिंह को प्राधिकृत किया गया है ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से जवाब दिया है और माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि राज्य के 38 जिले में 85,53,570 पी0एम0 किसान सम्मान के पंजीकृत लाभार्थी हैं । राज्य में अबतक पी0एम0 किसान के कुल 25.28 प्रतिशत ही लाभुक का फार्मर आई0डी0 बना है और महोदय, यह राजस्व विभाग से संबंधित भी है । चूंकि माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि किसानों, जिनकी जमाबंदी उनके पूर्वजों के नाम पर है उन सभी किसानों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से स्वयं नाम का जमाबंदी हस्तांतरित करने की कार्रवाई चल रही है । अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट बताएं कि राजस्व अभियान जो बिहार में चलाया गया 16 अगस्त से 20 सितंबर, 2025 तक, इसमें 44 लाख 95 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए और वह आवेदन प्राप्त हुए मुख्य रूप से जमाबंदी की त्रुटि के सुधार के लिए, उत्तराधिकार के नामांकन के लिए, बंटवारा नामांकन के लिए, तो संबंधित मामले में अब तक कितने आवेदन का निपटारा किया गया है जिससे किसानों की

आई0डी0 फॉर्म ससमय बनाये जा सकें और भारत सरकार ने इसके लिए क्या समय सीमा निर्धारित की है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, कृषि विभाग ।

टर्न–2 / मुकुल / 19.02.2026

श्री राम कृपाल यादव, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न का जवाब विस्तार रूप से दिया है, बावजूद उसके दिनांक–17.02.2026 के अपराह्न तक राज्य के कुल 45 लाख 18 हजार 744 किसानों का फॉर्मर आई0डी0 बनाया जा चुका है । जिन किसानों की जमीन के सभी कागजात उपलब्ध हैं, उनका फॉर्मर आई0डी0 तुरन्त बनाया जा रहा है, जिनके कागजात में कुछ समस्या है उसके लिए भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है हुजूर । सभी किसानों का फॉर्मर आई0डी0 बनेगा, सरकार इसके लिए दृढ़संकल्प है और कार्य हो रहा है । मैं इस सदन के माध्यम से माननीय सदस्य एवं राज्य के तमाम अन्नदाता किसानों को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि किसी भी पात्र किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना या अन्य किसी सरकारी योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जायेगा, स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमने यह जिक्र किया कि 44 लाख 95 हजार आवेदन अब तक लंबित हैं और जिसका निपटारा नहीं होने के कारण किसानों के जो फॉर्मर आई0डी0 है वह नहीं बन रहा है तो यह सरकार को बताना चाहिए कि कितने दिनों के अंदर जो विशेष अभियान के तहत किसानों के आवेदन प्राप्त किये गये हैं जिसमें जमाबंदी सुधार के लिए है, वह सरकार कब तक इसको पूरा करेगी और हमने दूसरा प्रश्न पूछा है कि मात्र 25 प्रतिशत ही फॉर्मर आई0डी0 बने हैं तो भारत सरकार ने क्या इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित किया है, उसके संबंध में माननीय मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री राम कृपाल यादव, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा कहा कि कृषि विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग दोनों मिलकर के इस काम को कर रहे हैं तो जमाबंदी का कार्य राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित है जैसा कि आपने कहा प्रश्न के माध्यम से और अभी कृषि विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा डोर टू डोर कैंप किया जा रहा है और मैं समझता हूं कि फॉर्मर आई0डी0 बनाया जा रहा है और शीघ्र बनाया जायेगा यह मैं सदन के माध्यम से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा लास्ट प्रश्न है । महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में उल्लेख किया कि प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और इसके

बाद भी अतिरिक्ति समय निर्धारित की गयी आवेदन सत्यापन के लिए दस्तावेजों का, लेकिन अभी भी मात्र 25 प्रतिशत हुआ है । तो अध्यक्ष महोदय, चिंता सरकार की किसानों के प्रति है, हमारी सरकार किसानों के प्रति चिंतित है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के माननीय मंत्री भी हैं उनसे भी यह उत्तर दिलवा दिया जाए कि कब तक आवेदनों का निपटारा कर दिया जायेगा, चूंकि किसान के लिए हमलोग चिंतित हैं अध्यक्ष महोदय ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें थोड़ा जोड़ देना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, इसमें विशेष तौर पर कृषि विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने मिलकर एक संयुक्त अभियान चलाया और इसके लिए हमें प्राइज के तौर पर 500 करोड़ रुपया, असिस्टेंट के तौर पर हमको सहयोग में मिला, मात्र 2 परसेंट इसमें उपलब्धि थी हमारी, दोनों विभाग ने मिलकर बिहार में पिछले डेढ़ से दो महीने में लगभग 50 लाख किसान को इसमें जोड़ने का काम किया यह ऐतिहासिक कार्य दोनों विभाग कर रहा है ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या–52, श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र सं0–62, पूर्णियां)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री राम कृपाल यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय से प्राप्त पत्र अनुसार आई0एस0ए0एम0 की ए0एम0आई0 उप–योजना के तहत आवंटित बजट पूरी तरह से उपयोग हो जाने के कारण योजना का कार्यान्वयन दिनांक–10.06.2025 से बंद है।

उक्त के आलोक में कृषि विपणन निदेशालय का पत्रांक–68, दिनांक–11.02.2026 द्वारा भारत सरकार से अनुरोध कर दिया गया है ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आया है । अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पूरक प्रश्न पूछ लीजिए ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक प्रश्न ही पूछ रहा हूं । एन0डी0ए0 की सरकार में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किसानों के प्रति समर्पित हैं महोदय और कृषि मंत्री भी इस पर ध्यान दे रहे हैं । मेरा जो प्रश्न था उसमें किसानों के लिए केन्द्र प्रायोजित कृषि विपणन योजना (ए0एम0आई0) एवं उप योजना (आई0एस0ए0एम0) जो है इस योजना के अंतर्गत महोदय किसान गोदाम बनाते हैं और कृषि आधारित उद्योग के लिए उनको सब्सिडी दी जाती है । मंत्री महोदय का उत्तर आया है कि 10.06.2025 को यह आवंटन जो है समाप्त हो गया तो 10.06.2025 को यह आवंटन समाप्त हुआ और बिहार के किसानों ने गोदाम बनाने के लिए और कृषि आधारित उद्योग के लिए आवेदन दिया है महोदय, जो लंबित है तो कृषि विभाग इसके लिए, मेरा पहला पूरक प्रश्न है महोदय कि कृषि

विभाग इसकी चिंता करके पहले से ही क्या केन्द्र की सरकार और उसके विभाग से वार्तालाप करके कोई प्रयास की है क्या ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री राम कृपाल यादव, मंत्री : महोदय, मैंने जवाब में ही यह कहा है कि उक्त आलोक में कृषि विपणन निदेशालय का पत्रांक–68, दिनांक–11.02.2026 को भारत सरकार से अनुरोध कर दिया गया है और मैं पुनः सम्पर्क करके इसका निष्पादन जल्द हो जाए और पुनः एक और आदेश आ जाए उसके लिए प्रयास करूंगा ।

अध्यक्ष : श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पूरक प्रश्न था । अध्यक्ष महोदय, सरकार बहुत संवेदनशील है, मुख्यमंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे प्रश्न करने के बाद, जो प्रश्न किया गया, उसके बाद जो है 11.02.2026 को अनुरोध किया गया है । इसका अनुरोध हम पहले भी कर सकते थे ताकि किसान हमारे सफर नहीं करें, मंत्री जी ने आश्वस्त किया है मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस विषय का जल्द ही केन्द्र सरकार से मिलकर निपटारा करेंगे । अध्यक्ष महोदय, बहुत–बहुत धन्यवाद।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या–53, श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह (क्षेत्र सं0–16, कल्याणपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री राम कृपाल यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणन एजेंसी के द्वारा बिहार राज्य के अतिरिक्त देश के अन्य राज्यों में भी जैविक प्रमाणीकरण का कार्य किया जा रहा था, जिससे एजेंसी को प्रमाणीकरण शुल्क के रूप में राजस्व की प्राप्ति होती थी ।

2. आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के बाहर जैविक प्रमाणीकरण का कार्य करने हेतु बिहार राज्य बीज एवं जैविक एजेंसी के जैविक प्रमाणन निरीक्षकों द्वारा विभिन्न जैविक समूहों का निरीक्षण एवं APEDA के NPOP 8th edition 2024, guidelines एवं विभिन्न advisory में अंकित जैविक समूह हेतु मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करवाना था, परन्तु जैविक प्रमाणन निरीक्षकों द्वारा उक्त कार्य को मानक अनुरूप नहीं की/कराई जा सकी । APEDA के Evaluation Committee के द्वारा आकस्मिक निरीक्षण में मानक अनुरूप कार्य नहीं पाये जाने के कारण बिहार राज्य बीज एवं जैविक एजेंसी पर राज्य के बाहर प्रामाणीकरण पर रोक लगाते हुए 5 लाख का जुर्माना लगाया

गया है। इस संबंध में APEDA के NPOP 8th edition 2024 के 6.1.9 में Appeal का प्रावधान है, जिसके तहत बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणन एजेंसी के द्वारा अपील करने की कारवाई की जा रही है।

3. अस्वीकारात्मक है । मानक अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण जैविक प्रमाणन निरीक्षक को बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणन एजेंसी के कार्यालय आदेश सं0 101, दिनांक–09.09.2025 के द्वारा सेवा मुक्त कर दिया गया है ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सवाल माननीय कृषि मंत्री जी से किया है कि बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणन एजेंसी द्वारा प्रमाणन का कार्य बिहार सहित अन्य राज्यों में किया जाता था । इसमें जांच की भारत सरकार की एक संस्था एपीडा ने । यह प्रमाण पत्र जाली वितरित हो रहा था और इसकी जांच की और जांच में यह प्रूफ हो गया कि हां विभाग ने यह गलती की है । सरकार ने जवाब दिया है और सरकार ने भी स्वीकार किया है कि विभाग ने यह गलती की है तो उन्होंने एक छोटे कनीय पदाधिकारी, इंस्पेक्टर रैंक के एक पदाधिकारी पर पूरा चार्ज लगाकर और इस कार्यक्रम को समाप्ति की तरफ ले गया है । महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि डायरेक्टर एग्रीकल्चर जिनके जिम्मे यह काम है, डायरेक्टर एग्रीकल्चर पर आपने क्या कार्रवाई की, दूसरा कि जब एपीडा ने मान लिया कि यह सर्टिफिकेट सारे जाली दिये गये हैं और बिहार के साथ अन्य राज्यों पर प्रमाणन का काम रोक दिया गया इसमें सरकार की भी भत पिट गयी तो पुनः कितने दिनों में यह अन्य राज्यों में जो प्रमाणन का काम करते थे इसको चालू करायेंगे और जब एपीडा ने यह मान लिया है कि यह गलती हुआ है तो फिर आप कह रहे हैं कि मैं अपील करूंगा उसी के यहां, जिस संस्था ने जांच करके यह बता दिया कि यह गलती है तो फिर उसके यहां अपील आप क्या करेंगे तो इसके लिए सरकार क्या कार्रवाई करना चाहती है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री राम कृपाल यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर में साफ तौर पर यह कहा गया है । सरकार ने बिल्कुल इसको गंभीरता से लिया है और हमने जो इसमें जो प्रमाणक निरीक्षक थे उनको सेवा से मुक्त कर दिया तो इस तरह से तो यह सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है ।

अध्यक्ष : श्री प्रमोद कुमार सिंह ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कार्रवाई तो हो गयी, सरकार ने कार्रवाई कर दी है ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पूरक प्रश्न है । महोदय, सरकार ने जो कार्रवाई कर दी है, वही तो मैं कह रहा हूं कि सरकार ने किस पर कार्रवाई

कर दी, सरकार ने इंस्पेक्टर पर कार्रवाई कर दी, ये इसके डायरेक्टर हेड हैं, डायरेक्टर पर आपने कुछ नहीं किया तो क्या डायरेक्टर पर आप कार्रवाई करना चाहते हैं जो इसके अथॉरिटी हैं, सरकार ने कार्रवाई कर दी तो एक कनीय पदाधिकारी पर कर दी और ऐसे अन्य कई इसमें इंस्पेक्टर जिन्होंने यह काम किया है तो जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई मैं यह जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री राम कृपाल यादव, मंत्री : महोदय, मैंने कहा कि जांच के उपरांत निरीक्षक ही उसमें इन्वॉल्व था तो हमने कार्रवाई की और स्पष्ट रूप से सरकार का यह भाव है कि जो भी गड़बड़ी करेंगे उनको पनिशमेंट मिलेगा, नीतीश कुमार जी की सरकार के कमिटमेंट है उसको हम पूरे तौर पर कर रहे हैं और उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं बची है और न बचेगी ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : श्री प्रमोद कुमार । माननीय सदस्य, अब आप बैठिए, हो गया । कार्रवाई हुई है अब आप बैठ जाइये ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : प्लीज बैठ जाइये, नाम पुकार दिया है । मेरा आपसे आग्रह है कि आप बैठ जाइये । ठीक है, सरकार ने संज्ञान ले लिया है ।

टर्न–सुरज / 03 / 19.02.2026

अल्पसूचित प्रश्न सं0–54, श्री राणा रणधीर (क्षेत्र सं0–18, मधुबन)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि वर्षों से डंप पुराने कचरे के जहरीली गैसों के उत्सर्जन, दुर्गंध, जल एवं भूमि प्रदूषण से निजात दिलाने हेतु बायो रेमेडिएशन (Bio-remediation) पद्धति से निस्तारण किया जाता है। इसके अंतर्गत उपलब्ध कचरे पर बायोकल्चर (ई–कम्पोस्टर) (Bioculture E-Composter) का छिड़काव किया जाता है, जिससे डीकम्पोजिशन (Decomposition) की प्रक्रिया होती है तथा डीकम्पोजिशन (Decomposition) के उपरांत दुर्गंध में कमी आती है।

इसी क्रम में राज्य के 54 नगर निकायों में डम्प कचरों का ड्रोन सर्वे के माध्यम से मात्रा ज्ञात कर लिया गया है, जिसमें से 27 नगर निकायों में डम्प कचरों का निस्तारण किया जा रहा है, जबकि 27 नगर निकायों में निविदा के माध्यम से एजेंसी का चयन प्रक्रियाधीन है।

उक्त के अलावे घरों एवं व्यवसायिक स्थलों से निकलने वाले कचरे के प्रसंस्करण हेतु 74 नगर निकायों में जमीन चिह्नित कर मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (Material Recovery Facility) एवं कम्पोस्ट प्लांट (Compost Plant) के निर्माण हेतु एजेंसी का चयन प्रक्रियाधीन है।

(2) नगर निगम पटना के रामचक बैरिया में पूर्व में 10 लाख 25 हजार टन एकत्रित कचरे का निस्तारण किया जा चुका है। वर्तमान में 13 लाख टन में से 48 हजार टन कचरे का निस्तारण ईकोस्टैन इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड (Ecostan Infra Pvt. Ltd.) एजेंसी के माध्यम से किया जा चुका है। शेष कचरे का निस्तारण सितम्बर, 2026 तक करने का लक्ष्य है।

भागलपुर शहर में पूर्व में 1 लाख 60 हजार टन कचरे का निस्तारण किया जा चुका है। शेष 2 लाख 24 हजार टन कचरे के निस्तारण हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है।

(3) पूर्व में बिहार के अन्य 18 शहरों में 18 लाख 33 हजार टन कचरे का निस्तारण किया जा चुका है तथा 19 शहरों में 4 लाख 30 हजार टन कचरे के निस्तारण हेतु कार्यादेश निर्गत है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री प्रमोद कुमार को प्राधिकृत किया गया है ।

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, माननीय मंत्री महोदय का जवाब आया है । मेरा पूरक प्रश्न यह है कि सरकार यह स्पष्ट करे, नगर विकास विभाग कि शहरों और नगर निकायों में कचरा प्रबंधन का मास्टर प्लान पूरे राज्य पैमाने पर क्या तैयार है या नहीं ? अगर तैयार है तो इसमें गीला कचरा, सूखा कचरा इसका क्या सिस्टम है, उस पर पी0पी0 मोड पर करना चाहते हैं कि प्राईवेट एजेंसी से करना चाहते हैं ? इन कचरों के साथ ऊर्जा का निर्माण करना चाहते हैं कि नहीं ? इसके लिये नगर विकास विभाग क्या मास्टर प्लान बनाया है पूरे राज्य के नगर निकाय, नगर निगम और नगर पंचायतों में ? इसके लिये माननीय मंत्री महोदय से जवाब चाहिये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, इनका जो प्रश्न था, विस्तार से और डिटेल में उत्तर दिया गया है और इनको वस्तुस्थिति से अवगत भी कराया गया कि व्यवसायिक स्थलों से निकलने वाले कचरे के प्रसंस्करण हेतु 74 नगर निकाय में जमीन चिन्हित कर मेटेरियल रिकवरी फैसिलिटी एवं कंपोस्ट के निर्माण हेतु एजेंसी का चयन प्रक्रियाधीन है । ये सारी प्रक्रिया, इनका जो प्रश्न है वह पूरा किया गया है ।

नगर निगम पटना के रामचक बैरिया में पूर्व में 10 लाख 25 हजार टन एकत्रित कचरे का निस्तारण किया जा चुका है। वर्तमान में 13 लाख टन में से 48 हजार टन कचरे का निस्तारण ईकोस्टैन इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड

एजेंसी के माध्यम से किया जा चुका है। शेष कचरे का निस्तारण सितम्बर, 2026 तक करने का लक्ष्य है।

भागलपुर शहर में पूर्व में 1 लाख 60 हजार टन कचरे का निस्तारण किया जा चुका है। शेष 2 लाख 24 हजार टन कचरे के निस्तारण हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है।

महोदय, पूर्व में बिहार के अन्य 18 शहरों में 18 लाख 33 हजार टन कचरे का निस्तारण किया जा चुका है । 19 शहरों में 4 लाख 30 हजार टन कचरे के निस्तारण हेतु कार्यादेश निर्गत है और इनका जो अलग से विषय है दे देंगे, हम इसकी समीक्षा भी करा लेंगे ।

डॉ0 सुनील कुमार : महोदय...

अध्यक्ष : पहले प्रमोद जी का हो जाए ।

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, विस्तार से उत्तर दिये हैं । मेरा प्रश्न प्लान के बारे में है, अभी मोतिहारी नगर निगम में कचरा का प्रबंधन था, अक्सर विभिन्न जगहों पर देखा जा रहा है प्लान शुरू होता है फिर बंद हो जाता है । मेरा कहना है कि पी0पी0 मोड पर या प्राईवेट एजेंसी के माध्यम से जो प्रबंधन किया गया, उसमें जो खामियां पायी गयी । वैसे लोगों के विरूद्ध कौन सी कार्रवाई हुई और कहां–कहां प्लांट लगाया गया और जो प्लांट लगाया गया वह ध्वस्त हो गया । खुले में कचरा है तो कचरा से ऊर्जा भी बनाने का प्लान रखते हैं क्या ? यह महोदय मेरा क्लीयर सवाल था । मंत्री जी पूरे शहर का लंबा–चौड़ा उत्तर बता रहे हैं लेकिन प्लान क्या है विभिन्न नगर निकायों के लिये ? यह मंत्री महोदय बताना चाहेंगे ?

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, माननीय सदस्य आ करके मिल लेंगे, डिटेल में इनको बता देंगे । अगर अभी बतायेंगे तो कम्प्लीट करने में समय लगेगा ।

अध्यक्ष : सुनील जी बोलिये ।

डॉ0 सुनील कुमार : महोदय, यह मामला पूरे बिहार राज्य के शहरों में है । शहरों में स्वागत पहले कचरों से ही होता है और यह डेली निकलने वाले कचरे हैं । एक बार अगर उसका विपणन कर दिये तो ऐसा नहीं है कि कल नहीं निकलेगा । इसलिये इसका स्थायी समाधान पूरे बिहार राज्य के शहरों में जरूरत है । इसके लिये सरकार क्या कार्रवाई कर रही है ? यह मैं जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : जिवेश जी बोलिये ।

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से बोलू या नहीं बोलू लेकिन जहां तक पटना का सवाल है । 11 नगर पंचायतों को मिलाकर बी0ए0जी0 के साथ एग्रीमेंट हो चुका है और पटना का बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं मंत्री जी । पटना के 11 इकाई को मिला करके हम गैस भी बनाने जा रहे हैं इससे, खाद्य

भी बनाने जा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मंत्री जी । यह एग्रीमेंट हो चुका है और देश का यह पहला है । भारत सरकार ने इसमें 05 सौ करोड़ रुपये दिया है, मंत्री जी इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं । 11 इकाई को मिलाकर के...

अध्यक्ष : जिवेश जी बैठ जाइये ।

डॉ0 सुनील कुमार : महोदय, माननीय सदस्य प्रॉक्सी मंत्री हैं क्या ? मंत्री जी को जवाब देना है न ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, माननीय सदस्य बिहार शरीफ की चिंता से चिंतित हैं । कल भी हमारे साथ वह बैठे हैं और जिन सदस्य के बारे में इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, वह पूर्व मंत्री रहे हैं और उनका अपना भी अनुभव है । माननीय अध्यक्ष महोदय, सफाई और कचरे को लेकर हम विभाग में समीक्षा भी किये हैं, निर्देशित भी किये हैं और आपके अंदर के दर्द को समझते हुये उसके निदान के लिये हम रणनीति और व्यवस्था, सरकार गंभीरता से बना रही है । व्यक्तिगत आपके पास कोई जानकारी है, जो व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था में लगता है कि यह खामी है, यह कमी है, यह सुधार की जरूरत है तो अलग से दे देंगे, हम उसको गंभीरता के साथ उसके निष्पादन का प्रयास करेंगे ।

डॉ0 सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : मो0 कमरूल होदा । अलग से दे दीजियेगा ।

डॉ0 सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर यह पूरे बिहार का मामला है....

अध्यक्ष : चर्चा किया है उन्होंने, सरकार तैयार है ।

डॉ0 सुनील कुमार : उसका स्थाई निदान करना होगा । मेडिकल कचरे का भी निदान करना होगा । जो एजेंसी अप्वांइटेड है मेडिकल कचरे के लिये, वह भी सप्ताह में एक बार भी कचरा कलेक्ट नहीं करता है...

अध्यक्ष : सरकार ने सारी बातों को संज्ञान में ले लिया है ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0–55, श्री मो0 कमरूल होदा (क्षेत्र सं0–54, किशनगंज)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री राम कृपाल यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि इस संबंध में एपीडा (भारत सरकार का उपक्रम) से पत्राचार किया गया है। एपीडा द्वारा फोन पर सूचित किया गया है कि बिहार के पटना के निकट बिहटा में एक उद्योग विभाग द्वारा स्थापित पैक हाउस के संचालक द्वारा मान्यता हेतु आवेदन दिया गया है जो सम्प्रति विचाराधीन है।

वस्तुस्थिति यह है कि कृषि विभाग अंतर्गत कृषि विपणन निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक–71 दिनांक–13.02.2026 के द्वारा बिहार राज्य में पैक हाउस को मान्यता दिलाने के संबंध में एपीडा से अनुरोध कर दिया गया है।

उक्त से स्पष्ट है कि कृषि विभाग द्वारा इस दिशा में अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है।

अध्यक्ष : उत्तर मिला है न ?

श्री मो0 कमरूल होदा : महोदय, मेरा प्रश्न है एपीडा द्वारा मान्यता प्राप्त भारत के अन्य राज्यों में 203 पैक हाउस खुला है । मेरी जानकारी में बिहार में एक भी पैक हाउस नहीं है । महोदय, किशनगंज जिला में सूर्यापुरी आम उत्पादन होता है, लंगड़ा आम उत्पादन होता है । किशनगंज जिला में अनानास का उत्पादन होता है, ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन होता है और इसी बिहार में भागलपुर है जहां जर्दालू आम की पैदावार होती है, जिस जर्दालू आम को माननीय मुख्यमंत्री महोदय माननीय प्रधानमंत्री जी को हर साल भेजते हैं । महोदय, इसी बिहार में मुजफ्फरपुर में लीची का उत्पादन होता है...

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिये ।

श्री मो0 कमरूल होदा : और यहां पर हाजीपुर में केला होता है और यहां पर तरह–तरह का फ्रूट भी पैदा होता है लेकिन यहां पर एक भी पैक हाउस नहीं है । महोदय, अगर यहां पर पैक हाउस होगा तो किसानों को अच्छी आमदनी मिलेगी, किसानों को लाभ मिलेगा । मेरी मांग है माननीय मंत्री महोदय से कि बिहार के अंदर में सीमांचल में और सीमांचल में ही नहीं बल्कि बिहार में तीन–चार पैक हाउस इस तरह का होना चाहिये । हमारा आयात तो होता है, हम उत्पादन तो करते हैं लेकिन निर्यात नहीं हो रहा है हमारा । निर्यात होकर के विदेशों में हमारा फल–फ्रूट जाए, इसके लिये मैं माननीय मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि इस सीमांचल में और बिहार के अंदर में तीन–चार पैक हाउस खोलने की कृपा की जाए ।

श्री राम कृपाल यादव, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य चिंतिंत हैं और सरकार भी इसे बहुत गंभीरता से ली है । बिहार की सरकार, बिहार के किसानों द्वारा उत्पादित जो फसल हैं, उत्पादों को विदेश तक निर्यात करने के लिये प्रतिबद्ध है और निर्यात के लिये एक्सपोर्ट पैक हाउस भी बनाया जा रहा है । मैं आपको बताऊं कि विभाग द्वारा बिहटा है, यहां से पास में ही है । बिहटा में एक बिल्कुल आधुनिक पैक हाउस का निर्माण कराया जा रहा है और इसकी मान्यता हेतु एपीडा से समन्वय स्थापित किया जा रहा है । कृषि विभाग इसके लिये प्रयासरत है और शीघ्र ही इसको मान्यता भी मिल जायेगी और शीघ्र ही माननीय सदस्य की चिंता भी दूर हो जायेगी ।

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–'क'604, श्री आलोक कुमार मेहता (क्षेत्र सं0–134, उजियारपुर)</u>

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0–1559, श्रीमती अश्वमेध देवी (क्षेत्र सं0–133, समस्तीपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री संजय कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक।

समस्तीपुर जिला अंतर्गत समस्तीपुर प्रखंड में कुल पंचायतों की संख्या–26 अदद है एवं कुल जलापूर्ति योजनाओं की संख्या 237 अदद है। PHED द्वारा 80 अदद वार्डों में 71 अदद योजना अधिष्ठापित है एवं क्रियाशील है जिसके माध्यम से जलापूर्ति सुचारू रूप से की जा रही है। PRD द्वारा हस्तांतरित 142 अदद वार्डों में कुल योजनाओं की संख्या 166 है जो वर्तमान में क्रियाशील है एवं सुचारू रूप से जलापूर्ति की जाती है।

विभिन्न ग्रामों में नल–जल योजना से वंचित टोलों के आच्छादन हेतु कुल 20 अदद योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है एवं कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में 4 अदद योजना का कार्य पूर्ण कर 689 अदद परिवारों को जलापूर्ति चालू कर दी गई है एवं 16 अदद योजनाओं का कार्य प्रगति में है, जिससे 1515 परिवारों को गृह जल संयोजन प्रदान करने का कार्य प्रगति में है। माह मई 2026 तक शेष कार्यों को पूर्ण कर सभी घरों में जलापूर्ति सुनिश्चित कर दी जायेगी।

श्रीमती अश्वमेध देवी : महोदय, इसका उत्तर आया हुआ है, मैं उससे संतुष्ट हूं । लेकिन मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं कि मई महीने में दिया गया है कि पूर्ण करेगा? लेकिन मार्च के बाद ही पानी के लिये हाहाकार मच जायेगा इसलिये पहले हो जाता तो अच्छा रहता ।

श्री संजय कुमार सिंह, मंत्री : महोदय, हमलोग लगातार उसके लिये प्रयासरत हैं और लगातार बैठकें हो रही है और संभवतः उसके पहले ही हमलोग उसको पूरा कर लेने का काम करेंगे ।

टर्न–4 / धिरेन्द्र / 19.02.2026

तारांकित प्रश्न संख्या–1560, श्री प्रमोद कुमार (क्षेत्र संख्या–19, मोतिहारी)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, उक्त भूमि का सीमांकन कराने हेतु नगर आयुक्त के स्तर पर कार्रवाई की जा रही है।

श्री प्रमोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने जो श्मशान की भूमि है उसको पैमाइश कराने हेतु आयुक्त को निर्देशित किया है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि

भूमि पैमाइश के बाद उस पर श्मशान जो आधुनिक इलेक्ट्रिक वाला श्मशान बन रहा है, वह कितने दिनों में मंत्री महोदय बनवा देंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग । माननीय सदस्य श्री प्रमोद कुमार जी का है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, उक्त भूमि का सीमांकन कराने हेतु नगर आयुक्त के स्तर पर कार्रवाई की जा रही है।

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, यह तो हम कह ही रहे हैं, इसी के लिए तो धन्यवाद दिये हैं कि उसका सीमांकन हो रहा है तो सीमांकन उपरांत कितने दिनों में उस पर आधुनिक इलेक्ट्रोनिक वाला श्मशान बन जायेगा ? यह कितने दिनों में बनेगा, यह मेरा मंत्री महोदय से सवाल है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, बहुत जल्दी ही बनेगा । माननीय सदस्य की गंभीरता को देखते हुए जल्द–से–जल्द करा देंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–1561, श्री विशाल कुमार (क्षेत्र संख्या–12, नरकटिया)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री राम कृपाल यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत प्राप्त उर्वरक को पंचायत को आधार मानकर समानुपातिक रूप से आच्छादन के आधार पर प्रखंडवार उपावंटित किया जाता है। रबी 2025–26 में बंजरिया प्रखंड में अब तक 1862.00 एम0टी0 लक्ष्य के विरूद्ध 1597.515 एम0टी0 यूरिया, छौड़ादानों प्रखंड में 2148.00 एम0टी0 लक्ष्य के विरूद्ध 1862.225 एम0टी0 एवं बनकटवा प्रखंड में 1432.00 एम0टी0 लक्ष्य के विरूद्ध 1179.2258 एम0टी0 यूरिया की आपूर्ति की गई है।

पूर्वी चम्पारण जिले में यूरिया की कोई कमी नही है तथा किसानों को ससमय सुगमतापूर्वक यूरिया की प्राप्ति हो रही है।

श्री विशाल कुमार : अध्यक्ष महोदय, जवाब मिला है, उससे असंतुष्ट हूँ । पूर्वी चम्पारण में विभाग कह रहा है कि खाद की कोई कमी नहीं है और मेरे विधान सभा बनकटवा, छौड़ादानों और बंजरिया तीनों प्रखंड में लगभग तीन–तीन एम॰टी॰ यूरिया की सप्लाई कम हुई है तो जब जिला में आपूर्ति पूरी है तब मेरे यहां कम क्यों है ? महोदय, एक यह सवाल बनता है चूंकि उसमें लगभग आठ से दस हजार किसान हमारे प्रभावित हो रहे हैं और मामला वह नहीं है । मेरे विधान सभा क्षेत्र में बनकटवा ब्लॉक जो है वह नेपाल से लगा हुआ ब्लॉक है, वहां पर दस गांव में खाद की अपूर्ति ही विभाग ने दुकानों को और पैक्स को बंद कर रखा है तो वहां के लोगों को ब्लैक में यूरिया खरीदना पड़ता है, समय से आपूर्ति नहीं होती है और महोदय, उसके अलावा...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पूरक पूछ लीजिये ।

श्री विशाल कुमार : महोदय, माननीय मंत्री जी यह मुझे बतायें कि किस कारण से मेरे क्षेत्र में आपूर्ति, जब जिला में आपूर्ति है, विभाग ही कह रहा है कि यूरिया की कमी नहीं है तो मेरे क्षेत्र में आपूर्ति क्यों कम हुई ? माननीय मंत्री जी पहले यह बतायें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, कृषि विभाग । विशाल जी, बैठ जाइये ।

श्री राम कृपाल यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य के प्रश्नों का जवाब दिया है । मगर फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि रबी वर्ष 2025–26 में बंजरिया प्रखंड में अब तक 1862.00 एम॰टी॰ लक्ष्य के विरूद्ध 1597.515 एम॰टी॰ यूरिया, छौड़ादानों प्रखंड के अंतर्गत 2148.00 एम॰टी॰ लक्ष्य के विरूद्ध 1862.225 एम॰टी॰ एवं बनकटवा प्रखंड के अंतर्गत 1432.00 एम॰टी॰ लक्ष्य के विरूद्ध 1179. 2258 एम॰टी॰ यूरिया की आपूर्ति की गई है। वर्तमान में वर्ष 2025–26 में खरीफ और रबी मौसम में पूर्वी चम्पारण जिला में यूरिया की महामार आवश्यकता की उपलब्धता निम्नतम है । महोदय, आप कहेंगे तो मैं विस्तार से कह दूं । अप्रैल, 2025 में 4750 एम॰टी॰, उपलब्धता है 7997 एम॰टी॰ यानी 168 प्रतिशत आपूर्ति की जा रही है आवश्यकता से ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, एक बार समीक्षा कर लीजिये ।

श्री राम कृपाल यादव, मंत्री : महोदय, उसके बाद मई, 2025 में 4750 एम॰टी॰, और 8200 एम॰टी॰ उपलब्धता है यानी 174 प्रतिशत है । जून, 2025 में, तो यह विस्तार से. ...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, एक बार समीक्षा कर लीजिये यदि अगर जरूरत पड़े तो बढ़वा दीजिये । माननीय सदस्या श्रीमती देवंती यादव ।

श्री विशाल कुमार : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट । महोदय, मैं आपके माध्यम से एक सुझाव माननीय मंत्री महोदय को देना चाहूँगा । मंत्री जी, हमारे जिला में खाद की कमी नहीं है यह विभाग भी मानता है और कालाबाजारी भी हो रही है यह भी विभाग जानता है । महोदय, हम कुछ नाम आपको देते हैं । क्यों समस्या है हमारे जिला में, क्या समस्या है जरा उसको देख लीजिये ? हम कुछ सुझाव आपको देते हैं । एक राहुल कुमार सिंह हैं, ये पौधा संरक्षण भभुआ जिला में हैं और रहने वाले सीतामढ़ी के हैं, ये हमारे जिला में क्या करते हैं ? इनके टावर लोकेशन और सी॰डी॰आर॰ की जांच की जाय । एक संजय सिंह, कृषि समन्वयक हैं, ये रामगढ़वा ब्लॉक में पोस्टेड थे, किस स्थिति में इनको बनकटवा लाया गया ? दूसरा कि साकम्भरी इंटरप्राइजेज और चंपारण फर्टिलाइजर, यह एक ही व्यक्ति के दो प्रतिष्ठान हैं, ये पश्चिमी चम्पारण में और पूर्वी चम्पारण में इनका है । महोदय, इनको किस अनुपात में खाद उपलब्ध कराया जा रहा है, एक रैक में एक हजार मीट्रिक टन के लगभग इनको दिया जाता है और दूसरे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को 50 टन और 100 टन दिया जाता है तो इतना क्यों

डिफरेंसेज है ? इनकी भूमिका की जांच हो । दूसरा, मंत्री जी, मैं आपको एक सुझाव दे देता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सुझाव दे दीजिये । मंत्री जी, सुझाव सुन लीजिये ।

श्री विशाल कुमार : महोदय, इन सारी समस्याओं का समाधान क्या है हमलोगों के नजर में. ...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुझाव दे दीजिये ।

श्री विशाल कुमार : महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूँ कि खाद की आपूर्ति के लिए जिस प्रखंड में जो डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर है उनको उसी प्रखंड में अपने खुदरा दुकानदारों को आपूर्ति करने का निर्देश दिया जाय । दूसरा कि बॉर्डर एरिया में जो भी खाद पकड़ा जाता है उसको उस प्रखंड में, जैसे बनकटवा में अगर खाद पकड़ा गया तो उसको वहां किसी दुकानदार को या किसी पैक्स को सुपुर्द न कर उसको किसी दूसरे प्रखंड में सुपुर्द किया जाय ताकि पुनः वह खाद कालाबाजारी की भेंट न चढ़े । तीसरा है कि जो भी कृषि समन्वयक हैं या किसान सलाहकार हैं, अगर आप दुकानों की आपूर्ति बंद करते हैं बॉर्डर एरिया के नाम पर तो वहां के किसानों को खाद उपलब्ध हो, इसके लिए विभाग के द्वारा पैक्स के माध्यम से या दुकानों पर ही कृषि सलाहकार की नियुक्ति कर खाद बंटवाने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, कृषि विभाग ।

श्री राम कृपाल यादव, मंत्री : महोदय, अगर कालाबाजारी हो रही है तो सरकार का ध्यान भी है और कार्रवाई भी हो रही है । महोदय, मैं बता देता हूँ कि पूर्वी चम्पारण में उर्वरक की जो कालाबाजारी है या अनियमितता हुई है उसमें 12 एफ॰आई॰आर॰ किये गए हैं, 19 लाइसेंस रद्द किए गए हैं और लाइसेंस निलंबित भी किए गए हैं पूरे बिहार में । पूरे बिहार में 104 एफ॰आई॰आर॰ और लगभग 419 लाइसेंस भी रद्द किए गए हैं । आपने जो बातें कही हैं, उसको मैं दिखवा लूंगा और जो उचित हो सकता है वह कार्रवाई होगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती देवंती यादव ।

(व्यवधान)

खेमका जी, सुन लीजिये । यह मामला पूर्वी चम्पारण का है ।

(व्यवधान)

श्री नीरज कुमार सिंह उर्फ बब्लू सिंह : महोदय, कार्रवाई भी हो रही है और एफ॰आई॰आर॰ भी दर्ज हो रहा है । महोदय, सच्चाई है कि एफ॰आई॰आर॰ दर्ज हो रहा है और गिरफ्तारी भी हो रही है लेकिन उससे बड़ी सच्चाई यह है कि यह कालाबाजारी रूक नहीं रही है । हमलोग का क्षेत्र भी नेपाल के बॉर्डर पर है। महोदय, किसान परेशान है, सारा खाद नेपाल चला जाता है और वे कहते हैं कि बड़े–बड़े होलसेलर हैं जो ये काम करते हैं और डीलर कहता है कि रेट में यह फर्क है, हमलोगों को सही रेट में मिलता ही नहीं है तो हम कहां से किसान

को सही रेट में देंगे तो इस रेट का डिफरेंसेज कैसे सही होगा ? यह भी देखा जाय और यह सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा कि कालाबाजारी के लिए हम एफ॰आई॰आर॰ कर रहे हैं । कालाबाजारी कैसे रूकेगी, इस पर काम होना चाहिए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, पूरे मामले को देख लीजिये । माननीय सदस्या, श्रीमती देवंती यादव ।

(व्यवधान)

सारी बात बब्लू जी ने कह दिया है । सरकार सारे मामले को देखेगी और कार्रवाई भी करेगी । श्रीमती देवंती यादव । बब्लू जी बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

करायेगी । सरकार ने कहा है कि जांच करायेगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1562, श्रीमती देवंती यादव (क्षेत्र संख्या–46, नरपतगंज)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, स्वीकारात्मक। नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक–330, दिनांक–04.02.2026 के द्वारा आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–3 योजना अन्तर्गत मोक्षधाम निर्माण हेतु नगर पंचायत क्षेत्र में 0.50 एकड़ जमीन की उपलब्धता की आवश्यकता है, जिसके आलोक में नगर पंचायत नरपतगंज क्षेत्रान्तर्गत मोक्षधाम के निर्माण हेतु भूमि चिह्नित कर ली गई है।

श्री देवंती यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक है । जवाब मुझे मिला है कि भूमि चिन्हित कर ली गई है । वह जमीन कहां पर चिन्हित की गई है और कितना दिन लगेगा मुक्तिधाम बनने में ? वहां के लोगों की परेशानी को देखते हुए मंत्री जी बतायें। महोदय, एक समय–सीमा होनी चाहिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, कार्यपालक पदाधिकारी, नरपतगंज नगर पंचायत को हमलोग पत्र भेजे हैं, पत्रांक–111, दिनांक–22.01.2026 के द्वारा और वह डिटेल में अनापत्ति प्रमाण–पत्र उपलब्ध करा रहे हैं । उनका जो जमीन दिया गया है वह फाइनल कर एन॰ओ॰सी॰ जो भेजेंगे तो उसके बाद हम इनको उपलब्ध करा देंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1563, श्रीमती सोनम रानी (क्षेत्र संख्या–44, त्रिवेणीगंज(अ॰जा॰))

(लिखित उत्तर)

श्री राम कृपाल यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1– स्वीकारात्मक ।

2–आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज एवं प्रतापगंज प्रखंड में एक–एक कोल्ड स्टोरेज कार्यरत

है, जिसकी भण्डारण क्षमता क्रमशः 6000 एवं 5500 कुल 11500 मेट्रिक टन है, जहाँ पर किसान आलू एवं अन्य सब्जियों का भण्डारण कर सकते है।

3–कृषि विभाग द्वारा कोल्ड स्टोरेज का निर्माण नहीं किया जाता है। यदि कोई निवेशक/उद्यमी/कृषक कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराना चाहते हैं, तो उन्हें एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजनान्तर्गत ऋण संबंधित अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। कोल्ड स्टोरेज Type-I के निर्माण हेतु, अधिकतम ₹1.68 करोड़ एवं Type-II हेतु अधिकतम ₹2.10 करोड़ तक निवेशकों/उद्यमियों/कृषकों को सहायता दी जाती है।

इसके अतिरिक्त, कृषकों हेतु राज्य योजना मद से 10 डज सोलर कोल्ड रूम का प्रावधान है, जिस पर 50 प्रतिशत अर्थात् ₹12.35 लाख (बारह लाख पैतीस हजार) रूपये अनुदान भी दी जा रही है।

इच्छुक निवेशक/उद्यमी/कृषक उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग के वेबसाइट www.horticulture.bihar.gov.in पर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट योजना में ऑनलाईन आवेदन कर, योजना का लाभ, ले सकते हैं।

श्रीमती सोनम रानी : अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला है । उत्तर से संतुष्ट हूँ ।

टर्न–5 / अंजली / 19.02.2026

तारांकित प्रश्न सं॰–1564, श्री अनिल सिंह (क्षेत्र सं॰–236, हिसुआ)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : 1. अस्वीकारात्मक है । समहर्त्ता पटना के प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति यह है कि सर्वे खतियान के अनुसार खाता संख्या–912 में खेसरा संख्या–218 नहीं है । खेसरा संख्या–218 का सही खाता संख्या–922 है । वर्तमान में प्रश्नगत खेसरा संख्या–218 में कुल 37 रैयतों के नाम से ऑनलाइन जमाबंदी चल रही है ।

2. आंशिक स्वीकारात्मक । वर्तमान में तारांकित प्रश्न में अंकित खाता संख्या–912 से संबंधित कोई भी जमाबंदी ऑनलाइन नहीं चल रही है तथा खेसरा संख्या–218 में कुल–37 रैयतों के नाम से ऑनलाइन जमाबंदी चल रही है । साथ ही, खाता संख्या–922 में कुल 72 रैयतों के नाम से ऑनलाइन जमाबंदी चल रही है, जिसका अवलोकन राजस्व विभागीय पोर्टल (https://parimarjan.bihar.gov.in/biharBhumireport/ViewJamabandi) पर किया जा सकता है ।

3. संबंधित रैयत द्वारा यदि वांछित कागजात / साक्ष्य के साथ ऑनलाइन परिमार्जन प्लस के माध्यम से आवेदन किया जाता है, तो आवेदन के

साथ संलग्न दस्तावेज के अनुसार जाँचोपरान्त नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अनिल सिंह । उत्तर मिला है न ?

श्री अनिल सिंह : जी महोदय, उत्तर मिला है लेकिन भ्रामक उत्तर है ।

अध्यक्ष : पूरक प्रश्न पूछ लीजिए ।

श्री अनिल सिंह : महोदय, यह प्रश्नगत जमीन से संबंधित है, वर्ष 2013 में इसकी रजिस्ट्री हुई, वर्ष 2016 में इसका म्यूटेशन हुआ, डिजिटलाइजेशन के लिए हमने अप्लाई किया, अप्लाई जब किया तो उसमें जवाब दिया गया कि यह जमीन रजिस्टर–2 में दर्ज नहीं है और खंड–3 में उत्तर में दिया गया है कि संबंधित रैयत द्वारा यदि वांछित कागजात/साक्ष्य के साथ ऑनलाइन परिमार्जन प्लस के माध्यम से आवेदन किया जाता है, तो आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज के अनुसार जाँचोपरान्त नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी, तो जब हमने परिमार्जन प्लस के लिए आवेदन किया, तो इन्होंने काऊज गलत डालकर इसको रिजेक्ट कर दिया, दूसरा, अभी खंड–3 में वही चीज ये बोल रहे हैं फिर वह आएगा । महोदय, दो में से एक तो सही है या तो हमने परिमार्जन प्लस के लिए जो आवेदन दिया और रिजेक्ट किया या तो यह सही है या वर्ष 2016 में जो म्यूटेशन कराया गया है वह गलत है, मैं माननीय मंत्री महोदय से इतना ही जानना चाहता हूं कि क्या ये दोनों की समीक्षा करते हुए, जिसने या तो गलत प्रतिवेदन प्रतिवेदित किया है उस पदाधिकारी के विरुद्ध या जिसने गलत म्यूटेशन किया है उसके विरुद्ध ये कौन–सी कार्रवाई करने का विचार रखते हैं ?

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने जांच की बात कही है, हम जांच करवाकर दोषी होंगे तो जरूर कार्रवाई होगी ।

श्री अनिल सिंह : बहुत–बहुत धन्यवाद ।

<u>तारांकित प्रश्न सं॰–1565, श्री मो॰ तौसीफ आलम (क्षेत्र सं॰–52, बहादुरगंज)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री संजय कुमार सिंह, मंत्री : स्वीकारात्मक । किशनगंज जिला अंतर्गत प्रखंड टेढ़ागाछ में बीस हजार गैलन क्षमता वाले जलमीनार निर्माण के क्रम में ही दिनांक–01.05.2014 को धराशायी होने के उपरांत संवेदक द्वारा अपने खर्च पर जलमीनार का पुनर्निर्माण कराया गया । परंतु निर्मित जलमीनार से संबंधित तकनीकी दस्तावेज संदेहास्पद/असंतोषप्रद रहने के कारण भुगतान लंबित है । जलमीनार का लंबित भुगतान हेतु संवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में वाद दायर किया गया है । वर्तमान में टेढ़ागाछ ग्रामीण जलापूर्ति योजना से सीधी जलापूर्ति के माध्यम से आंशिक रूप से जलापूर्ति की जा रही है ।

2. आंशिक स्वीकारात्मक । टेढ़ागाछ ग्रामीण जलापूर्ति योजना से पंचायत हाटगांव के वार्ड संख्या–01 में 12 घर एवं वार्ड संख्या–04 में 18 घरों में गृह संयोजन के माध्यम से सीधी जलापूर्ति की जा रही है ।

विभिन्न निर्माण क्रम यथा अररिया–किशनगंज रेलवे लाइन, पुलिया तथा सड़क निर्माण क्रम में कई स्थलों पर पाईप लाइन क्षतिग्रस्त हो गया है। वार्ड संख्या–01 एवं 04 को गृह संयोजन के माध्यम से पूर्ण आच्छादित करने हेतु छुटे हुए टोलों में सम्मिलित कर निविदा/पुनर्निविदा की कार्रवाई की गयी है । परन्तु अद्यतन माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा स्थगन आदेश के कारण पुनर्निविदा पर अग्रेतर कार्रवाई लंबित है ।

3. उपर्युक्त कंडिका 01 एवं 02 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

अध्यक्ष : उत्तर मिला है ?

श्री मो॰ तौसीफ आलम : महोदय, मैं पूछता हूं । महोदय, उत्तर मिला है ।

अध्यक्ष : पूरक प्रश्न पूछ लीजिए ।

श्री मो॰ तौसीफ आलम : महोदय, हमने वर्ष 2014 में भी इस प्रश्न का क्वेश्चन किया था । वर्ष 2014 में हमको जवाब मिला था कि उसको कर दिया जाएगा, जवाब में लिखा है कि वह गिर गया था लेकिन गिरा नहीं था, वर्ष 2014 में जब हम जलमीनार का क्वेश्चन किए, क्योंकि टेढ़ा बनाया था, तो उसको तोड़कर फिर से बनाया गया लेकिन वर्ष 2014 से 2025 करीब 11 साल हो गया, आज तक जलमीनार का पानी किसी को नहीं मिला है, जबकि वहां प्रखंड कार्यालय है, अंचल कार्यालय है, थाना है और नेपाल की सीमा में एकमात्र जलमीनार उस समय बना था, लोगों में खुशी थी कि चलो एक जलमीनार बन रहा है लेकिन आज तक पानी नहीं मिल रहा है और सरकार ने जवाब दिया है कि यह मामला कोर्ट में चला गया है, ठेकेदार कोर्ट में गया है । हम कहते हैं कि ठेकेदार कोर्ट में गया, उस समय में जब टेढ़ा बनाया गया था, तो वहां के जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं, उन पर उस समय कार्रवाई क्यों नहीं हुआ और पानी कैसे मिलेगा वहां की जनता को, प्रखंड को, अंचल को, थाना को यह मैं सरकार से जवाब जानना चाहता हूं ।

श्री संजय कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है, मैं बताना चाहूंगा कि उस समय जो संवेदक थे, संवेदक के ऊपर पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है और संवेदक के ऊपर कार्रवाई के साथ–साथ जो विभागीय पदाधिकारी थे उन पर भी कार्रवाई की गई है और चूंकि यह मामला माननीय न्यायालय में लंबित है और जहां तक रही जलापूर्ति की बात, तो वर्तमान में टेढ़ागाछ ग्रामीण जलापूर्ति योजना से सीधा जलापूर्ति के माध्यम से आंशिक रूप से जलापूर्ति की जा रही है ।

श्री मो॰ तौसीफ आलम : महोदय, जलमीनार जो बना हुआ है उससे पानी हमको कब मिलेगा ? आप कहीं से पानी हमको दिला रहे हैं या दे रहे हैं उससे हमको

मतलब नहीं है । वर्ष 2014 में जो जलमीनार बना, उससे पानी आप कब तक दिला रहे हैं ?

अध्यक्ष : जनता को पानी से मतलब है न ।

श्री मो॰ तौसीफ आलम : जी महोदय । महोदय, जलमीनार से भी मतलब है हुजूर, क्योंकि वह बिहार सरकार की संपत्ति है ।

अध्यक्ष : यह मामला कोर्ट में है । माननीय सदस्य, मामला कोर्ट में है । कोर्ट का फैसला आने दीजिए कार्रवाई होगी ।

श्री मो॰ तौसीफ आलम : महोदय, नहीं–नहीं, ठेकेदार पर कार्रवाई हो । जलमीनार तो चालू कर सकती है न सरकार । वह केस किया है अपना पैसा के लिए ।

अध्यक्ष : मंत्री जी, एक बार दिखवा लीजिए ।

श्री संजय कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह मामला माननीय न्यायालय में लंबित भी है और हमने माननीय सदस्य को पहले भी बताया है कि पहले भी संवेदक पर ऑलरेडी कार्रवाई की जा चुकी है और माननीय न्यायालय का जब तक फैसला नहीं आ जाता, हमलोग उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टे ऑर्डर लगा हुआ है ।

अध्यक्ष : श्री मंजीत कुमार सिंह ।

श्री मो॰ तौसीफ आलम : हुजूर, पानी कब मिलेगा यह बता दीजिए ?

अध्यक्ष : आप चाहते हैं कि टंकी से पानी मिले, यही न कहना चाहते हैं कि पानी टंकी से मिले । पानी मिल रहा है ।

श्री मो॰ तौसीफ आलम : महोदय, पानी नहीं मिल रहा है, मैं चुनौती दे रहा हूं हुजूर, जलमीनार से पानी नहीं मिल रहा है यह चुनौती मैं दे रहा हूं ।

अध्यक्ष : सही बात है, उन्होंने स्वीकारा है कि मामला न्यायालय में है, जनता को अन्य स्रोत से पानी मिल रहा है ।

श्री मो॰ तौसीफ आलम : नहीं मिल रहा है उससे पानी ।

अध्यक्ष : उससे नहीं, अन्य स्रोत से । अन्य जगह से पानी आ रहा है ।

श्री मो॰ तौसीफ आलम : महोदय, नया वाला जो बनाया है उससे पानी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वह कब चालू होगा यह हम जानना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : अब न्यायालय के फैसले के बाद ही हो पाएगा । आप बैठिए । माननीय सदस्य, श्री मंजीत कुमार सिंह ।

<u>तारांकित प्रश्न सं॰–1566, श्री मंजीत कुमार सिंह (क्षेत्र सं॰–100, बरौली)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : दिनांक–30.04.2025 को सम्पन्न नगर परिषद् बोर्ड की बैठक के प्रस्ताव संख्या–01 में प्राथमिकता के आधार पर क्रम संख्या–7 एवं 10 पर योजनाएँ राज्य योजना के रूप में प्रस्तावित एवं चयनित हैं ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है और माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह उल्लेख किया है कि दिनांक–30.04.2025 को सम्पन्न नगर परिषद् बोर्ड बरौली की बैठक के प्रस्ताव संख्या–01 में प्राथमिकता के आधार पर क्रम संख्या–7 एवं 10 पर योजनाएँ राज्य योजना के रूप में प्रस्तावित एवं चयनित है । महोदय, 30.04.2025 को नगर परिषद् बरौली की बैठक हुई, उसमें दस योजनाओं का चयन किया गया, लगभग 9 करोड़ से अधिक की योजनाएं थीं । महोदय, इतना लंबा समय बीत गया और विकास के लिए हमारी सरकार कृतसंकल्पित है, तो मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि दस योजना में केवल तीन योजना ही क्यों प्रस्तावित किया गया, चयनित किया गया राज्य योजना मद में और शेष योजना को क्या राज्य योजना मद में चयनित करते हुए इसी वित्तीय वर्ष में सरकार उन योजनाओं को पूर्ण कराने का विचार रखती है कि नहीं ?

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि दिनांक–30.04.2025 को सम्पन्न बोर्ड की बैठक में योजना का प्रस्ताव प्रस्तावित एवं चयनित है । महोदय, लंबे समय नहीं उस पर प्रक्रिया जारी था, अधीक्षण अभियंता, नगर विकास अंचल सारण, छपरा के पत्रांक–353, दिनांक–03.09.2025 द्वारा प्राक्कलन का तकनीकी अनुमोदन भी प्राप्त हुआ है और कार्यालय पत्रांक–1687, दिनांक–11.12.2025 से प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना को टंकन भूल से प्रशासनिक स्वीकृति के स्थान पर राशि आवंटन हेतु पत्र निर्गत किया गया है, तो पुनः कार्यालय द्वारा विभाग को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजने की कार्रवाई की जा रही है । इन्होंने जो दस योजना की बात कही, तो तीन ही योजना क्यों स्वीकृत हुई उसको हम दिखवा लेते हैं, माननीय सदस्य मिल लेंगे, हम बता देंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न सं०–1567, प्रो० नागेन्द्र राउत (क्षेत्र सं०–26, सुरसंड)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री संजय कुमार सिंह, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सुरसंड, चोरौत एवं पुपरी प्रखंड में वर्तमान में औसत भूजल स्तर क्रमशः 15'6'', 15'4'' एवं 15'2'' है । प्रखंड–सुरसंड में 1812 अदद साधारण चापाकल एवं 309 अदद इंडिया मार्क–II/III चापाकल, प्रखंड–चोरौत में 583 अदद साधारण चापाकल एवं 207 अदद इंडिया मार्क–II/III चापाकल तथा पुपरी में 1089 अदद साधारण चापाकल एवं 261 अदद इंडिया मार्क–II/III चालू अवस्था में है । प्रखण्ड सुरसंड में कुल 209 वार्डों में PHED द्वारा निर्मित 23 योजना एवं पंचायती राज विभाग द्वारा हस्तांतरित 187 योजना कार्यरत है । प्रखण्ड–चोरौत में कुल 93 वार्डो में PHED द्वारा निर्मित, 04 योजना एवं पंचायती राज विभाग द्वारा हस्तांतरित 88 योजना कार्यरत है एवं पुपरी में 155 वार्डों में PHED द्वारा

निर्मित 03 योजना एवं पंचायती राज विभाग द्वारा हस्तांतरित 176 योजना कार्यरत है, जिसका संचालन एवं रख–रखाव कार्य कर जलापूर्ति की जा रही है । पंचायती राज विभाग द्वारा हस्तांतरित योजनाओं में प्रखंड–सुरसंड, चोरौत एवं पुपरी अंतर्गत क्रमशः 27, 26 एवं 34 अदद छूटे हुए टोला थे, इन छूटे हुए टोलों में योजना का निर्माण कार्य प्रगति में है । जिसे मई–2026 तक पूर्ण कर जलापूर्ति बहाल कर दी जाएगी । वर्तमान में पेयजल संकट की स्थिति नहीं है ।

गत वर्ष 2025 के अगस्त–सितम्बर में सुखाड़ (आपदा) में प्रखंड–सुरसंड, चोरौत एवं पुपरी का औसत जल स्तर–22′2′′, 19′4′′ एवं 20′2′′ था । जिसके बाद तीनों प्रखंडों में क्रमशः 18, 12 एवं 06 अदद साधारण चापाकलों को विशेष चापाकलों में परिवर्तन (Conversion) का कार्य कराया गया । वर्ष 2025–26 में प्रखंड–सुरसंड, चोरौत एवं पुपरी में क्रमशः 199, 34 एवं 145 अदद चापाकलों का साधारण मरम्मती एवं 09, 05 एवं 04 अदद नये इंडिया मार्क–II चापाकलों का निर्माण कार्य कराया गया ।

साथ ही पेयजल की समस्या के समाधान हेतु जिला स्तर पर प्रमंडलीय नियंत्रण कंक्ष तथा राज्य स्तर पर केंद्रीयकृत शिकायत निवारण कोषांग (CGRC) का गठन किया गया है जिसका Toll Free No–18001231121 है, ताकि पेयजल से संबंधित समस्या का शीघ्र निष्पादन किया जा सके ।

प्रो॰ नागेन्द्र राउत : महोदय, मैं पूछता हूं । उत्तर मिला है महोदय ।

अध्यक्ष : पूरक प्रश्न पूछ लीजिए ।

प्रो॰ नागेन्द्र राउत : महोदय, पूरक भी यही है कि चापाकल या नल–जल जो बताया गया है कि संचालित है, चालू है, उसमें अभी कुछ काम करने की भी जरूरत है, जहां–तहां की नल–जल योजना सही से, खासकर जो स्थानांतरित हुआ है पंचायती राज विभाग से, उस नल–जल योजना में बड़ी खामियां हैं, तो उसको दूर किया जाए, चूंकि हमारे क्षेत्र में जल संकट आने ही वाला है, अभी समय है, समय रहते उसको दूर करें, यही हम अपेक्षा रखते हैं ।

श्री संजय कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता के आलोक में सूचित करना है कि विगत वर्ष सीतामढ़ी जिला में भूजल स्तर नीचे चले जाने के कारण कतिपय समस्या आई थी, जिसे विभाग द्वारा तत्परता से दूर करने का प्रयास भी किया गया था । महोदय, वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है, परंतु आगामी गर्मी के पहले भूजल स्तर नीचे जाने पर विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार इंडिया मार्क–III चापाकल 60 फीट से अधिक स्तर पर होने पर पानी देता है, कार्य अधिष्ठापन साधारण चापाकल को, विशेष चापाकल में परिवर्तन कर कन्वर्सन एवं आकस्मिक स्थिति में टैंकर के द्वारा पानी की जलापूर्ति की जाती है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री सुरेंद्र प्रसाद ।

तारांकित प्रश्न सं॰–1568, श्री सुरेंद्र प्रसाद (क्षेत्र सं॰–01, वाल्मीकिनगर)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक है । समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति यह है कि नौरंगिया उत्क्रमित उच्च माध्यमिक स्कूल+2 का भवन निर्माण कराये जाने हेतु मौजा–नौरंगिया/26, खाता संख्या–65, खेसरा संख्या–109/1, रकबा 1–25 डी० भू–हस्तांतरण से संबंधित अभिलेख संख्या–51/2024–25 अंचल अधिकारी, बगहा–2 के द्वारा उचित माध्यम से जिला कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है तथा भवन निर्माण हेतु भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव वर्तमान में प्रक्रियाधीन है ।

उक्त भूमि पर वर्तमान में कोई स्थायी अतिक्रमण नहीं है।

उपर्युक्त खंड में स्थिति स्पष्ट की गयी है ।

श्री सुरेंद्र प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो मिला है लेकिन हम माननी मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि स्कूल के भवन का कब तक निर्माण हो जाएगा कि बच्चे कम से कम बिल्डिंग में पढ़ सकें, नहीं तो आज की डेट में वहां पर अधिकतर स्कूल में बच्चे सब बाहर ही कहीं पीपल के पेड़ के नीचे और किसी गांछ के नीचे अभी भी पढ़ रहे हैं और बहुत जगह ऐसा है कि एक ही क्लास में दो–दो क्लास के बच्चे सब पढ़ते हैं, तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि कब तक बिल्डिंग का निर्माण होगा ?

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, जवाब इनको स्पष्ट तौर पर हमने दिया है कि आंशिक स्वीकारात्मक है । समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति यह है कि नौरंगिया उत्क्रमित उच्च माध्यमिक स्कूल +2 का भवन निर्माण कराये जाने हेतु मौजा–नौरंगिया/26, खाता संख्या–65, खेसरा संख्या–109/1, रकबा 1–25 डिसमिल भू–हस्तांतरण से संबंधित अभिलेख संख्या–51/2024–25 अंचल अधिकारी, बगहा–2 के द्वारा उचित माध्यम से जिला कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है तथा भवन निर्माण हेतु भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव वर्तमान में प्रक्रियाधीन है और उक्त भूमि पर वर्तमान में कोई स्थायी अतिक्रमण नहीं है । इनका प्रश्न है कि कब तक अतिक्रमण मुक्त कराएंगे, तो अतिक्रमण है ही नहीं और माननीय सदस्य को लगता है कि अतिक्रमण है, तो हम अलग से भी जांच करा देते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, श्रीमती बिनिता मेहता ।

श्री सुरेंद्र प्रसाद : महोदय, माननीय मंत्री जी वहां पर भवन कब तक बनेगा ?

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : हमने बताया कि प्रक्रियाधीन है, उसकी प्रक्रिया जल्द से जल्द होगी ।

श्री सुरेंद्र प्रसाद : ठीक ।

टर्न–6 / पुलकित / 19.02.2026

अध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती बिनिता मेहता ।

तारांकित प्रश्न सं0–1569, श्रीमती बिनिता मेहता (क्षेत्र सं0–238, गोविन्दपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री राम कृपाल यादव, मंत्री : अस्वीकारात्मक है । नवादा जिले के समीपवर्ती जिले नालंदा के नूरसराय में एक उद्यान महाविद्यालय स्थापित है, जिसमें कृषि विषयों की पढ़ाई की सुविधा प्राप्त होती है ।

नवादा जिला में कृषि विज्ञान केन्द्र भी कार्यरत है, जहां किसानों को कृषि से संबंधित नवीनतम तकनीक के संबंध में जानकारी दी जाती है, जिससे कृषक लाभान्वित होते हैं तथा फसलों की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है ।

अतएव सरकार स्तर पर नवादा जिला में कृषि महाविद्यालय की स्थापना से संबंधित कोई भी प्रस्ताव संप्रति विचाराधीन नहीं है ।

श्रीमती बिनिता मेहता : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है । लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं कि हमारे विधानसभा के कौआकोल प्रखंड में शेखोदेवरा आश्रम है, जहां बहुत अच्छी किस्म के बीज और फलों की खेती होती है और वहीं इसी आश्रम में 1954 से 1970 तक लोकनायक जयप्रकाश वहां रहे थे, रणनीति तैयार किए थे, जो कांग्रेस सरकार को वहां से उखाड़ फेंके थे । वहीं पर किसान और छात्र प्रशिक्षण भी लेते हैं । अगर उस आश्रम के निकट कृषि महाविद्यालय बन जाता है, तो वहां न सिर्फ केवल किसान और छात्र को मजबूती मिलेगी, बल्कि वहां लोकनायक जयप्रकाश को सच्ची श्रद्धांजलि भी मिलेगी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री राम कृपाल यादव, मंत्री : महोदय, 2008 में कृषि रोड मैप के क्रियान्वयन के उपरांत कृषि शिक्षा एवं शोध प्रसार विषय पर विशेष ध्यान दिया गया है । वर्ष 2010 में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर की स्थापना की गई है । इसके उपरांत 2011 में भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय पूर्णिया, और वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय डुमरांव, बक्सर, वर्ष 2015 में डॉ0 कलाम कृषि महाविद्यालय किशनगंज, वर्ष 2021 में जैविक प्रावैधिकी महाविद्यालय सबौर, कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय भोजपुर, आरा, कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय मीठापुर, पटना, और वर्ष 2022 में वानिकी महाविद्यालय मुंगेर में स्थापना की गई है । इन विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्र के छात्र–छात्राओं को कृषि विषय पर पठन–पाठन पढ़ाया जा रहा है । सरकार बहुत गंभीर है और बड़े पैमाने पर यूनिवर्सिटी और विद्यालय का निर्माण किया गया है, तो अभी विचाराधीन नहीं है।

तारांकित प्रश्न सं0–1570, श्री बिजय सिंह (क्षेत्र सं0–68, बरारी)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना के अधिसूचना सं०–3057, दिनांक–04.10.2025 के आलोक में वृन्दावन कॉलोनी नगर परिषद, खगौल क्षेत्र के दायरे में अधिसूचित है । परन्तु अंतिम रूप से गठित वार्डों का जिला गजट में प्रकाशन नहीं हुआ है । योजना का क्रियान्वयन नगर निकाय के स्तर पर विचाराधीन नहीं है ।

श्री बिजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, जवाब प्राप्त है । लेकिन मेरा एक पूरक है और माननीय मंत्री जी का जवाब है कि 2025 के जिला गजट सूची में उसका प्रकाशन नहीं हुआ है । क्या माननीय मंत्री से यह कहना चाहेंगे, 2026 के जिला गजट की सूची में प्राथमिकता के आधार पर उस रोड नाला को चढ़ाया जाए ? या इस वर्ष, इस वित्तीय वर्ष में बनाने की इच्छा रखती है कि नहीं, यह हम जानना चाहेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को स्पष्ट उत्तर दिया है कि जिला गजट में प्रकाशन नहीं हुआ है । योजना का क्रियान्वयन नगर निकाय के स्तर पर भी विचाराधीन नहीं है । जब विचाराधीन नहीं है तो सरकार वहां से, जब विचार करके आएगा तब न कराया जाएगा ।

श्री बिजय सिंह : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार का लक्ष्य है हर गली नली का निर्माण होना है, तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि उस रोड में भी नली और गली का निर्माण हो ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, आएगा तो जरूर विचार सरकार करेगी ।

तारांकित प्रश्न सं0–1571, श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र सं0–20, चिरैया)

(लिखित उत्तर)

श्री संजय कुमार सिंह, मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक ।

पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत चिरैया प्रखंड के परेवा पंचायत में कुल वार्ड–15 है । जिसमें पंचायती राज विभाग द्वारा निर्मित सभी 16 अदद योजना का हस्तांतरण विभाग को अनुरक्षण हेतु किया गया है ।

छुटे हुए टोला में विभाग द्वारा 02 अदद नई योजना का निर्माण कार्य कराया जा रहा है । जिसका निर्माण कार्य मई, 2026 तक पूर्ण करा लिया जायेगा ।

वार्ड संख्या–04 :– वार्ड संख्या–04 में योजना से 143 घरों में जलापूर्ति की जाती है ।

वार्ड संख्या–05 :– वार्ड संख्या–05 में योजना से 122 घरों में जलापूर्ति की जा रही थी । रोड एवं नाला बनने के क्रम में लगभग 700 मीटर पाईप क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसमें 300 मी0 पाईप बिछाया गया है एवं शेष 400 मी0 पाईप बिछाने का कार्य प्रगति पर है । जिसे अगले 10 दिनों में पूर्ण कर लिया जायेगा ।

वार्ड संख्या–12 :–इस वार्ड में योजना से 67 घर आच्छादित है । पानी का निकासी व्यवस्था नहीं होने के कारण स्थानीय ग्रामीण द्वारा योजना बंद रखी गयी थी, जिसे आपसी सहमति उपरांत पुनः चालू करा दिया गया है।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, उत्तर जो मिला है संतोषजनक है । इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और कुछ राय भी देता हूं मंत्री जी को क्योंकि हम लोगों के एरिया में अभी से चापाकल सूखना शुरू हो गये हैं इसलिए थोड़ा सा मंत्री जी से आग्रह है कि वहां विशेष ध्यान देकर हमारे चिरैया विधानसभा में अभी बहुत से चापाकल सूख गए । थोड़ा सा यह नल जल जो है उस पर ध्यान देकर के सबको पूर्ण रूप से चालू रखें । इसके बाद अगर कहीं दिक्कत होती है तो नया भी चापाकल लगाया जाए, जिससे लोगों को पानी से सुख शांति मिले और टैंकर की भी व्यवस्था हम लोगों को करना पड़ता है । मार्च के बाद अपनी तरफ से टैंकर से पानी भिजवाते हैं जनता को पानी पीने के लिए । इस पर ध्यान देकर के मंत्री जी से आग्रह है कि विशेष ध्यान देकर के चिरैया विधानसभा में पानी की व्यवस्था करावे । इसके लिए मंत्री जी जो अभी जवाब दिए हैं उससे हम संतुष्ट हैं, इसके लिए मंत्री जी को बहुत–बहुत धन्यवाद ।

(व्यवधान)

<u>तारांकित प्रश्न सं0–1572, डॉ0 रामानन्द यादव (क्षेत्र सं0–185, फतुहा)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : उक्त योजना की निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है ।

डॉ0 रामानन्द यादव : अध्यक्ष महोदय, पूछता हूं, उत्तर प्राप्त है । महोदय आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कार्य प्रारंभ करने की समय सीमा बता दी जाए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, उक्त योजना की निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और निविदा जब पूर्ण हुई है तो कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ हो जाएगा । माननीय सदस्य पुराने हैं, अब तो अगले ही वित्तीय वर्ष में न शुरू होगा ? इस वित्तीय वर्ष में तो आप प्रश्न ही कर रहे हैं ।

तारांकित प्रश्न सं0–1573, श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र सं0–67, मनिहारी, (अ0ज0जा0))

(लिखित उत्तर)

श्री संजय कुमार सिंह, मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक ।

कटिहार जिला के मनसाही प्रखंड के चित्तौड़िया पंचायत के 13 वार्डो में 13 अदद वार्ड आधारित जलापूर्ति योजना है । जिसमें वार्ड संख्या–03, 04, 05, 08, 09, 10, 13 अर्थात कुल–07 वार्डों में नियमित रूप से जलापूर्ति दी जा रही है ।

06 अदद वार्ड (वार्ड संख्या–01, 02, 06, 07, 11, 12) में योजनाओं की पाईप लाईन ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा रोड चौड़ीकरण के दौरान क्षतिग्रस्त हो गयी है । उक्त वार्डों में आंशिक जलापूर्ति की जा रही है । सड़क चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण होने के उपरांत शीघ्र ही क्षतिग्रस्त पाईप लाईन का मरम्मति कार्य करा कर जलापूर्ति सुचारू रूप से बहाल कर दी जायेगी ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त हुआ है । मेरा प्रश्न था कि 13 वार्डों में से किसी में भी वाटर सप्लाई नहीं हो रहा है । और उत्तर आया है कि सात में जलापूर्ति हो रही है, छह में नहीं हो रही है । मैं इस उत्तर पर चुनौती देता हूं कि इस पर क्या कार्रवाई होगी ? इस तरह का भ्रामक उत्तर आया है । महोदय, दूसरी बात जो है वह यह है कि इन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 9 में सप्लाई हो रही है । लेकिन वार्ड नंबर 9 की जो जल मीनार बनी हुई थी, वह टूट गयी । जब सड़क बना रहे थे तब टूट गयी । और जो टूट गया है, उसका कंपनसेशन भी उसको नहीं मिला और यहां कहा जा रहा है कि उनको सप्लाई किया जा रहा है । यह कैसे संभव हो सकता है ? मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री संजय कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । कटिहार जिला के मनसाही प्रखंड के चित्तौड़िया पंचायत के 13 वार्डो में 13 अदद वार्ड आधारित जलापूर्ति योजना है । जिसमें से वार्ड संख्या–03, 04, 05, 08, 09, 10, 13 अर्थात् कुल–07 वार्डों में नियमित रूप से जलापूर्ति दी जा रही है ।

06 अदद वार्ड (वार्ड संख्या–01, 02, 06, 07, 11, 12) में योजनाओं की पाईप लाईन ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा रोड चौड़ीकरण के दौरान क्षतिग्रस्त हो गयी थी । उक्त वार्डों में आंशिक रूप से जलापूर्ति की जा रही है । क्षतिग्रस्त हुए पाइपलाइन एवं गृह जल योजना संयोजन को पुनर्स्थापन हेतु कार्य किया जा रहा है । एक सप्ताह में कार्य पूरा कराकर जलापूर्ति बहाल कर दी जाएगी ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : महोदय, यह सब उत्तर में है । मैं तो उत्तर के विरुद्ध बोल रहा था न कि उत्तर तो है ही । मैं तो उत्तर भी पढ़ रहा था । लेकिन आपका

कहना है कि सप्लाई हो रही है और मेरा कहना है कि सप्लाई नहीं हो रही है। इसकी जांच कौन कराएंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इस मामले की जांच करवा दीजिए ।

श्री संजय कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम पहले ही बता चुके हैं कि इसके लिए हम लोग दे चुके हैं और एक सप्ताह में अगर नहीं होगा तो निश्चित रूप से हम लोग जांच कराकर माननीय सदस्य को बता भी देंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0–1574, श्री सुजीत कुमार (क्षेत्र सं0–79, गौड़ाबौराम)
(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0–1575, श्री राहुल कुमार (क्षेत्र सं0–216, जहानाबाद)
(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : 1– आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । समाहर्त्ता, नालन्दा से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति यह है कि :–

मौजा–कोरावाँ, थाना नं0–95 के अंतर्गत खाता सं0–331, खेसरा सं0–1130, खतियानी रकवा–1.21 एकड़ गैर–मजरूआ सर्वसाधारण किस्म–भीठ एक है ।

2– स्वीकारात्मक ।

अंचल अधिकारी, इस्लामपुर से जमाबंदी रद्दीकरण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–9 एवं बिहार जमाबंदी रद्दीकरण नियमावली, 2012 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

3– उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री राहुल कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त हुआ है और जिस तरह का उत्तर है तो मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी तो बिहार में बदलाव लाना चाहते ही हैं, लेकिन कभी–कभी लगता है कि इनके ही लोग इन्हीं का पैर खींचना चाहते हैं । माननीय मंत्री जी से सिर्फ मैं इतना जानना चाहता हूं कि कोई समय सीमा तय कर देंगे कि इतने दिनों में मैं यह कार्रवाई कर लूंगा ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, अंगद का पैर कोई खींच सकता है ? जो मेरा मिशन और ध्येय है, परिणाम की बगैर चिंता किए हम अपना काम करते हैं और माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाते हैं कि जो मिशन है, जितने ही दिन रहेंगे, राजस्व भूमि सुधार विभाग में आपके अतिक्रमण के मामले मार्च के बाद शुरू करेंगे और उसका परिणाम भी देखेंगे । आपकी चिंता जायज है कि कभी अंचलाधिकारी हड़ताल में जाते हैं, कभी कर्मचारी को हड़ताल में ले जाते हैं। लेकिन...

(व्यवधान)

बोगो बाबू एक चीज ध्यान रखिएगा, दवा कड़वी होती है और दवा जब लोग ग्रहण करते हैं, खाते हैं, तो उसका असर जब पड़ता है, स्वस्थ होता है, तो सब स्वीकार करता है । यह स्वीकार है । अगर समय है तो बीमारी के इलाज के लिए धैर्य रखना पड़ेगा, हड़बड़ाने से तो नहीं चलेगा और हम एलोपैथिक और होम्योपैथिक के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, आयुर्वेदिक जो स्थायी समाधान कर देगा, इसके चक्कर में हैं ।

महोदय, अंचल अधिकारी, इस्लामपुर द्वारा मौजा–कोरावाँ, थाना नं0–95 के अंतर्गत खाता सं0–331, खेसरा सं0–1130, खतियानी रकवा–1.21 एकड़ गैर–मजरूआ सर्वसाधारण के जमाबंदी रद्दीकरण हेतु अभिलेख संख्या–2/2025–26 का प्रस्ताव अपर समाहर्ता, नालंदा को भेजा गया है । प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–9 एवं बिहार जमाबंदी रद्दीकरण नियमावली, 2012 के सुसंगत प्रावधानों के तहत सभी पक्षों को सुनकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी ।

श्री रूहेल रंजन : अध्यक्ष महोदय, यह हमारे विधानसभा क्षेत्र का भी मामला है, तो मैं....

अध्यक्ष : वह अलग है, अलग से लिख के दे दीजिएगा ।

श्री रूहेल रंजन : जी सर । लेकिन हमको सिर्फ एक ही सवाल छोटा सा पूछना था कि इनको 16 गरीब परिवारों को बेघर करने की इतनी क्या जल्दी है ?

अध्यक्ष : ठीक है, आप अलग से माननीय मंत्री जी को लिखकर के दे दीजिए ।

श्री रूहेल रंजन : महोदय, 16 परिवारों को बेघर करने की इनको क्या जल्दी है ? एक बार कम से कम मंत्री जी बतायें ।

अध्यक्ष : सरकार देखेगी इन बातों को ।

श्री रूहेल रंजन : सर, गरीब लोगों को रोड पर लाने की क्या जल्दी है ।

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हो उन्हें सदन पटल पर रख दिया जाएं । अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

श्री राहुल कुमार : महोदय, माननीय सदस्य ने बोला है तो मैं उनको बता देता हूं कि जल स्रोत पर सरकार का नियम है ।

अध्यक्ष : राहुल जी, अब बैठ जाइये । प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ ।

श्री राहुल कुमार : महोदय, माननीय सदस्य पूछे हैं तो मैं बता देना चाहता हूं कि....

अध्यक्ष : सरकार देख लेगी ।

श्री राहुल कुमार : महोदय, सरकार का नियम है वहां पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होगा । महोदय, अतिक्रमण है । माननीय सदस्य ने पूछा हैं तो मैं उनको बता देना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : सरकार देखेगी इस मामले को ।

(व्यवधान)

प्लीज, बैठ जाइये । शून्यकाल हो रहा है । माननीय सदस्या श्रीमती अनीता ।

टर्न–7 / अभिनीत / 19.02.2026

शून्यकाल

श्रीमती अनीता : माननीय अध्यक्ष महोदय, नवादा जिलांतर्गत दिनांक– 15.02.2026 को नवादा–पकरीबरावां स्टेट हाईवे पर ग्राम रेहुआ में संजना कुमारी, पिता– नवीन राजवंशी की अज्ञात वाहन से सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गयी है, जो काफी गरीब थी ।

अतः मृत संजना कुमारी के परिजनों को 4 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग करती हूं ।

श्रीमती सावित्री देवी : अध्यक्ष महोदय, जमुई जिलांतर्गत सभी प्रशिक्षण प्राप्त बेसिक ग्रेड के शिक्षकगण एवं नियोजित शिक्षकगण को वित्तीय उन्नयन / कालबद्ध प्रोन्नति के लाभ हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूं ।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चम्पारण जिलांतर्गत बकहा अनुमंडल में आधुनिक सरकारी बस स्टैंड के निर्माण के लिए मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं ।

श्री साम्रीद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार में स्थायी महिला कर्मियों को विशेष अवकाश मिलता है लेकिन संविदा और बेल्ट्रॉन की महिला कर्मी इससे वंचित हैं । जैविक जरूरतें सभी महिलाओं की एक समान होती है ।

अतः राज्य की हजारों महिला कर्मियों के हित में यह अवकाश लाभ देने की मांग करता हूं ।

श्री मो0 मुर्शिद आलम : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला के जोकीहाट प्रखंडान्तर्गत उदाहाट में स्थित ए.पी.एच.सी. को उत्क्रमित कर पी.एच.सी. किया जाय । उदाहाट छः पंचायतों का मुख्य बाजार है । आम नागरिकों को चिकित्सा के लिए परेशानी होती है । तत्काल छः बेड वाला अस्पताल हो जाने से समस्या का समाधान हो सकेगा ।

मैं उक्त ए.पी.एच.सी. को उत्क्रमित कर पी.एच.सी. बनाने की मांग करता हूं ।

श्री गुलाम सरवर : अध्यक्ष महोदय, पूर्णियां जिलांतर्गत डगरूआ प्रखंड एन0एच0–31 लसनपुर से भाया पतरिंगा होते हुए चॉपी गांव जाने वाली पक्की सड़क एवं डगरूआ बाजार से पतरिंगा जाने वाली सड़क की स्थिति अत्यंत जर्जर है । ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाई होती है ।

उक्त दोनों पथों का मरम्मति कार्य कराने की मांग करता हूं ।

श्रीमती देवंती यादव : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला के नरपतगंज थाना से जयनगर मोड़ तक लगभग 20 किलोमीटर की दूरी में कोई भी ओ.पी. / टी.ओ.पी. नहीं होने के

कारण सुरक्षा के मद्देनजर पिथौड़ा चौक के पास पुलिस चौकी की मैं सरकार से मांग करती हूं ।

श्री राजेश कुमार मंडल : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1933 में स्थापित मधुबनी जिलांतर्गत सकरी चीनी मिल 1997 से बंद है जो दरभंगा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र की सीमा पर है । बिहार सरकार 2026–27 के बजट में इसे पुनजीर्वित कर रही है ।

अतः मैं सकरी चीनी मिल शीघ्र खोलने की मांग करता हूं ।

श्री पप्पु कुमार वर्मा : अध्यक्ष महोदय, अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी जो एक समाजवादी नेता थे । उनके जन्मदिन 2 फरवरी को राजकीय अवकाश तथा अरवल जिले के कुर्था प्रखंड में उनके जन्मदिन पर 2, 3 तथा 4 फरवरी को मेला लगता है उसे राजकीय मेला घोषित करने की मांग करता हूं ।

श्री अभिषेक रंजन : अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चंपारण के चनपटिया थाना क्षेत्र स्थित सिकरहना नदी के नुनियावा टोला, पकडिहार घाट एवं मझौलिया के तिरहवां क्षेत्र में लगातार अवैध खनन हो रहा है । खनन पदाधिकारी एवं स्थानीय थाना की मिलीभगत है ।

मैं सरकार से जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग करता हूं ।

श्रीमती सोनम रानी : अध्यक्ष महोदय, सुपौल जिला के प्रखंड त्रिवेणीगंज अंतर्गत लतौना दक्षिण वार्ड नं0–08 नेपानी टोला निपनियां आजादी से पूर्व आबाद है लेकिन नदी पर पुल और सड़क नहीं है । लोग पगडंडी से आवागमन करते हैं ।

अतः सरकार से सड़क एवं पुल निर्माण की मांग करती हूं ।

श्री मो0 सरवर आलम : अध्यक्ष महोदय, बिहार में 01 सितम्बर, 2005 के बाद नियुक्त समस्त राज्यकर्मियों को नई पेंशन योजना (NPS) के दायरे में रखा गया है । कई अन्य राज्यों द्वारा इसे हटाकर पुरानी पेंशन योजना (OPS) को पुनः लागू कर दिया गया है ।

अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से बिहार में भी सभी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा हेतु पुरानी पेंशन योजना (OPS) अविलंब बहाल करने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : श्रीमती बिनिता मेहता जी, आपके 66 शब्द हैं, 50 शब्दों में करना था । आगे से ध्यान में रखिएगा । संक्षिप्त में पढ़ लीजिए ।

श्रीमती बिनिता मेहता : अध्यक्ष महोदय, नवादा जिला कृषि मामले में काफी पिछड़ा रहा है । कृषि विकास के लिए लगभग 1974–75 में महत्वाकांक्षी अपर सकरी जलाशय परियोजना की कल्पना की गयी थी । नवादा जिला के गोविन्दपुर प्रखंड अंतर्गत बकसोती ग्राम के पास बकसोती बराज बनाने की योजना थी परंतु बकसोती बराज का निर्माण नहीं हो पाने से यहां के किसान काफी मायूस हैं ।

अतः सरकार से अनुरोध करती हूं कि बकसोती बराज का निर्माण कराया जाय ।

श्री मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के सभी प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के दौरान मृत्यु होने के पश्चात उनकी पूरी चिकित्सीय फीस माफ की जाय । इससे फायदा यह होगा कि मरीज को बचाने की पूरी कोशिश की जायेगी और इन सबके बावजूद अगर मृत्यु होती है तो उसके परिजनों से अनावश्यक लूटपाट नहीं की जायेगी ।

श्रीमती छोटी कुमारी : अध्यक्ष महोदय, छपरा नगर निगम द्वारा कराए जा रहे सड़क एवं नाला निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की कमी से कई स्थानों पर टूट–फूट एवं गंदगी की समस्या बनी हुई है । कई पोखरों में भी गंदगी का ढेर लगा है ।

अतः पिछले पांच वर्षों के कार्यों की जांच करवाकर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाय ।

सुश्री मैथिली ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिलांतर्गत अलीनगर विधान सभा में धनश्यामपुर, अलीनगर, तारडीह प्रखंड अंतर्गत बीपीएल वृद्ध महिलाओं के नाम में आंशिक त्रुटि या शब्द छूट जाने के कारण वृद्ध पेंशन योजना एवं लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा योजना वर्षों से लंबित है । विशेष शिविर लगाकर पेंशन देने हेतु मैं सरकार से मांग करती हूं ।

टर्न–8 / हेमन्त / 19.02.2026

श्री भीषम प्रताप सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिवान जिला अंतर्गत मैरवा धाम के पास स्थापित 'हरिराम डिग्री महाविद्यालय' में चहारदीवारी नहीं होने के कारण यहां जुआरियों, नशेबाजों, स्मैकरों एवं असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। इसके चलते आये दिन अप्रिय घटनाएं होती रहती हैं।

अतः मैं उक्त महाविद्यालय में चहारदीवारी निर्माण की मांग करता हूं।

श्री शुभानंद मुकेश : अध्यक्ष महोदय, पुलिस द्वारा केवल प्राथमिकी के आधार पर चरित्र प्रमाणपत्र में प्रतिकूल टिप्पणी अंकित करना अनुचित है। भूमि विवाद या आपसी रंजिश में निर्दोष युवा नामजद हो जाते हैं। जब तक न्यायालन से दोष सिद्ध न हो, युवाओं को रोजगार हेतु चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करने की मांग करता हूं।

अध्यक्ष : श्री शंकर प्रसाद जी, आपका शून्यकाल 50 शब्दों से ज्यादा है, 50 शब्दों में पढ़िये।

श्री शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा सरैया प्रखंड के ग्राम पंचायत राज–चकना में मनरेगा योजनाओं की जांच में भारी अनियमितता पाई गयी थी। इस संबंध में कार्यालय के ज्ञापांक 540, दिनांक 28.02.2023 द्वारा दोषी पाए गए मुखिया, पंचायत रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक, कनीय अभियंता एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों पर वित्तीय दंड (वसूली) अधिरोपित किया गया था

आदेश में स्पष्ट निर्देश था कि वसूली की राशि एक सप्ताह के अंदर State Nodal Account (SNA) में जमा करायी जाय। परंतु अत्यंत खेद का विषय है कि आदेश के लंबे समय बीत जाने के बाद भी अब तक दोषी कर्मियों और प्रतिनिधियों से पूर्ण राशि की वसूली नहीं की जा सकी है।

अतः दोषियों से अविलंब दंड की संपूर्ण राशि वसूल की जाय एवं आदेश का अनुपालन न करने वाले लापरवाह पदाधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करने की मैं सरकार से यह मांग करता हूं।

श्री रोमित कुमार : अध्यक्ष महोदय, 1931 की जातीय जनगणना में 'भूमिहार ब्राह्मण' की आबादी लगभग 9 लाख दर्ज थी तथा राजस्व अभिलेखों में भी उनका उल्लेख है, फिर भी 2023 के 215 जातियों की सूची में उनका नाम नहीं है।

अतः बिहार सरकार इस विसंगति पर स्पष्टीकरण दे और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करे।

श्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिस अभिलेख में ''भूमिहार ब्राह्मण'' पहले से लिखा हुआ है, उसको कहीं–कोई संशोधित नहीं कर पायेगा।

श्री राकेश रंजन : अध्यक्ष महोदय, शाहपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत दामोदरपुर पंचायत का +2 उच्च विद्यालय 2025 के बाढ़ में ढह गया है। आज छात्रों को पढ़ाई के लिए कठिनाइयों का सामना करते हुए घर से दूर जाना पड़ता है।

मैं सरकार से दामोदरपुर पंचायत में +2 उच्च विद्यालय निर्माण शीघ्र कराने की मांग करता हूं।

श्रीमती ज्योति देवी : अध्यक्ष महोदय, गयाजी जिलान्तर्गत थाना–मोहनपुर का पंचायत–डेमा, लाडू, खरडीह, धरहरा, बगुला, सिन्दुआर, बुमुआर थाना क्षेत्र से दूर है। सुनसान होने एवं प्रशासनिक गतिविधियां कम होने से इस क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं तथा अवैध कार्य धड़ल्ले से होते हैं।

अतः पंचायत बुमुआर के सूजीरवाप में ओ0पी0 खोलने हेतु सदन से मांग करती हूं।

श्री बबलू कुमार : अध्यक्ष महोदय, खगड़िया के 'कैंब्रिज' कहे जाने वाले एकमात्र प्रमुख शैक्षणिक संस्थान कोशी कॉलेज के जर्जर भवनों के जीर्णोद्धार एवं वर्षों से अर्धनिर्मित महिला छात्रावास के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने की मांग सरकार से करता हूं।

श्री उदय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, गयाजी जिला अंतर्गत प्रखंड डोभी के पंचायत कुरमवां, ग्राम खरने स्थित फल्गु नदी के तट अवस्थित पंचवाहिनी मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है। यहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु पूजा अर्चना करने आते हैं।

अतः मैं सरकार से उक्त धार्मिक स्थल को विकसित करते हुए पर्यटन के रूप में दर्जा दिलाने की मांग करता हूं।

श्री ललन राम : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिला अन्तर्गत प्रखण्ड देव में पतलगंगा के पास मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा 2025 में किया गया था, पर अभी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है।

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत नारायणपुर प्रखंड के सिंहपुर पश्चिम पंचायत खगड़िया–जिला से सटे रहने के कारण कई किसानों की जमीन खगड़िया जिला में रहने से बाढ़ या अन्य आपदा से क्षति हुई फसल का मुआवजा सीमा विवाद के कारण नहीं मिल पाता है।

अतः सरकार से इस सीमा विवाद को सुलझाने की मांग करता हूं।

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड अंतर्गत विष्णुपुर पंचायत के विष्णुपुर गांव होकर अधवारा समूह की नदी बहती है। किसानों के खेतों में पानी जाए इसके लिए स्लूईस–गेट या पक्का बांध बनाने की आवश्यकता है।

अतः विष्णुपुर गांव के अधवारा नदी पर स्लुईस गेट निर्माण की मांग मैं सरकार से करती हूं।

श्री विमल राजवंशी : अध्यक्ष महोदय, रजौली विधानसभा के सिरदला प्रखंड अंतर्गत रामरायचक से कारीगिधी गांव के बीच तिलैया नदी पर पुल निर्माण अत्यंत आवश्यक है। सरकार शीघ्र स्वीकृति दे तथा वन विभाग से एन0ओ0सी0 जारी कराकर निर्माण कार्य प्रारंभ करे।

श्री महेश पासवान : अध्यक्ष महोदय, अगिआंव विधान सभा के अंतर्गत ग्राम कुसुम्ही, कचहरी महादलित टोला से नौवा नहर तक सड़क का निर्माण आजादी से अब तक हुआ ही नहीं। गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है। ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाई होती है।

अतः ग्रामीण विभाग के माध्यम से जनहित में शीघ्र सड़क बनवाने की मांग करता हूं।

श्री ललित नारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, किसानों से धान अधिप्राप्ति की समय सीमा तथा खरीद का लक्ष्य बढ़ाने एवं समय पर किसानों को धान का मूल्य दिलाने की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं।

श्री रोहित पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति का पद रिक्त होने के कारण शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्य प्रभावित है। सत्र विलंबित है और परीक्षाओं में देरी हो रही है।

अतः शीघ्र स्थायी कुलपति की नियुक्ति कर विश्वविद्यालय की व्यवस्था सुचारू की जाए।

श्री भरत बिन्द : अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिला अन्तर्गत भभुआ प्रखंड के अकोढ़ी गांव की नहर से ग्राम तमाढ़ी–तमाड़, मीरीयां के आगे दुर्गावती नदी तक नहर में गाद जमने के कारण सिंचाई नहीं हो पाती है।

अतः उक्त नहर की सफाई एवं मरम्मति की मांग सरकार से करता हूं।

टर्न–9 / संगीता / 19.02.2026

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिलान्तर्गत कर्मनाशा बाजार के समीप एन0एच0–19, सड़क के दोनों तरफ बिहार सरकार के द्वारा भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगी है, परंतु सड़क सिक्स लेन निर्माण कार्य होने से प्रतिमा गड्ढे में जीर्ण–शीर्ण हो गयी है प्रतिमा की ऊंचाई बढ़ाने एवं सौन्दर्यीकरण करने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचना ली जाएगी और ध्यानाकर्षण के उपरान्त समय बचने पर, अगर सदन की सहमति हो तो शेष शून्यकाल की सूचना ली जाएगी।

अब ध्यानाकर्षण सूचना लिए जायेंगे । माननीय सदस्य श्री आलोक कुमार मेहता सूचना पढ़ें ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री आलोक कुमार मेहता, भाई वीरेन्द्र एवं अन्य तीन सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (सूचना प्रावैधिकी विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2025 में मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के अधीन प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक डिजिटल लाइब्रेरी को स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । इस योजना का लाभ राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं, छात्र–छात्राओं को प्राप्त होता है । उपरोक्त योजना के स्वरूप को अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब, दलित, पिछड़ा छात्र–छात्रा इसके लाभ से वंचित हैं ।

अतः गांवों के छात्र–छात्राओं के हित में उपरोक्त योजना को शीघ्र लागू करने के लिए सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री :

सुश्री श्रेयसी सिंह, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–1593, दिनांक–07.08.2025 के द्वारा राज्य में विद्यार्थियों की उन्नत शिक्षा के लिए डिजिटल तकनीक के माध्यम से लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना, एम0एम0डी0एल0वाई0 की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके माध्यम से राज्य

के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में डिजिटल लाइब्रेरी केन्द्र स्थापित कर विद्यार्थियों को डिजिटल माध्यम से अध्ययन की सुविधा प्रदान की जाएगी । मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के तहत एक राज्य स्तरीय, एक क्षेत्र स्तरीय की लाइब्रेरी एवं राज्य अंतर्गत सभी 243 विधान सभा में एक–एक लाइब्रेरी केन्द्र की स्थापना की जानी है । प्रत्येक डिजिटल लाइब्रेरी केन्द्र में निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध होगीं :–

विद्युत और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी की उपलब्धता, न्यूनतम 300 वर्गफुट का क्षेत्र, प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में स्थित लाइब्रेरी केन्द्र में 10 कम्प्यूटर, राज्य स्तरीय मॉडल लाइब्रेरी केन्द्र में 60 तथा क्षेत्रीय मॉडल लाइब्रेरी केन्द्र में 50 कम्प्यूटर एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था की जानी है । मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी के लिए मैन–पॉवर एवं कार्यालय उपकरण उपलब्ध कराने हेतु एजेंसी का चयन किया जा चुका है । राज्य स्तरीय लाइब्रेरी की स्थापना, बिस्कोमान भवन, पटना में किया जा चुका है, जो अभी वर्तमान में संचालित है । उक्त में अतिरिक्त 85 लाइब्रेरी हेतु स्थान का चयन किया गया है, शेष 158 लाइब्रेरी हेतु स्थल चयन का कार्य प्रक्रियाधीन है । मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना अंतर्गत 85 लाइब्रेरी की स्थापना हेतु प्रखंड स्थित, प्रखंड संसाधन केंद्र, जो बी0आर0सी0 के नाम से जाना जाता है, उसका चयन किया गया है । जिससे इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के युवा–युवती, छात्र–छात्राओं को प्राप्त होगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से ये ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र–छात्राओं को आधुनिक ढंग से पढ़ने–लिखने में सुविधा होगी, इस योजना के माध्यम से लेकिन इसकी समयसीमा क्या होगी ? योजना का आकार आपने बताया लेकिन क्या किसी विधान सभा में अभी तक शुरू की गई है ? मैं मांग करता हूं कि गांव के गरीब छात्र–छात्राओं के हित को ध्यान में रखते हुए यह सरकार इस योजना को शीघ्र कार्यान्वित करे तथा उसकी गुणवत्ता और पारदर्शिता दोनों को सुनिश्चित करे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

सुश्री श्रेयसी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन के सभी सदस्यों को बताना चाहूंगी कि जहां 85 प्रखंड स्तरीय जगह को चयनित किया गया है, वहां निश्चित रूप से इस चलंत वित्तीय वर्ष में ये लाइब्रेरी को शुरू करा दिया जाएगा, क्योंकि इसमें चुनाव का समय बीच में आ गया था तो थोड़ा समय जरूर लग रहा है लेकिन मेरा पूरा प्रयास है कि चलंत वित्तीय वर्ष में सभी जगह पर ये लाइब्रेरी शुरू कर दी जाए । साथ ही साथ, पटना में जो मॉडल लाइब्रेरी बनी है, वह वर्तमान में संचालित है और जहां तक माननीय सदस्य का

जो कंसर्न है कि इसको जल्द से जल्द खोला जाए तो वित्तीय वर्ष में हमलोग कर लेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रमोद कुमार ।

श्री भाई वीरेन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : पूछ लीजिए ।

श्री भाई वीरेन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या माननीय विधायकों का सलाह लेकर, जहां ई–लाइब्रेरी खोलना है, क्या माननीय विधायकों से भी सलाह ली जाएगी ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

सुश्री श्रेयसी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय सदस्य चाहते हैं अपना सुझाव देना तो निश्चित रूप से मैं दिखलवा लुंगी लेकिन यदि आपका क्षेत्र या किसी भी माननीय सदस्य के क्षेत्र में जो 85 जगह की मैं बात कर रही हूं, यदि वहां पर कम्प्यूटर और मैन–पॉवर सब चला गया है और वह तुरंत ही चलंत होने वाला लाइब्रेरी है तो मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि उसका जगह अगर चेंज करेंगे तो समय व्यर्थ जाएगा ।

श्री भाई वीरेन्द्र : शेष जगहों का, विधान सभा का मैं चाहूंगा कि उसका भी...

सुश्री श्रेयसी सिंह, मंत्री : शेष जितने 158 की बात हो रही है मैं माननीय सदस्य से सुझाव लेकर आगे बढ़ूंगी ।

अध्यक्ष : श्री प्रमोद कुमार सूचना पढ़ें ।

सर्वश्री प्रमोद कुमार, सचीन्द्र प्रसाद सिंह एवं अन्य अठाईस सभासदों से प्राप्त <u>ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (योजना एवं विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य ।</u>

श्री प्रमोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनाओं की लागत में लगातार वृद्धि जैसे बढ़ते हुए सीमेन्ट, लोहा, बालू एवं मजदूरी में व्यापक वृद्धि होने के कारण माननीय मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की जो 04 करोड़ रुपये की राशि है, उसे 08 करोड़ रुपये करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री हैं नहीं, समय ले लीजिए ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उपमुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति, शांति ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उपमुख्यमंत्री : माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया और सभी सदस्यों का इसपर जिस तरह से समर्थन दिखाई पड़ा तो मामला तो गंभीर है

महोदय, तो इसपर वृहत रूप से सरकार चिंतन करेगी, इसको समय चाहिए महोदय । समय लिया जाता है ।

अध्यक्ष : श्रीमती ज्योति देवी ।

(व्यवधान)

सरकार ने कहा है वृहत तौर पर समीक्षा की जाएगी ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गए)

(व्यवधान)

माननीय मंत्री जी ने कहा है वृहत विचार किया जाएगा इस विषय पर ।

(व्यवधान)

बैठ जाइए, बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उपमुख्यमंत्री : महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइए, कृपया बैठ जाएं ।

(व्यवधान)

सरकार का जवाब सुन लीजिए, सरकार का जवाब सुन लीजिए बबलू बाबू।

(इस अवसर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर बैठ गए)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उपमुख्यमंत्री : महोदय, माननीय सदस्य की भावना का हम सम्मान करते हैं और माननीय मंत्री, योजना विकास विभाग, जो वित्त मंत्री भी हैं तो एक बार माननीय वित्त मंत्री योजना विकास मंत्री जी के मुख से कोई भी घोषणा सदन को भी गौरवान्वित करेगा और माननीय सदस्य को भी उनके भाव को...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अभी स्थगित कर देते हैं, अभी स्थगित कर देते हैं...

(व्यवधान)

प्रमोद जी, अभी स्थगित कर देते हैं । अभी स्थगित कर देते हैं, जब सदन में...

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, प्रमोद बाबू इस क्वेश्चन को स्थगित किया जाता है । योजना एवं विकास विभाग के मंत्री जब रहेंगे, जवाब दिलवायेंगे ।

(व्यवधान)

माननीय मंत्री विधान परिषद में हैं और माननीय उपमुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि निश्चित तौर पर सरकार इसको देखेगी और मंत्री जी जवाब देंगे ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, इसको स्थगित कर दिया जाए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उपमुख्यमंत्री : आसन पर सबको विश्वास है और जब सारे सदस्य सहमत हैं तो समय दिया जाए महोदय । माननीय वित्त मंत्री–सह–योजना विकास मंत्री निर्णय करेंगे ।

अध्यक्ष : बिल्कुल । श्रीमती ज्योति देवी ।

(व्यवधान)

हां, बिल्कुल, स्थगित किया गया है, अभी स्थगित कर दिया गया है । ज्योति देवी जी पढ़िए सूचना को ।

टर्न–10 / यानपति / 19.02.2026

श्रीमती ज्योति देवी, श्री रोमित कुमार एवं अन्य छः सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्रीमती ज्योति देवी : अध्यक्ष महोदय, राज्य के तकनीकी संस्थानों में 'सात निश्चय' के तहत दशकों से कार्यरत अतिथि शिक्षक बिहार के मूल निवासी हैं और आरक्षण नियमों के तहत नियुक्त हुए हैं । इन्हीं शिक्षकों के बल पर संस्थानों को AICTE से संबद्धता प्राप्त होती रही है । माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इन्हें 'गेस्ट से होस्ट' बनाने का आश्वासन दिया गया था, किंतु इसके विपरीत विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग द्वारा हाल ही में अधिकांश योग्य शिक्षकों को कार्यमुक्त कर दिया गया है । कई कॉलेजों में एम–टेक की पढ़ाई शुरू हुई है तब अनुभवी शिक्षकों को हटाना अतार्किक है अन्य राज्यों और बिहार के ही विश्वविद्यालयों / स्कूलों में अतिथि शिक्षकों को 60–65 वर्षों तक समायोजित किया जा रहा है तो तकनीकी शिक्षकों के साथ यह भेदभाव क्यों ? कई शिक्षकों की उम्र अब प्रतियोगी परीक्षाओं के योग्य नहीं बची है । 2010 से अनवरत सेवा देने वाले इन स्किल्ड शिक्षकों को हटाना उनके साथ अमानवीय और अन्यायपूर्ण व्यवहार है ।

अतएव वर्ष 2010 से 2024 तक 500 से अधिक अतिथि शिक्षक अपनी सेवाएँ दे चुके हैं, इन शिक्षकों को 65 वर्ष तक समायोजन कर पुनः कार्य अनुमति प्रदान करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराती हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, उत्तर दे दीजिए ।

(व्यवधान)

प्रमोद बाबू, आपका विषय आयेगा आगे, चिंता मत कीजिए ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राजकीय तकनीकी संस्थानों में नियमित शिक्षकों के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की सेवा लिये जाने हेतु विभागीय संकल्प सं0–3016, दिनांक–02.12.2021, पत्रांक–897, दिनांक–31.03.2022, आदेश सं0–3408, दिनांक–07.08.2024 एवं आदेश सं0–3409, दिनांक–07.08.2024 द्वारा प्रावधान किया गया है । तदालोक में अतिथि शिक्षकों की सेवा ली गई है । राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पोलिटेक्निक संस्थानों में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए0आई0सी0टी0ई0), द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली, 2020 एवं बिहार पोलिटेक्निक शिक्षा सेवा नियमावली, 2020 गठित है एवं राज्य के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के तकनीकी संस्थानों/महाविद्यालयों में आवश्यकता आधारित पदों को सृजित किया गया है । पूर्व से रिक्त एवं ऐसे सृजित पदों को नियमित नियुक्ति द्वारा भरा जाना है । अतः उक्त नियमावली के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के माध्यम से कई पदों पर नियमित नियुक्ति की गई है । नियमित नियुक्ति किये जाने के फलस्वरूप ही अतिथि शिक्षकों की सेवा निरंतर रखा जाना प्रभावित हुआ है ।

यथाउल्लिखित नियमावली के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के माध्यम से नियमित नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । अतएव अतिथि शिक्षकों को 65 वर्ष की उम्र तक समायोजन किया जाना नियमानुकूल नहीं है । यहां पर हम, संकल्प जो निकला था महोदय, उसमें स्पष्ट रूप से उल्लिखित है, जब उन्हें संविदा पर रखा गया कि संविदा या नियुक्तियां लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियमित नियुक्तियों के लिए अनुशंसा देने के विलंब के कारण उस समय तक की जाती है जब तक नियमित नियुक्तियां न हो जायं । इस वजह से इस संकल्प पर जो नियम था उसी के आधार पर कार्रवाई की गई है । धन्यवाद महोदय ।

श्रीमती ज्योति देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार के आंकड़े बताते हैं कि अतिथि शिक्षक केवल शिक्षण कार्य नहीं कर रहे थे बल्कि चुनाव ड्यूटी, परीक्षा मूल्यांकन और विश्वविद्यालय के अन्य प्रशासनिक कार्यों में भी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे । उनकी सेवा समाप्ति से उक्त पद पर रिक्तियां भरने के लिए सरकार पुनः, हम यह कहना चाह रहे हैं कि नया करना चाहते हैं क्योंकि अगर इनको नहीं लिया जाता है तो हम यह कहना चाहते हैं कि पिछले वर्ष जो बहाली हुई है जिसमें शिक्षकों को पांच–पांच नंबर दिया गया है जो पूरी तरह से अवैध है और अतिथि शिक्षकों को इसमें अनदेखा किया गया है । मामला न्यायालय में भी लंबित है महोदय । यहां तक कि इनको ऑफर लेटर में भी लिखा हुआ है कि इनको कभी भी हटाया

जा सकता है । तो महोदय, आपसे मैं विनम्र आग्रह के साथ कहना चाहती हूं कि हमारी सरकार संवेदनशील है, लोगों को रोजगार देने की बात करती है, इतने सारे काम हमलोग कर रहे हैं, इन अतिथि शिक्षकों की उम्र भी नहीं है किसी परीक्षा में यह बैठ सकते हैं सेवा देते सरकारी काम में, तो यह इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ महोदय, मैं आपके आसन से विनम्र आग्रह करना चाहती हूं कि इन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर के इसको खाली स्कूलों में भर्ती किया जाय, समायोजित कर इन्हें बहाल किया जाय ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये, ज्योति जी ।

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, अतिथि शिक्षकों का भविष्य बहुत गंभीर स्थिति में है और समायोजन कर दिया जाता है क्योंकि इनकी उम्र जो है बीत चुकी है और इनके परिवार के लोग भूखे मरने पर आ गए हैं इसलिए सदन से आग्रह है कि अतिथि शिक्षकों के बारे में सदन सोचे ।

अध्यक्ष : अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

अच्छा पूछ लीजिए, रोमित जी ।

श्री रोमित कुमार : अध्यक्ष महोदय, पटना उच्च न्यायालय ने संदीप कुमार झा मामले में स्पष्ट किया था कि अतिथि शिक्षक तथा संविदा शिक्षक समान कर्तव्यों का पालन करते हैं यदि हां तो संविदा शिक्षकों को वेटेज का लाभ देना और अतिथि शिक्षकों को कार्यमुक्त करना भारतीय संविधान अनुच्छेद 14, जहां समानता का अधिकार है उसका उल्लंघन क्यों किया गया है । दूसरा प्रश्न है विनोद कुमार बनाम भारत संघ 2024 मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि औपचारिकताओं का उपयोग कर उन कर्मचारियों को नियमित करने से रोकने के लिए नहीं किया जाना चाहिए जिन्होंने लंबे समय तक सेवा दी है । क्या सरकार इस नियम के आलोक में अपनी 31 मार्च, 2024 की अधिसूचना को वापस लेने का विचार कर रही है और तीसरा एक और है कि क्या विभाग ने ए0आई0सी0टी0ई0 रेगुलेशन 2019 के नियम 2.25 एफ के खिलाफ केंद्र सरकार या ए0आई0सी0टी0ई0 को कोई पत्राचार किया है ताकि बिहार के उन शिक्षकों के अनुभव को बचाया जा सके जिन्होंने राज्य के तकनीकी संस्थान को शून्य से शिखर तक पहुंचाया । एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि ए0आई0सी0टी0ई0 में कुछ नियम बाधा उत्पन्न करते हैं इनको रेगुलाइज करने में, लेकिन सरकार के पास कार्यकारी शक्ति है, एक्सक्यूटिव पावर है और नीति निर्णय की स्वायत्ता उनको इन शिक्षकों को बचाने की अनुमति देती है। हाई कमीशन, हाई लेवल कमेटी बनाई जाय और उनको हरियाणा की तर्ज पर...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री रोमित कुमार : हरियाणा में भी किया गया था और हरियाणा की तर्ज पर उनकी नियुक्ति होनी चाहिए ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो संकल्प जिसका जिक्र अभी हमने किया, सदन को उसके बारे में कहा उससे स्पष्ट है और साथ ही साथ जहां तक नियुक्तियों का प्रश्न है तो यूनिवर्सिटी कमीशन के द्वारा नियमित नियुक्तियां की जा रही हैं जिसकी वजह से करीब–करीब पौने तीन–तीन हजार नियुक्यिां की गई हैं जिसमें से इंजीनियरिंग कॉलेजेज वगैरह के लिए भी नियुक्यिां की गई हैं । जहां तक माननीय सदस्य ने दोनों जो कोर्ट के आदेश को पढ़ा है तो उसको पुनः हम उसका अवलोकन कर लेंगे, लेकिन जहां तक हमें मालूम है कि कोर्ट का कोई ऐसा एक्सप्रेस ऑर्डर नहीं था कि अमुक–अमुक केस में आप कर लें फिर भी हम जो कोर्ट के मैटर्स हैं उनको पुनः अवलोकन कर लेंगे और नियमानुसार कार्रवाई करेंगे । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

टर्न–11 / मुकुल / 19.02.2026

अध्यक्ष : अब शून्यकाल लिये जायेंगे । श्री राम सिंह । माननीय सदस्या, सरकार ने कहा है ।

श्रीमती ज्योति देवी : अध्यक्ष महोदय, हम यह कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने कहा है कि कोर्ट का यह देख लेंगे कि क्या कानून है नहीं है, तो हम यह कहना चाह रहे हैं कि नई पॉलिसी लाकर के उनकी बहाली तो की ही जा सकती है, क्योंकि यह कानून का सदन है यहां कानून बनाये जाते हैं, हम सब कानून बनाने वाले हैं । कोई भूखा रोड पर मर रहा है, उसके लिए क्या कोर्ट का इंतजार करेंगे या सदन इसका जवाब देगी । इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से और अपनी सरकार से यह कहना चाहती हूं और भूखे को भोजन देने के लिए है, किसी का रोजगार छीनने के लिए नहीं हैं । इसलिए मैं आपसे विनम्र आग्रह के साथ कहना चाहती हूं कि इन्हें समायोजित कर इन्हें काम दिया जाए । बहुत–बहुत धन्यवाद महोदय।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या के आग्रह पर सरकार विचार करे ।

अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

<u>शेष शून्यकाल की सूचनाएं</u>

श्री राम सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, बगहा विधान सभा अन्तर्गत रतवल चौक से चखनी होते हुए एन0एच0–727 रोड तक चौड़ीकरण के साथ मजबूतीकरण कराने हेतु सरकार से मांग करता हूं ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, गयाजी जिला के गुरूआ, परैया प्रखण्डों में अवैध बालू खनन ओवरलोड वाहनों द्वारा ग्रामीण सड़कों को क्षतिग्रस्त कर गांव के वातावरण को प्रदूषित किया जा रहा है । प्रदूषण से बुजुर्ग, बच्चों,

आमजन के स्वास्थ्य, फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । इस संबंध में सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत रफीगंज प्रखंड में गरवा मोड़ से मिसिर बिगहा देवी मंदिर तक स्थित पथ जिसकी लम्बाई 1. 82 कि0मी0 है, उक्त पथ का डी0पी0आर0 बनने के बावजूद प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान नहीं करने के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सकता है । अतएव उक्त पथ का निर्माण कार्य प्रारंभ करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दिलाने हेतु कार्रवाई की जाए ।

अध्यक्ष : श्री अजय कुमार जी आप शून्यकाल की सूचना 50 शब्द से अधिक है, आगे से आप इसका ध्यान रखियेगा । इन्हें संक्षेप में पढ़िए ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, गयाजी जिलान्तर्गत टिकारी प्रखंड के टिकारी–केसपा पथ को एस0एच0–69 से जोड़ने वाली अति महत्वपूर्ण बलियारी–चितौरवर पथ में ग्राम–ईटहोरी एवं मालडा के बीच रतनी–फरीदपुर कैनाल पर बना हुआ पुल क्षतिग्रस्त हो गया है एवं आकार में भी छोटा है । आए दिन उक्त पुल पर आवागमन करने वाले यात्री एवं वाहन दुर्घटना के शिकार होते रहते हैं । अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि जनहित में उपरोक्त पुल का निर्माण अतिशीघ्र करवाया जाए ।

अध्यक्ष : श्री बैद्यनाथ प्रसाद जी, आपकी भी शून्यकाल की सूचना 50 शब्द से अधिक है, आप भी आगे से ध्यान रखियेगा ।

श्री बैद्यनाथ प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला का बगहीधाम संत शिरोमणि तपस्वी नरायण दास जी की तपोभूमि है । हिन्दीभाषी राज्यों खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा सहित नेपाल से काफी संख्या में भक्तों का आना–जाना इस धाम में सालोंभर होता है । आस्था के इस केन्द्र को बारहमासी सड़क सम्पर्कता उपलब्ध कराने हेतु मनीयारी से रणजीतपुर होकर बगहीधाम तक 5.5 मीटर चौड़ाई वाली पक्की सड़क निर्माण सरकार कराये ।

श्री इन्द्रदेव सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिवान जिलान्तर्गत प्रखंड पचरूखी के भटवलिय, उखई, शंभोपुर, पिपरा, सुरवाला, भरतपुरा एवं सहलौर पंचायतों के खेतों में बराबर जल–जमाव की स्थिति बनी रहती है, जिससे खेती नहीं हो पा रही है । किसान भुखमरी के कगार पर हैं । अतः खेतों से जल निकासी कराने की मांग करता हूं ।

श्री कृष्णनंदन पासवान : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण, तुरकौलिया प्रखण्ड, शंकर सरैया पंचायत को बिना सरकारी सहायता पूर्ण साक्षर बनाने वाले पूर्व मुखिया एवं विधान पार्षद स्व0 रामजी प्रसाद शर्मा के अथक प्रयास से मध्य विद्यालय, फतेह टोला स्थापित हुआ । मैं सृजनकर्ता, शिक्षा प्रेमी स्व0 रामजी

प्रसाद शर्मा जी के नाम से विद्यालय का नामकरण कराने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री रणविजय साहू : माननीय अध्यक्ष महोदय, महान स्वतंत्रता सेनानी, निषाद समाज के प्रथम बिहार विधान परिषद सदस्य रहे, समस्तीपुर जिला के मोरवा प्रखंड अंतर्गत गुनाई बसही निवासी डॉ0 मुक्तेश्वर सिन्हा जी के सामाजिक, राजनैतिक योगदान को देखते हुए, ताजपुर प्रखंड के हॉस्पिटल चौक पर आदमकद प्रतिमा स्थापित करने की मांग करता हूं ।

श्री अजय कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के दलसिंहसराय प्रखंड अंतर्गत, पंचायत–बम्बईया हरलाल के वार्ड संख्या–02 स्थित रामटोल (आबादी–250) से आर0ई0ओ0 रोड तक सम्पर्क पथ (लम्बाई–1000 फीट) का निर्माण नहीं होने से लोगों को आवागमन में कठिनाई हो रही है । मैं सरकार से उक्त सम्पर्क पथ का निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री पुरन लाल टुडू : अध्यक्ष महोदय, बांका जिला के कटोरिया प्रखण्ड में कोल्ड स्टोरेज नहीं होने से किसान अपनी उपज (टमाटर आलू प्याज) को संधारित नहीं कर पाते हैं, जिससे किसानों का बहुत नुकसान होता है, कटोरिया प्रखण्ड में किसानों के हित के लिए एक कोल्ड स्टोरेज बनाने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री कलाधर प्रसाद मंडल : अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला के रूपौली विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत क्रमशः भवानीपुर, रूपौली, बिरौली, टीकापट्टी एवं बड़हरा कोठी स्थित बड़े बाजार में डीलक्स शौचालय नहीं रहने के कारण व्यवसायी, महिलाएं, बच्चे एवं आम जनता काफी कठिनाई झेलते हैं । अतः उक्त बाजारों में डीलक्स शौचालय की शीघ्र व्यवस्था कराने की मांग करता हूं।

श्री सदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, पटना जिलान्तर्गत पालीगंज प्रखंड के नदहरी कोदहरी पंचायत के साहाचक गांव में गंगहर नदी पर पुल नहीं होने से आसपास के ग्रामीणों को नजदीकी बाजार जहानाबाद आने–जाने में भारी कठिनाइयों और जोखिमों का सामना करना पड़ता है । अतः साहाचक गांव में गंगहर नदी पर पुल निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिला के कुरसेला बाजार में आगजनी से लगभग 400 दुकानें जल गयी हैं । प्रति दुकान 2 लाख से 50 लाख का नुकसान हुआ है, इससे दुकानदार महाजनी कर्ज में डूब गए हैं । इसको विशेष आपदा घोषित कर, दुकानदारों को समुचित मुआवजे की मांग करता हूं ।

श्री मुरारी पासवान : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिले के पीरपैंती प्रखंड अंतर्गत हरिकोल ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन हेतु खाता सं0–127, खेसरा–316, रकबा–2 एकड़ 27 डिसमील भूमि उपलब्ध है । तथापि, अवैध राशि की मांग

के कारण निर्माण कार्य बाधित है । मैं उक्त भवन निर्माण कराने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, उजियारपुर प्रखंड के किसानों की आय बढ़ाने, युवाओं को रोजगार दिलाने और प्रखंड की आर्थिक उन्नति के लिए देवखाल चौड़ में उपलब्ध सरकारी भूमि पर एक औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री राज कुमार राय : अध्यक्ष महोदय, राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल में डायलिसिस मशीन उपलब्ध है । लेकिन डायलिसिस टेक्निशियन की नियुक्ति नहीं होने के कारण स्टाफ नर्स के द्वारा ही डायलिसिस करवाया जा रहा है । अतः जनहित में अतिशीघ्र बेरोजगार डायलिसिस टेक्निशियन की नियुक्ति करवाने हेतु सरकार से मांग करता हूं ।

श्री नंद किशोर राम : अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखण्ड गौनाहा के मरजादपुर मरजदी से गौनाहा–नरकटियागंज मुख्य मार्ग के मेघौली चौक तक तथा जमुनिया पंचायत के गेन्हरिया बुढ़िया माई स्थान से ग्राम भवानीपुर तक जनहित में सड़क निर्माण कराने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं ।

टर्न–12 / सुरज / 19.02.2026

श्री आसिफ अहमद : अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिलान्तर्गत पी0एम0 श्री योजना अंतर्गत चयनित राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय, हुसैनपुर, रहिका में अभी तक शैक्षणिक भवन निर्माण नहीं होने से उसका असर बच्चों के पठन–पाठन पर पड़ रहा है ।

अतः विद्यालय में शैक्षणिक भवन का निर्माण शुरू कराने की मांग करता हूं ।

श्री अमित कुमार : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी के पचनौर–ननौरा घाट पर पुल के अभाव में वर्षा ऋतु में हजारों लोग टापू में कैद हो जाते हैं । सरकार से आग्रह है कि भौतिक सत्यापन कराकर, इसे आगामी कार्य योजना में शामिल करे ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों को पूर्व से देय नियत मासिक भत्ता में 1.5 गुणा वृद्धि के तर्ज पर जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य तथा नगर निकाय के वार्ड पार्षद सदस्य के नियत मासिक भत्ते में सम्मानजनक वृद्धि करने की मांग मैं सरकार से करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, इस विषय का ध्यानाकर्षण भी आया था, सरकार संज्ञान ले ।

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, नवलपुर थाना अंतर्गत पांच पंचायत है । जिनका केन्द्र नवलपुर बाजार है । इसके लिये प्राप्त भूमि खाता सं0–534, 509, 571, 563, 256, 538, 1929, 327, 3155, 508 खेसरा–1979, 1693, 1697, 1703, 2150,

1701 एवं रकबा– 01 एकड़ 32 डी0 है । सदन के माध्यम से आग्रह है उक्त भूखंड पर भवन का निर्माण हो ।

श्री नागेन्द्र चन्द्रवंशी : अध्यक्ष महोदय, नोखा विधान सभा अंतर्गत प्रखंड नासरीगंज के प्राथमिक विद्यालय, भरकोल में 50 वर्ष पूर्व मात्र 02 कमरा ही बना था । दोनों कमरों की स्थिति जर्जर है । विद्यालय तक पक्की सड़क भी नहीं है ।

अतः प्राथमिक विद्यालय, भरकोल में समुचित कमरा तथा पक्की सड़क बनाने की मांग करता हूं ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह : अध्यक्ष महोदय, डेहरी विधान सभा के अंतर्गत अकोढ़ीगोला एवं डेहरी डालमियानगर शहर में व्यवस्थित वेंडर जोन न होने के कारण दुकानदार फुटपाथ पर दुकान लगाते हैं, जिससे आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है ।

अतः अकोढ़ीगोला एवं डेहरी डालमियानगर शहर में अविलंब वेंडर जोन बनावाने की मांग मैं सरकार से करता हूं ।

श्रीमती विभा देवी : महोदय, नवादा जिला...

अध्यक्ष : माइक पर बोलिये ।

श्रीमती विभा देवी : महोदय, नवादा जिला में ग्राम–घंघौली है, वहां पर जमीन जो है किसी का उस पर अवैध कब्जा है । उस पर माननीय मंत्री जी बढ़िया से निरीक्षण करेंगे...

अध्यक्ष : आप लिखकर दे दीजियेगा माननीय मंत्री जी को ।

अब सभा की कार्यवाही 02.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित की जाती है ।

टर्न–13 / धिरेन्द्र / 19.02.2026

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।
अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

वित्तीय कार्य

माननीय सदस्यगण, आज शिक्षा विभाग के अनुदान की मांग पर वाद–विवाद तथा सरकार के उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है, इसी समय में से सरकार के उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगाः–

भारतीय जनता पार्टी	– 66 मिनट
जनता दल यूनाइटेड	– 63 मिनट
राष्ट्रीय जनता दल	– 18 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)	– 14 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	– 04 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	– 04 मिनट
ए0आई0एम0आई0एम0	– 04 मिनट
राष्ट्रीय लोक मोर्चा	– 03 मिनट
सी0पी0आई0 (एम॰एल॰)(एल॰)	– 01 मिनट
सी0पी0आई0 (एम॰)	– 01 मिनट
बहुजन समाजवादी पार्टी	– 01 मिनट
इंडियन इंक्लूसिव पार्टी	– 01 मिनट

.....

कुल = 180 मिनट

.....

माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग । अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''शिक्षा विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 60204,60,95,000 / – (साठ हजार दो सौ चार करोड़ साठ लाख पंचानवे हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : इस मांग पर माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार, श्री आलोक कुमार मेहता, श्री मो॰ कमरूल होदा, श्री अखतरूल ईमान एवं श्री सतीश कुमार सिंह यादव जी से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । ये सभी व्यापक हैं, जिन पर सभी माननीय सदस्य विचार–विमर्श कर सकते हैं । माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार जी का प्रस्ताव प्रथम है ।

अतएव, माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री राहुल कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''इस शीर्षक की माँग 10/– रुपये से घटायी जाय ।''

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री चन्द्रशेखर जी ।

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, बहुत–बहुत धन्यवाद, साधुवाद । मैं विपक्ष द्वारा पेश कटौती प्रस्ताव के पक्ष में तथा सरकार के शिक्षा विभाग पर प्रस्तावित बजट के खिलाफ में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । आपने समय दिया इसके लिए बहुत–बहुत साधुवाद । अब मैं इस पंचायत के बड़े मंच से अपने नेता सामाजिक न्याय के महायोद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी का साधुवाद और धन्यवाद करता हूँ । अपने नेता युवा आदर्श तेजस्वी प्रसाद यादव जी का धन्यवाद करता हूँ और हमारे बगल में बैठे हुए सचेतक साहब का धन्यवाद करता हूँ ।

महोदय, शिक्षा के बारे में जितनी बात की जाय बहुत ही कम होगा । शिक्षा एक व्यक्ति के जीवन, परिवार, समाज और राष्ट्र के अंधकार को दूर करने का सबसे सशक्त माध्यम है । ऐसे में अगर शिक्षा किसी भी कारण से कमजोर पड़ती हो, यह घोर चिंता का विषय है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ और इस बात को चूंकि जो चिंताजनक स्थिति पैदा हुई है, इस बात के लिए पक्ष और विपक्ष सब लोग को एक मत होना चाहिए कि आखिर यह जो नशा बेसुमार फैले हैं, डेढ़ साल की बच्ची के साथ कल हमारे यहां बलात्कार हुआ और उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड छोड़ दिया । दो साल की बच्ची, चार साल की बच्ची, छः साल की बच्ची, यह क्या हो रहा है महोदय और सरकार को विशेष रूप से इस मामले में पहल करनी चाहिए । इसमें सारे, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे विपक्ष का आपको सहयोग मिलेगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, ये बातें आ कहां से रही है । अगर हम आर्थिक सर्वेक्षण का जो प्रतिवेदन है, वर्ष 2025–26 का, इसको देखेंगे महोदय तो तालिका संख्या–12.14, पेज संख्या–425, स्पष्ट है कि नामांकन प्राथमिक स्तर पर कमजोर हुए हैं । अब लोग अपने बच्चों को नशा की तरफ ले जा रहे हैं, मजबूर हैं, ऐसी स्थिति भयावह है, पता नहीं एक–एक सदस्य वाकिफ होंगे कि इस ढंग से, पता नहीं क्या हो गया है कि बच्चे को अगर माता–पिता मना करते हैं तो माता–पिता पर भी गोली चलाने की स्थिति

मानसिकता रखते हैं । महोदय, रोज दिन 300 रुपया के लिए, 500 रुपया के लिए जो प्रतिवेदित नहीं होती हैं घटनाएं, 800 रुपया के लिए फेरीवाले का ये लोग छीन कर सूखा नशा खरीद कर पीते हैं, खाते हैं जो भी इस तरह की बातें होती हैं । महोदय, इसको हम आपके सामने, मैं सदन पटल पर रख दूंगा कि वर्ष 2023–24 की अपेक्षा वर्ष 2024–25 में 07 लाख 49 हजार बच्चे कम नामांकित हुए हैं प्राथमिक स्तर पर । कहां जायेंगे, नशा में लोग जा रहे हैं तो होगा क्या ? उसी तरह संयुक्त रूप से अनुसूचित जाति के 01 लाख 63 हजार बच्चे स्कूल नहीं जा सकें । अनुसूचित जनजाति के तो 17 हजार हैं और लड़कियों में 05 लाख 37 हजार है तो इस तरह से मैं, महोदय, और वही स्थिति है माध्यमिक शिक्षा का । माध्यमिक शिक्षा का क्या है ? नामांकन में कमी, लड़कों में तो कम है 32 हजार ही है लेकिन अनुसूचित जाति में 01 लाख 69 हजार है, उसी ढंग से उच्च प्राथमिक में अनुसूचित जाति में 1.55 प्रतिशत है, जबकि आंकड़ों की कलाबाजी होती है महोदय, सब को पता है, सरकार कुछ कलाबाजी दिखाती है, करती है, आंकड़ों को मिलाती है, सब काम करती है । उसी ढंग से...

(व्यवधान)

महोदय, उसी ढंग से सभी तरह के प्रारंभिक विद्यालयों में स्थिति और भयावह है । लड़कों में संयुक्त रूप से 07 लाख 81 हजार बच्चे नामांकन कम लिये वर्ष 2023–24 की अपेक्षा, अनुसूचित जाति के 03 लाख 32 हजार, अनुसूचित जनजाति के 18 हजार । लड़कियों में संयुक्त रूप से 04 लाख 55 हजार, इस तरह से यह नामांकन में कमी दर्ज की गयी है ।

ड्रॉप आउट की क्या स्थिति है ? पेज संख्या–426, तालिका–12.15, वर्ष 2023–24 में जो 1.26 प्रतिशत ड्रॉप आउट रेट था वह वर्ष 2024–25 में 6.8 हो गया, अंतर कितना हो गया 5.54 का । लड़कों में 1.23 प्रतिशत था वर्ष 2023–24 में वह वर्ष 2024–25 में 07 प्रतिशत हो गया, इसमें भी 5.77 दर्ज किया गया है । संयुक्त रूप से 5.65 प्रतिशत बच्चे स्कूल छोड़े हैं । इस तरह से शिक्षा पर हमारी सरकार खर्च कितना करती है ? महोदय, शिक्षा पर हमारी सरकार कुल जी॰डी॰पी॰ का महाराष्ट्र खर्च करती है 1.65 परसेंट, प्रतिशत में जी॰डी॰पी॰ का और वह रुपया होता है महोदय राशि में 01 लाख करोड़, महोदय, जनसंख्या कितनी है लगभग 11 करोड़ । केरल खर्च करती है अपने जी॰डी॰पी॰ का 1.5 परसेंट और वह लाख में होता है 55,261 करोड़। उसके बाद बिहार कितना खर्च करती है 1.56, यह होता है 68,216 करोड़ । महोदय, इसका मतलब स्पष्ट है जब जनसंख्या हमारा महाराष्ट्र के आसपास का है तो हम महाराष्ट्र से कम क्यों खर्च करते हैं ।

....क्रमशः....

टर्न–14 / अंजली / 19.02.2026

(क्रमशः)

श्री चन्द्र शेखर : इसी प्रकार से जब देश की स्थिति को समझेंगे तो हमारा देश कितना खर्च करता है, समुचा देश कितना खर्च करता है, तो इसमें देखेंगे, स्पष्ट है अमेरिका की आबादी है 33.5 करोड़ और वह खर्च करता है 118 लाख करोड़ शिक्षा पर, यह कुल जी0डी0पी0 का 5.5 परसेंट से लेकर 5.8 परसेंट तक है । रूस खर्च करता है 4.16 परसेंट, 8.1 लाख करोड़ शिक्षा पर खर्च करता है, चीन खर्च करता है 4 परसेंट 16.5 लाख करोड़ आबादी भारत और चीन की बराबर नहीं, भारत की लगभग एक करोड़ ज्यादा ही हो गया और भारत खर्च करती है 2.7 परसेंट शिक्षा पर 13.3 लाख करोड़ जबकि जनसंख्या हमारी चीन से एक करोड़ ज्यादा है, तो यह स्थिति भयावह स्थिति दर्शाती है कि जब शिक्षा पर हमारा ध्यान कम होगा तो महोदय, स्थिति भयावह होगी । महोदय, इस बात को समझते हुए शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इस देश के महान चिंतक नेल्सन मंडेला साहब ने कहा है शिक्षा दुनिया को बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार है । महोदय, उन्होंने कहा है कि शिक्षा के माध्यम से ही एक किसान की बेटी डॉक्टर,...

(व्यवधान)

एक खदान मजदूर का बेटा खदान का प्रमुख और खेतिहर मजदूर का बेटा महान राष्ट्र का राष्ट्रपति बन सकता है, नेल्सन मंडेला साहब का नाम छिपा हुआ नहीं है जिन्होंने अपना जीवन जेल में बिता दी उनकी यह फीलिंग है और उनका यह अनुभव है ।

महोदय, हम देख रहे थे महोदय, ऑक्सफोर्ड प्रेस द्वारा प्रकाशित रिसर्च बुक और उसकी पेज संख्या–304 में लिखी है, हमारे महागठबंधन से पहले की जो नीति थी शिक्षा की, नियोजन नीति के दंश से तेजस्वी प्रसाद यादव ने, ठीक है माननीय मुख्यमंत्री जी थे, तो 17 साल से आप इन्हीं के साथ थे ही, क्यों नहीं निकाल रहे थे तो इसमें लिखा है बिहार की भयावह स्थिति राज्यकर्मी के दर्जा से पहले की बात मैं कह रहा हूं –

"The salaries of the para-teachers are inadequate for survival and the field realties suggest that the fundamental rights of these teachers are denied by the government itself in terms of non-payment of equal wages for equal work."

महोदय, एक शिक्षक वर्ग जिसका हमारे सनातन संस्कृति भगवान का दर्जा जिस शिक्षक को प्राप्त है, उस शिक्षक को संघर्ष करना पड़े सैलरी के लिए, एक जगह तीस हजार मिलता था, एक जगह 32 हजार मिलता था...

(व्यवधान)

सब करवा दिए हैं, हम ही लोग आए हैं, तो करवाए हैं महोदय ।

अध्यक्ष : चन्द्र शेखर जी । चन्द्र शेखर बाबू, शिक्षा मंत्री आप भी थे ।

(व्यवधान)

श्री विनय कुमार चौधरी : संचिका के माध्यम से ये शिक्षकों के विषय की बात करते हैं, इसमें इनका सिग्नेचर भी नहीं है...

श्री चन्द्र शेखर : महोदय, देखिए डिस्टर्ब कर रहे हैं, बैठ जाएं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : विनय बाबू, बैठ जाइए । प्लीज, बैठ जाइए । हो गया, बात आ गई, प्लीज बैठ जाइए । यह कोई क्वेश्चन है ? बैठिए–बैठिए । बैठिए न । बिना अुनमति के अनुमति मत खड़ा होइए ।

श्री चन्द्र शेखर : महोदय, देखिए मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं । बैठ जाएं महोदय । मेरा समय बढ़ा दिया जाए महोदय । महोदय, साढ़े चार लाख शिक्षकों को बिहार में नियोजन के दंश से बाहर निकालना यह तेजस्वी प्रसाद यादव जी और महागठबधंन के समय का ही मामला है, दूसरे समय का मामला नहीं है महोदय और टी0आर0ई0–1 और टी0आर0ई0–2, हमारे सत्ता पक्ष के एक सुर्खाब के पंख लगाकर आए हैं, बगल के अपर हाउस में सदस्य हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूं, अब अद्भुत है,...

(व्यवधान)

हम शिक्षा मंत्री के कार्यभार का देख रहे थे लेकिन संचिका की जानकारी उन्हीं को है, मेरे पास नहीं है अद्भुत है, कुछ भी कुछ बोल देना । यह कौन नहीं जानता है कि टी0आर0ई0–1 के विज्ञापन के 1 महीना सात दिन के बाद पाठक साहब आए थे, तो बी0पी0एस0सी0 की बहाली से क्या मतलब है भाई, बेमतलब है । हाँ, पाठक साहब आए, तो आउटसोर्सिंग में अन्याय किए, पाठक साहब आए, तो वे अन्याय किए लाखों बहाली में कि पिछड़ों, दलितों, अनुसूचित का, आदिवासियों का सब का हिस्सा काट दिए और यह पत्र है राज्य सरकार, कैबिनेट का डिसीजन है कि आउटसोर्सिंग की बहालियों में आरक्षण का लाभ मिलेगा । पत्रांक–14556, दिनांक–17.11.2017 मगर कहीं बहाली हुई, इसकी कौन समीक्षा करेगा । मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूं कि कम से कम जो बहालियां हुई हैं, उसकी समीक्षा कराइए और मंत्री जी तो खैर दलित वर्ग को रिप्रजेंट करते हैं, हम आशा करेंगे कि कम से कम आरक्षण की समीक्षा करिए कि आउटसोर्सिंग में कितने परसेंट आरक्षित वर्ग के लोग आ सकें, नहीं आ सकें । महोदय, मतलब भयावह स्थिति है और टी0आर0ई0–1, टी0आर0ई0–2 में 2 लाख 90 हजार लोगों की वैकेंसी और 2 लाख 25 हजार लोगों का रिजल्ट, 2 लाख 17 हजार को कंपटीशन के माध्यम से शिक्षा के लिए समाज को परोसी गई, शिक्षक बहाल हुए, क्या इसको उपलब्धि नहीं कहेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव जी की, आदरणीय लालू प्रसाद जी की । वर्ष 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी, तो उस समय भी वही स्थिति थी कि

शिक्षक के सर्विस कंडीशन को आगे बढ़ाया गया, मेरा मतलब इस बात का है कि निश्चित तौर पर यह माना जाएगा कि जब–जब महागठबंधन आती है, तब–तब कुछ न कुछ समाज के लिए लाती है और जब–जब केंद्र से लेकर यहां तक सरकार बनती है, तो पेंशन खाती है । महोदय, पेंशन समाप्त करना यह जघन्य अपराध है, समझिए कौन बेटा–बेटी अपने माता–पिता का किस कद्र ख्याल करती है और साहब आप क्या करते हैं एक तो हत्या के जुर्म...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बीच में अनावश्यक खड़ा न होइए विनय बाबू ।

श्री अलोक कुमार मेहता : महोदय, माननीय सदस्य को निर्देशित कीजिए । ऑर्डर में रहता है, हर चीज में खलल डाल रहे हैं ।

अध्यक्ष : सही बात है । गलत चीज है बीच में नहीं बोलना चाहिए । बिना अनुमति के नहीं बोलिए ।

श्री चन्द्र शेखर : महोदय, संपूर्ण बिहार की आवाम जानती है । महोदय, मैं मधेपुरा की महान मतदाताओं के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से लगातार चौथी बार जीतकर आया हूं और मैं समझता हूं कि अगर भगवान जी मेरे साथ नहीं होते, तो मैं चुनाव हारकर आता । हमको भगवान जी भेजे हैं यहां XXX पर नकेल कसने के लिए ।

अध्यक्ष इस शब्द को हटा दिया जाए ।

(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : महोदय, अरे भगवान को कौन नहीं मानता है, मगर जो नहीं मानता है, हिंदू व्यवस्था को सनातन व्यवस्था को समाप्त करने का सबसे बड़ा औजार है, जरिया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपस में बात न करें । बोलिए आप ।

श्री चन्द्र शेखर : महोदय, भगवान राम जी अछूत कुल में पैदा होने वाले मनुवाद द्वारा बनाए गए अछूत कुल में पैदा होने वाली माता सबरी के जूठे बैर खा सकते हैं, मगर भगवान को मानने वाले लोग माता सबरी बेटा, चाहे मांझी साहब हों या राष्ट्रपति कोविंद साहब हों, उनको न मंदिर जाने देंगे, न कहीं और जाने देंगे, क्या है यह ? चौधरी साहब यह है समझिए, इसे कहते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ऐसा नहीं है, मंदिर जाने पर रोक नहीं है ।

श्री चन्द्र शेखर : महोदय, संपूर्ण बिहार के लोग जानते हैं कि ''मेडल लाओ नौकरी पाओ'' था क्या ? 17 साल के एन0डी0ए0 शासन में मेडल लाओ, नौकरी पाओ था क्या ? क्या तेजस्वी प्रसाद यादव जी को साधुवाद इस सदन को नहीं व्यक्त करना चाहिए । महोदय, एक ठोस उद्योग नीति, ठोस पर्यटन नीति, सरकारी खर्च पर गरीब मेधावी बच्चों को 100 बच्चों को बाहर भेजने की नीति इसी 22

से 24 जनवरी तक के काल में हुआ है । महोदय, जातिगणना हुई, 65 प्रतिशत आरक्षण की बढ़ोत्तरी हुई है, कहां फंसा हुआ है, न्यायालय के चक्कर में कमजोर पैरवी करके हमको फंसाते हैं और हमको हिंदू बनाते हैं, भैया आप अभी पाकिस्तान दे दो हिंदू बनाना चाहते हो, तो आदिवासी, दलित, पिछड़ा हिंदू नहीं हैं क्या ? महोदय, अद्भुत है, हमारे काबिल साथी लोग सत्य को दबाने की कोशिश करेंगे । ई0डब्लू0एस0 आरक्षण, एक हफ्ता में सब कुछ हो गया, मगर यू0जी0सी0 बिल आया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आया, सर्वे कराकर आया, 118 प्रतिशत ज्यादती होती है, 100 नहीं, 118 प्रतिशत और यू0जी0सी0 बिल के खिलाफ के कॉन्सिपरेसी हो गई ।

(क्रमशः)

टर्न–15 / पुलकित / 19.02.2026

(क्रमशः)

श्री चन्द्र शेखर : और जो–जो आदर्श थे, प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेन्द्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी जिन सेवा, समाज के आदर्श होते थे, XXX

अध्यक्ष : इन बातों को कार्यवाही से हटाया जाए । माननीय सदस्य जातिगत बात को शामिल मत कीजिए ।

(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : महोदय, मैं आप सभी को यह कहना चाहता हूं इस सदन को आपके माध्यम से कि 17 साल...

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं, विद्वान आदमी हैं और प्रधानमंत्री को जातिसूचक शब्द से जोड़ रहे हैं । पूर्व मुख्यमंत्री जो सजायाफ्ता महोदय, लालू प्रसाद लिखते हैं। श्रीमान लालू प्रसाद, लालू यादव कब से जोड़ने लगे, महोदय ? क्या वह नहीं है ? कथनी और करनी एक होनी चाहिए, चेहरा एक तरह का दिखाई पड़े, अपने अंदर झांकना चाहिए । इस तरह की भाषा कतई उचित नहीं है ।

अध्यक्ष : वह प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेगा ।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, हम सम्मान करते हैं । विजय बाबू अच्छे आदमी हैं। विभाग और सरकार में ठीक–ठाक मतलब स्थिति रखते हैं । मगर अन्याय, जुल्म काहे बोलते हैं ? यह सब हम बोले हैं ?

(व्यवधान)

माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बारे में सड़क पर कौन बोलते हैं ? यह देश नहीं जानता है क्या ? यह कोई नहीं जानता है ? हम तो, उनको मानने वाले लोग हैं । महोदय, अब आप देखिए ।

अध्यक्ष : आपका समय समाप्त हो रहा है ।

श्री चन्द्र शेखर : कौन नहीं जानता है । महोदय, वह बैठकर हमारा समय बर्बाद कर दिए। महोदय, बस 3 मिनट दिया जाए ।

अध्यक्ष : एक मिनट में अपनी बात रखिये ।

श्री चन्द्र शेखर : महोदय, कौन नहीं जानता है कि निःशक्तों के लिए 400 से 1500 रुपये पेंशन हो, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आंख खोली है, सरकार उस पर काम की है । क्या आप धन्यवाद नहीं करेंगे ? उसके बाद बिजली बिल माफी, इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे भीष्म पितामह कोसी क्षेत्र के बिजेंद्र बाबू कहने लगे, बिजली बिल माफी नहीं हो सकती है । मगर आप बिजली बिल माफ करने के लिए मजबूर हुए कि नहीं ? आप समझिए, क्या तेजस्वी यादव का साधुवाद नहीं करेंगे ? करोड़ों रोजगार और एन0डी0ए0...

(व्यवधान)

महोदय, दो–दो करोड़ प्रति साल नौकरी, 2022 तक किसानों की आय दुगुनी । हम लोग कब देखेंगे ? बस एक मिनट, महोदय दिया जाए । मेरा यह कहना है कि बीफ एक्सपोर्ट बढ़ा करके, भाजपा के लोग अपने आप को ब्राजील के लेवल में हैं । आप असली गौ माता के रक्षक और हिंदू बनते हैं । बीफ एक्सपोर्ट कैसे बढ़ गया ? कैसे स्लॉटर हाउस को रिमोट किया गया ?

अध्यक्ष : आपका समय समाप्त हुआ । श्री विनय कुमार सिंह ।

श्री चन्द्र शेखर : महोदय, उस शिक्षा हो, उस शिक्षा की स्थिति और भी भयावह है । एक मिनट दिया जाए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी को लिख के दे दें ।

श्री चन्द्र शेखर : माननीय मंत्री जी, हम सदन पटल पर रख देंगे, खाली कह देते हैं, सिमुलतला विद्यालय की स्थिति भयावह है । 2 जून, 2023 समझ लीजिए चंद्रशेखर जी के समय में हुई । उसके बाद सिमुलतला शिक्षा सोसाइटी की बैठक नहीं हुई । बी0पी0एस0सी0 को बहालियां देनी थी, निर्णय हुआ । मॉडल स्कूल की अभी चर्चा हो रही है । सरकार करने जा रही है । जिला स्तर पर मॉडल स्कूल उच्च स्तरीय बैठक में विजय बाबू जानते हैं । उच्च स्तरीय बैठक में यह तय हुआ कि सिमुलतला मॉडल का स्कूल हर जिला में एक बने । उसके आधार पर जो सामान्य सभा की बैठक जो एपेक्स बॉडी होती है सिमुलतला की, उसकी बैठक हुई और यह निर्णय हुआ । पाठक साहब भी उसमें शामिल थे । परंतु एक नाजायज आदेश से उसको रोक दिया गया इसलिए शिक्षा पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना है ।

अध्यक्ष : आपकी बात आ गयी है । माननीय सदस्य श्री विनय कुमार सिंह ।

श्री चन्द्र शेखर : अब मैं अपने वक्तव्य को सदन पटल पर रखता हूं आपकी अनुमति चाहता हूं ।

श्री विनय कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्रीमती अनीता : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाह रही हूं । इस सदन में,

अध्यक्ष : माननीय सदस्या आप बैठ जाइये ।

श्रीमती अनीता : महोदय, मुझे 30 सेकेंड दिया जाए ।

अध्यक्ष : आपको मौका देंगे, जब समय आयेगा ।

श्री विनय कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करते हुए आज विपक्ष के द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव के विरोध में और अपनी सरकार की मांग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । यह अवसर आपने दिया है, आपका आभार प्रकट करता हूं । महोदय, प्राचीन काल से अपनी शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है । इसके साक्षी अपने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय हैं । महोदय, 12वीं शताब्दी तक इसका गौरवशाली इतिहास रहा है नालंदा और तक्षशिला का । लेकिन दुर्भाग्य है इस राज्य का की आजादी के 70 वर्षों तक जिन लोगों ने इस राज्य की सत्ता को संभाला। विशेषकर कांग्रेस के भाई बैठे हुए हैं, कांग्रेस की सरकार रही और 15 वर्षों तक अभी विद्वान साथी डॉक्टर चंद्रशेखर जी बोल रहे थे, मैं उनको सुन रहा था। इस राज्य के शिक्षा मंत्री के रूप में हमने इनको देखा है और 15 वर्षों तक इनका राज सरकार में रहा और इनकी उपलब्धियां क्या रही इस राज्य के लिए ? हम उपलब्धियां खोज के लाए, अनुसंधान करके लाए तो इन्होंने चरवाहा विद्यालय जैसी उपलब्धियां को लेकर आए थे, 15 वर्षों के अंदर सरकार में । मैं तो आज अपने पूर्व के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 15 वर्षों के यदि वे कितने दूरदर्शी लोग थे, कि 15 वर्षों के जंगलराज को समाप्त करने के लिए बिहार से किसी नायक को चुना । हमारे आज के विकास पुरुष जिनको हम जानते हैं, बिहार जानता है, देश जानता है, नीतीश कुमार जी को अपने साथ लाए कि जंगलराज का खात्मा करना है । यदि नहीं लाते, तो क्या होता इस बिहार का, शिक्षा की दुर्दशा और क्या होती, वह भगवान ही जानते । लेकिन यह तो संयोग ठीक रहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 में जब बिहार में एन0डी0ए0 की सरकार बनी तो एक माहौल बदला और आज भी एक माहौल बदला ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति–शांति । शांतिपूर्वक माननीय सदस्य की बातों को सुनिए ।

श्री विनय कुमार सिंह : और आज मैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया बैठे–बैठे मत बोलिये । आप सभी सदस्यों से आग्रह है कि बैठकर नहीं बोलिये ।

श्री विनय कुमार सिंह : मान्यवर नीतीश कुमार जी ने यह संकल्प लिया कि जो गौरवशाली इतिहास मेरा नालंदा और विक्रमशिला का था उस इतिहास को पुनः बिहार में

लागू करूंगा और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और हमारे नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपना जो गौरवशाली इतिहास था, उस विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को प्रारंभ करने का काम किया। आज दुनिया और देश के बहुत सारे छात्र हमारे बिहार में उस नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आज आ रहे हैं । बिहार की जो गरिमा गिरी थी उसको हमारे मान्यवर नीतीश कुमार जी ने वापस लाने का प्रयास किया है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को मैं इस सदन के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन उनका स्वागत करना चाहता हूं।

महोदय, उतना ही नहीं जब 2005 में हमारी एन0डी0ए0 की सरकार बनी, यह तय किया गया कि साहब एक किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय होंगे। यह हमारा मानक है, किसी भी सरकार को, यदि विजनरी सरकार नहीं हो, तो कुछ नहीं कर सकती है । लेकिन हमारी सरकार, एन0डी0ए0 की, 2005 में बनी, तो वहां से तय किया गया कि एक किलोमीटर के अंदर में प्राथमिक विद्यालय होंगे, तीन किलोमीटर में मध्य विद्यालय होंगे, और प्रत्येक पंचायत में हमारे माध्यमिक विद्यालय खोले जाएंगे । यह एक मानक तैयार किया गया । आज मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कि जो मानक हमने 2005 में प्लेटफार्म तैयार किया था, आज हम सभी पंचायतों में माध्यमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय, हाई स्कूल हैं, सभी मानक को पूरा कर रहे हैं और आज स्थिति यह है, महोदय, कि यदि गिना जाए आज, तो हमारे यहां सरकारी माध्यमिक उच्च विद्यालयों की संख्या 9300 इस बिहार के अंदर हो गई है । जबकि 8000 लगभग ही पंचायत हैं, इस बिहार के अंदर और उतना ही नहीं, आज माध्यमिक कक्षाओं में बच्चों की कुल संख्या 34 लाख 80 हजार 70 विद्यार्थी जो हैं, हमारे इन स्कूलों में, कक्षाओं में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं । महोदय, उतना ही नहीं, आज राज्य में राजकीय विद्यालय, आज राज्य में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या इतनी हो गई ।

(क्रमशः)

———————————————————————————

XXX – आसन के आदेशानुसार अंश विलोपित किया गया ।

———————————————————————————

टर्न–16 / हेमन्त / 19.02.2026

(क्रमशः)

श्री विनय कुमार सिंह : महोदय, आज राज्य में माध्यमिक उच्च विद्यालयों की संख्या इतनी हो गयी। महोदय, आज इस राज्य के अंदर 19 सार्वजनिक विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं..

अध्यक्ष : आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री विनय कुमार सिंह : महोदय, आज इस राज्य के अंदर 40,522 प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं,। 28,628 मध्य विद्यालय इस राज्य के अंदर चल रहे हैं, बुनियादी 391 काम कर रहे हैं और मैं सुन रहा था कि इस राज्य के अंदर 2 करोड़ 21 लाख 93 हजार 885 बच्चे, जो 6 वर्ष से 13 वर्ष की आयु वाले हैं, वह विद्यालय में नामांकित हैं, पढ़ रहे हैं। इस राज्य के प्रारंभिक विद्यालय, निजी विद्यालय में 1 करोड़ 80 लाख 22 हजार 810 बच्चे आज प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। महोदय, सरकारी एवं गैर सरकारी सहायता विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या 1 लाख 4 हजार 751 है और अभी मैं डॉक्टर साहब का सुन रहा था कि विद्यालयों में बच्चे नहीं हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी को और अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जो बिहार के बच्चे को सरस्वती के मंदिर तक ले जाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने आज इस राज्य को ऐसा सर्व शिक्षा अभियान दिया, तो देश के सारे प्राथमिक विद्यालय के भवन यदि आज चकाचक दिखायी दे रहे हैं, तो वह उनकी देन थी और इसको हमारे नीतीश कुमार जी ने बढ़ाने का काम किया। एक मानक तय किया था कि 40 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक बहाल होंगे। उस मानक को आज पूरा किया गया है। हमारे नीतीश कुमार जी ने पूरा किया है। यह साफ–साफ दिखायी दे रहा है। डॉक्टर साहब, आप इस राज्य के शिक्षा मंत्री रहे हैं। आप कलेजे पर हाथ रखकर विचार कीजिएगा। हमारी केंद्र की सरकार ने आज देश के अंदर नयी शिक्षा नीति को लागू किया है। नयी शिक्षा नीति 2020 में लागू की गयी। उस नयी शिक्षा नीति से अब छात्र अपनी भाषा में पढ़ पायेंगे, यानी भोजपुरी क्षेत्र के बच्चे भोजपुरी में पढ़ेंगे, मैथिली क्षेत्र के बच्चे मैथिली में पढ़ेंगे। जो मातृभाषा है उसी भाषा में छठी क्लास तक उनको छूट दी गयी कि वह पढ़ने का काम करेंगे।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय आपका हो रहा है, संक्षिप्त करें।

श्री विनय कुमार सिंह : महोदय, सरकार बजट का 20 प्रतिशत, इसी से आकलन किया जा सकता है कि सरकार का शिक्षा के प्रति विजन क्या है। इस बात से आकलन किया जा सकता है कि सरकार के बजट का 20 प्रतिशत व्यय शिक्षा पर कर रही है, इसका साफ–साफ प्रमाण है कि यह सरकार शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती है, बिहार को साक्षर बनाना चाहती है। महोदय, इतना ही नहीं, आज हमारी सरकार बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मैट्रिक पास करने पर 10 हजार रूपया, इंटर करने पर 25 हजार रूपया और स्नातक करने पर 50 हजार रूपया...

अध्यक्ष : कृपया, समाप्त करें।

श्री विनय कुमार सिंह : देकर महिला सशक्तिकरण की ओर कदम बढ़ाने का काम कर रही है। आज हमारे बिहार की बेटियों को सरकार ने 35 प्रतिशत तक आरक्षण देकर...

अध्यक्ष : कृपया, समाप्त करें।

श्री विनय कुमार सिंह : 50 प्रतिशत पंचायती राज में आरक्षण देकर...

अध्यक्ष : डॉ0 कुमार पुष्पंजय।

श्री विनय कुमार सिंह : समाज के समतुल्य बनाने का काम किया है। महोदय, बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से तीन चरण में हमारी सरकार ने दो 2 लाख 27 हजार 195 शिक्षकों की बहाली की है।

अध्यक्ष : विनय जी, आपका समय समाप्त हुआ। कृपया, बैठ जायें।

श्री विनय कुमार सिंह : महोदय, दो मिनट। महोदय, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। महोदय, 1915 से लेकर, मैं सरकार का ध्यान, शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि ठीक है हम बजट का 20 प्रतिशत पैसा शिक्षा जगत में खर्च कर रहे हैं, यह बात ठीक है, लेकिन आपसे मेरा आग्रह होगा, निवेदन होगा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक, चूंकि, अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार अपने किसी विद्यालय की दसवीं क्लास में....

अध्यक्ष : कृपया, आप बैठ जायें। डॉ0 कुमार पुष्पंजय।

श्री विनय कुमार सिंह : सर, एक मिनट। 1915 से 18 तक...

अध्यक्ष : आपने अपनी बातों को रख दिया है। विनय बाबू, अलग से लिखकर दे दीजिए। समय कम है।

डॉ0 कुमार पुष्पंजय। आपका समय आठ मिनट है।

डॉ0 कुमार पुष्पंजय : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का अवसर है कि हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री नीतीश कुमार जी के दिशा–निर्देशन पर हमारी पार्टी ने मुझे आज वित्तीय वर्ष 2026–27 के आय–व्यय में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर सरकार के पक्ष में बोलने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिहारवासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का नेतृत्व हम बिहारवासियों को प्राप्त है। संपूर्ण देश में इनकी कार्यशैली की चर्चा हो रही है। इनके कार्यों का अनुसरण देश के दूसरे राज्यों के द्वारा किया जाता है। बीस वर्षों के शासनकाल के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता बिहारवासियों के बीच बढ़ती जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, बिहार के वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट में शिक्षा को मानक रूप से सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लगभग 68,216.95 करोड़ रूपये बजटीय आवंटन किया गया है। यह वर्ष 2026–27 के पेश कुल बजट 3,47,589.76 करोड़ रूपये का लगभग 20 प्रतिशत है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर सुधार हुआ है। शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए व्यापक स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति की गई है और पठन–पाठन का निरीक्षण गहन पैमाने पर विभिन्न स्तरों से किया जा रहा है। सरकार का बालिकाओं के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना काफी सराहनीय

पहल रही है। साथ ही, स्मार्ट क्लास एवं मिड–डे मील काफी प्रशंसनीय कदम साबित हुआ है। सरकार 2008 के पारित संकल्प के द्वारा संबद्धता प्राप्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम आधारित अनुदान का लाभ संबंधित शिक्षण संस्थान के कर्मियों को दिया जा रहा है, जो संबद्धता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में कार्यरत कर्मियों के लिए नवजीवन प्रदान करने जैसी सुनहला पहल है। महोदय, ठीक उसी तरह, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर सभी विषयों में बिहार लोक सेवा आयोग एवं विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की जा रही है, जो एक प्रशंसनीय कार्य है। संबद्धता प्राप्त डिग्री कॉलेजों को भी 2008 से पारित संकल्प के द्वारा विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम पर आधारित अनुदान महाविद्यालय कर्मियों को दिया जा रहा है। उक्त मिलने वाले अनुदान से महाविद्यालय कर्मियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठा रहा है।

(इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

यहां मैं एक सलाह के रूप में अपनी ही सरकार से अनुरोध करता हूं कि बिहार के संबद्ध महाविद्यालय के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतनमान की चिर–प्रतीक्षित मांगों की पूर्ति के लिए 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव के पूर्व एक हाई लेवल कमेटी का जो गठन किया गया है, उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। अनुरोध है कि हमारी सरकार इस दिशा में पहल तेज करे। सात निश्चय की कड़ी में उन्नत शिक्षा एवं उज्ज्वल भविष्य का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय की स्थापना करना, दूसरा, प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलना, तीसरा, नए उच्च शिक्षा विभाग का गठन और पुराने प्रतिष्ठित शिक्षित संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करना है।

(क्रमशः)

टर्न–17 / संगीता / 19.02.2026

...क्रमशः...

डॉ0 कुमार पुष्पंजय : उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्येक जिले में नए–नए केन्द्रीय विद्यालयों एवं नवोदय विद्यालयों की स्थापना कराना सरकार का सराहनीय कदम और पहल है । प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के विकास में एक अभिनव क्रान्ति हुई है । नए–नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है । अलग–अलग शिक्षा विधि के लिए अलग–अलग विश्वविद्यालय से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अग्रसर है । विद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति पूरी पारदर्शिता के साथ हो रही है । यह सुशासन के सरकार की बड़ी उपलब्धि है । शिक्षा के

क्षेत्र में सभी स्तर पर तेजी से व्यापक सुधार हो रहा है । शिक्षा के क्षेत्र में उक्त सभी कार्यों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कोटि–कोटि बधाई के पात्र हैं।

महोदय, राज्य के सभी सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को दो–दो लैपटॉप एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को 3–3 लैपटॉप दिया गया है, जिससे ऑनलाईन उपस्थिति एवं अनुश्रवण की व्यवस्था है । कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी शिक्षण संस्थानों में कम्प्यूटर की व्यवस्था की गई है । माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की परीक्षा प्रणाली सम्पूर्ण देश में एक बेहतरीन नजीर बन गया है, जिससे अन्य राज्य भी इस प्रणाली को अपना रहे हैं । समय पर पंजीयन, समय पर परीक्षा और समय पर परिणाम प्रकाशित होना एक सुखद अनुभूति हो रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी सरकार के समक्ष सलाह के रूप में कुछ मांग रख रहा हूं । बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी की धर्मपत्नी के नाम पर शेखपुरा जिला के बरबीघा थाना अंतर्गत ग्राम, पोस्ट– मौर में स्थित श्रीमती रामरूचि देवी मध्य विद्यालय का भवन काफी जर्जर, जीर्ण–शीर्ण एवं ढहने के कगार पर पहुंच चुका है । अपनी सरकार से अनुरोध है कि मौर स्थित उस मध्य विद्यालय के भवन का जीर्णोद्धार करते हुए अतिरिक्त कक्षा, कमरों का निर्माण करने का विचार किया जाए । दूसरा है, शेखपुरा जिला के बरबीघा में स्थित प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण जी के नाम पर एस0के0आर0 महाविद्यालय में शिक्षकों की कमी है एवं महाविद्यालय का भवन भी अपने स्थापना काल का बना होने से आज की स्थिति में कमरों की कमी को झेलते हुए जीर्ण–शीर्ण स्थिति में पहुंच चुका है, जिससे विद्यार्थियों को पठन–पाठन में काफी दिक्कत हो रही है, कृपया इस ओर माननीय मंत्री जी से ध्यान देने का अनुरोध करता हूं । माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में बैठे हुए हैं, उनसे मैं सादर आग्रह करूंगा कि शेखपुरा को प्रखंड से लेकर जिला तक बनाने में स्वर्गीय राजो बाबू का अहम योगदान रहा है । उनकी प्रतिमा शेखपुरा कलेक्ट्रियट में बनकर तैयार है, जो प्लास्टिक में लिपटा हुआ है और काफी दिनों से धूल फांक रहा है । शेखपुरावासियों की प्रबल इच्छा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी शेखपुरा जिला में समृद्धि यात्रा के दौरान स्वर्गीय राजो बाबू की प्रतिमा का अनावरण अपने हाथों से करने की कृपा करें, जो स्वर्गीय राजो बाबू के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन ग्रहण करें । आपका समय हो गया है ।

डॉ0 कुमार पुष्पंजय : धन्यवाद, बहुत–बहुत धन्यवाद सर ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अभिषेक रंजन जी, आपके पास 4 मिनट का वक्त है ।

श्री अभिषेक रंजन : सदन के उच्चतम आसन के प्रति अपनी पूर्ण आस्था एवं सदन के सभी माननीय सदस्यों के प्रति आदर–सम्मान एवं सद्भाव व्यक्त करते हुए मैं अपनी बातों की शुरूआत करता हूं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं

आपके माध्यम से अपनी विधान सभा क्षेत्र चनपटिया के जागरूक, मेहनतकश एवं प्रतिभाशाली जनता को कोटि–कोटि नमन करता हूं । सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण हमारे युवाओं में अपार क्षमता, ऊर्जा एवं जज्बा है लेकिन संसाधनों की कमी उनके सपनों की उड़ान को सीमित कर रही है । आज मैं इस सदन में विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों की आवाज बनकर खड़ा हूं । हमारे सदस्य, वरिष्ठ सदस्य यह पूछ रहे थे कि कांग्रेस ने क्या किया है ? मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस देश को शिक्षा का अधिकार कानून दिया । हमारा स्पष्ट मत है कि शिक्षा अधिकार है, एहसान नहीं । कांग्रेस ने नवोदय विद्यालय दिए, सेंट्रल स्कूल दिए, आई0आई0एम0 दिए, आई0आई0टी0 दिए और मेरा मानना है कि माननीय सदस्य जिस स्कूल से, जिस कॉलेज से शिक्षा ग्रहण किए होंगे, वह भी कांग्रेस की ही देन होगी । मेरे विधान सभा क्षेत्र के चनपटिया प्रखंड की शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति अत्यंत ही चिन्ताजनक है, 14 से अधिक विद्यालय ऐसे हैं जिनके पास अपनी भूमि नहीं है । पूरे जिले में 105 विद्यालय भूमिहीन हैं । चनपटिया में 22 से अधिक विद्यालय ऐसे हैं, जिनके पास भवन नहीं है और जहां भवन है भी, वह दो कमरों का जर्जर ढांचा है । जिले में 143 विद्यालयों को अपग्रेड कर हाई स्कूल बना दिया गया है परन्तु न पर्याप्त कक्षाएं हैं, न विषयवार शिक्षक हैं, 191 विद्यालय ऐसे हैं, जहां आधारभूत संरचना का घोर अभाव है । क्या केवल उन्नयन की घोषणा कर देना शिक्षा का सुधार है ? क्या भवन, शिक्षक और संसाधन के बिना हाई स्कूल बन जाना पर्याप्त है ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पी0एम0श्री उच्च विद्यालय, चनपटिया में लगभग 1500 छात्र–छात्राएं नामांकित हैं । 11वीं और 12वीं के 700 विद्यार्थियों के लिए केवल एक संगीत शिक्षक है । कक्षा–6 से 8 तक मात्र 3 शिक्षक हैं । बैठने के लिए पर्याप्त बेंच और डेस्क नहीं है, परिणाम यह है कि बच्चे उपस्थिति दर्ज कराकर लौट जाते हैं। क्या यही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है ? क्या यही नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है ? जहां किताबों की कमी हो और शिक्षक भी कम हो, वहां सपनों की उड़ान अक्सर थम जाती है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे चनपटिया विधान सभा क्षेत्र में एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है । सरकार ने सात–निश्चय योजना के अंतर्गत और माननीय मुख्यमंत्री जी ने समृद्धि यात्रा के दौरान प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की थी लेकिन जारी अधिसूचना में चनपटिया को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है । पश्चिमी चंपारण का सबसे बड़ा प्रखंड मझौलिया है, जहां 29 पंचायतें हैं और विद्यार्थियों की संख्या अन्य प्रखंडों से 21 प्रतिशत अधिक है, वहां भी एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, जिससे हजारों विद्यार्थी पलायन को मजबूर हैं। अनेक छात्र आर्थिक अभाव में पढ़ाई छोड़ देते हैं । क्या यह क्षेत्रीय असमानता नहीं है? क्या यह शिक्षा के अधिकार के साथ

न्याय है ? राज्य में लगभग 40 विश्वविद्यालय और 286 कॉलेज संचालित हैं लेकिन इनमें से बहुत कम संस्थान एन0ए0ए0सी0 मान्यता प्राप्त हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और एकेडमिक विश्वसनीयता प्रभावित होती है । तकनीकी शिक्षा की स्थिति भी चिन्ताजनक है । लगभग 56 इंजीनियरिंग कॉलेज होने के बावजूद भी किसी को भी एन0बी0ए0 मान्यता नहीं मिली है, परिणामस्वरूप छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालयों में आगे की पढ़ाई में कठिनाई होती है। एन0आई0आर0एफ0, 2025 की रैंकिंग में आई0आई0टी0, पटना कुल मिलाकर 36वें और इंजीनियरिंग श्रेणी में 19वें स्थान पर है जबकि एन0आई0टी0, पटना 53वें स्थान पर है । राज्य के अधिकांश विश्वविद्यालय शीर्ष 100 में जगह नहीं बना पाए हैं । गुणवत्तापूर्ण संस्थानों की कमी के कारण हर वर्ष बड़ी संख्या में छात्र दिल्ली, पूणे और बैंगलूर जैसे शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं । यह स्पष्ट है कि बिहार को उच्च शिक्षा में मान्यता, शोध, नवाचार और शिक्षक–प्रशिक्षण पर ठोस निवेश कर त्वरित सुधार की आवश्यकता है...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अब आसन ग्रहण करें, आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री अभिषेक रंजन : सर, दो मिनट सर । विद्यालयों की संख्या गिनाने से शिक्षा की गुणवत्ता सिद्ध नहीं होती । एक शिक्षक 5 कक्षाओं को संभाल रहे हैं । राज्य में लाखों पद रिक्त हैं, नियोजित शिक्षक वेतन–विसंगति और सेवा असुरक्षा से जुझ रहे हैं । मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि समान कार्य के लिए समान वेतन, सेवा सुरक्षा सुनिश्चित की जाए । एन0ए0ए0सी0 ग्रेडिंग संतोषजनक नहीं है । परीक्षा परिणाम में देरी युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय है । यह केवल शिक्षा का प्रश्न नहीं, यह बिहार की बौद्धिक और...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री अभिषेक रंजन : सर कन्क्लूड कर रहे हैं, दो मिनट सर । आखिर में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हम जानते हैं कि लोकतंत्र में संख्या बल को तवज्जो दिया जाता है, लोकतंत्र में गरदनें गिनी जाती हैं, लोकतंत्र में संख्या बल देखा जाता है लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप अपनी गरदनें गिनवाने का काम करें और जिस दिन त्याग और बलिदान की बारी आएगी, इस सदन का एक छोटा सा सच्चा सिपाही आपको सबसे आगे खड़ा दिखेगा ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विष्णु देव पासवान जी । पांच मिनट है आपके पास में समय ।

टर्न–18 / यानपति / 19.02.2026

श्री विष्णुदेव पासवान : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उपमुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को और हमारे नेता लोक जनशक्ति पार्टी (रा0) के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को और दरौली विधान सभा की महान

जनता का मैं धन्यवाद करता हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर पद्मभूषण श्रद्धेय रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने सामाजिक न्याय को शिक्षा से जोड़ा । वे कहा करते थे कि जब तक गरीब और दलित के हाथ में कलम नहीं होगी, तब तक समानता अधूरी रहेगी और आज आदरणीय चिराग पासवान जी के ''बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट'' विजन में शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माना गया है । अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्षों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय 8000 रु0 से बढ़ाकर 16,000 रु0 कर दिया गया है और उनकी वार्षिक मानदेय वृद्धि 200 रु0 से बढ़ाकर 400 रु0 कर दी गई है । रात्रि प्रहरियों का मानदेय 5000 रु0 से बढ़ाकर 10,000 रु0 किया गया है । शैक्षणिक सत्र 2025–26 में वर्ग 1 से 8 तक 1.19 करोड़ छात्र–छात्राओं को 11.50 करोड़ पुस्तकों को मुद्रित कराकर राज्य के सभी प्रखंडों में निःशुल्क ससमय उपलब्ध करा दिया गया है । 1.7 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी या फिर प्रगति पर है । विद्यालय भवन निर्माण एवं मरम्मत पर 8000 करोड़ से अधिक खर्च किये गये हैं। छात्रवृत्ति, पोशाक एवं साइकिल योजना पर मिलाकर 5000 करोड़ से अधिक का वार्षिक प्रावधान किया गया है। राज्य में 2 करोड़ से अधिक छात्रों का नामांकन सरकारी विद्यालयों में हैं । सैकड़ों प्लस–टू विद्यालयों का उत्क्रमण हुआ । आई0टी0आई0, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट क्लास और ई–लर्निंग प्लेटफॉर्म का विस्तार किया । महोदय, राजद के शासनकाल के उस समय शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति थी यह बिहार की जनता भली–भांति जानती है । उस दौर में 90 के दशक में जो चरवाहा विद्यालय खोले गए थे, उन्हें शिक्षा का मंदिर कहा गया था । लेकिन हकीकत यह है कि कई जगह वे शिक्षा के मंदिर नहीं, बल्कि अव्यवस्था और मजाक का केंद्र बनकर रह गया है । जहां बच्चों के हाथ में किताब होनी चाहिए थी, वहां जुआ की गोटियां चलती थीं । जहां ज्ञान की रोशनी जलनी चाहिए थी, वहां शराब की बोतलें खुलती थीं । स्कूल परिसर में गाय भैंस बांध दी जाती थीं । यह शिक्षा के नाम पर छल था, गरीब और वंचित समाज के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ था । उस दौर में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के बजाय उसे बदनाम करने का काम किया गया। जो खुद 9वीं पास हो वो क्या जाने शिक्षा का महत्व, शिक्षा का महत्व वही समझ सकता है जिसने शिक्षा की ताकत को महसूस किया हो । जो स्वयं शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष उपलब्धि नहीं रखते, वे आज शिक्षा सुधार की बड़ी–बड़ी बातें कर रहे हैं । बिहार की जनता जानना चाहती है क्या केवल आरोप और भाषण से स्कूल सुधरेंगे ?

(व्यवधान)

सुन लीजिए, सुन लीजिए । शिक्षा सिर्फ प्रमाणपत्र का विषय नहीं, बल्कि दृष्टि, समर्पण और प्रतिबद्धता का विषय है । जो शिक्षा की गंभीरता को जीवन में प्राथमिकता नहीं दे पाए, वे आज शिक्षा पर नैतिक उपदेश कैसे दे सकते हैं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठे–बैठे नहीं बोलिए । टोका–टोकी नहीं कीजिए । आप शांति बनाएं ।

श्री विष्णुदेव पासवान : सुन लीजिए, अभी बहुत कुछ है । हमारा मानना है कि बिहार को दिखावा नहीं, बल्कि मजबूत नीति, योग्य शिक्षक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए। हमारा मानना है कि शिक्षा के साथ ऐसा प्रयोग नहीं, बल्कि ईमानदार प्रयास होना चाहिए । विद्यालय ज्ञान का केंद्र बने, अनुशासन का प्रतीक बने न कि अव्यवस्था का अड्डा बने। मैं इस सदन के माध्यम से बिहार की जनता को सच्चाई की याद दिलाना चाहता हूं जब राज्य की पहचान विकास से नहीं बल्कि घोटालों से होती थी ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : कृपया शांति बनायें, माननीय सदस्या ।

श्री विष्णुदेव पासवान : राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में हुआ बहुचर्चित चारा घोटाला केवल पैसों की लूट नहीं थी, यह गरीबों के अधिकारों की लूट थी । उस समय सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति को भी अदालत ने दोषी माना और सजा सुनाई इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि भ्रष्टाचार व्यवस्था की जड़ों तक समा चुका था । और फिर जमीन के बदले नौकरी जैसे आरोप क्या बिहार के युवाओं का भविष्य सौदेबाजी का विषय था । क्या सरकारी नौकरी किसी की निजी जागीर थी । यह सवाल आज भी जनता के मन में गूंज रहा है । हमारा संकल्प है घोटाले नहीं, विकास की राजनीति । परिवारवाद नहीं, पारदर्शिता की राजनीति ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : आप शांति बनाएं माननीय सदस्य । आपके पास एक मिनट का वक्त है ।

श्री विष्णुदेव पासवान : अध्यक्ष महोदय, हम मानते हैं कि अभी भी सुधार की गुंजाइश है । गुणवत्ता, प्रशिक्षण और तकनीकी संसाधनों को और मजबूत करना होगा ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप शांति बनाएं । बैठे–बैठ नहीं बोलें ।

श्री विष्णुदेव पासवान : लेकिन दिशा सही है, नीयत स्पष्ट है और परिणाम भी दिख रहे हैं। रामविलास पासवान जी ने जो सपना देखा था । गरीब का बेटा भी अधिकारी बने । वह सपना आज शिक्षा के बजट के माध्यम से साकार हो रहा है । चिराग पासवान जी का संकल्प है कि बिहार को अवसरों की

धरती बनाया जाय, जहां प्रतिभा संसाधनों के अभाव में न रुके । विपक्ष को मैं कहना चाहता हूं अगर आपके पास बेहतर सुझाव हैं तो सदन में रखिए ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका समय हो गया है ।

श्री विष्णुदेव पासवान : लेकिन विकास को बदनाम करने की राजनीति मत कीजिए ।

(व्यवधान)

आप रहने दीजिए, आपलोगों ने क्या किया है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना आसन ग्रहण करें । आपका समय हो गया है ।

श्री विष्णुदेव पासवान : जाते–जाते एक शब्द मैं और कहना चाहूंगा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी जी को देश के सबसे बड़े सदन में चुनौती देने वाले मर्द थे स्व0 रामविलास पासवान जी । वे बेचारे नहीं थे ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अख्तरूल ईमान ।

श्री विष्णुदेव पासवान : आप हमें बताएंगे सुशासन क्या होता है, संस्कृति क्या होती है, सभ्यता क्या होता है ? जिनके शासन काल में सोना बेचकर लोहा खरीदने की प्रथा चलाई गई थी । धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अख्तरूल ईमान । चार मिनट का वक्त है आपके पास।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, टोका–टोकी नहीं करें । शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर बात चल रही है । यह महत्वपूर्ण विभाग है टोका–टोकी नहीं करें ।

श्री राजू तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि माननीय सदस्य बोल रहे थे और बैठे–बैठे ये बी0डी0ओ0 साहब जो हैं या जो अन्य सदस्य लोग हैं एकदम मतलब समय को बर्बाद करना ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने बार–बार उनसे आग्रह किया है ।

श्री राजू तिवारी : महोदय, नये सदस्य हैं और बोल रहे हैं ।

उपाध्यक्ष : अख्तरूल ईमान साहब, अपना भाषण जारी रखें ।

श्री राजू तिवारी : ये लोग सत्य नहीं सुनना चाहते हैं महोदय । सत्य सुनना ही नहीं चाहते हैं महोदय । इनलोगों के बैठे–बैठे बोलने पर प्रतिबंध लगाइये महोदय ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायं । एक–एक मिनट का महत्व है ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, बैठ जायं । कृपया आसन ग्रहण करें ।

श्री अख्तरूल ईमान : डिप्टी स्पीकर साहब, हाउस ऑर्डर में नहीं है, जरा लिया जाय । जनाबे आली, आज अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बहस हो रही है और कहा गया है कि नॉलेज इज पावर...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : कृपया बैठ जायं माननीय सदस्य ।

श्री अख्तरूल ईमान : यानी ज्ञान ही शक्ति है और मैं समझता हूं 20 साल पुरानी सरकार जिनको काम करने के बहुत सारे मौके मिले, एजुकेशन के सेक्टर में इसने

क्या किया है । आईने में अपनी तस्वीर देखनी चाहिए । आज कई एजुकेशन के ताल्लुक से तहकीक करनेवाली कई प्राइवेट एजेंसियों की रिपोर्ट है कि बिहार में आज भी क्लास 8 के बच्चों की तादाद तकरीबन 70 फीसद ऐसे हैं जो क्लास 5 की किताब नहीं पढ़ पाते हैं । हुआ क्यों ऐसा महोदय इसलिए कि आपने शिक्षा जगत पर वो बमबारी की जिसके आसरात आज दिखते हैं । मैंने 2008 में इसी सदन में कहा था कि हिरोशिमा नागाशाकी पर बमबारी हुई है, प्रदूषण कम हुआ है, सेहतमंद बच्चे पैदा हो रहे हैं । लेकिन बिहार की शिक्षा जगत पर आपने जो बमबारी की है, मैं समझता हूं कि आनेवाली पीढ़ी भी इस बीमारी से नहीं निकल पायेगी जिसका साफ संकेत आज दिख रहा है। महोदय, प्राइमरी एजुकेशन का बुरा हाल है और हायर एजुकेशन तो चौपट कर दिया है आपने । पटना यूनिवर्सिटी अब किसी गिनती की यूनिवर्सिटी नहीं रही है । साइंस कॉलेज को भी आपने दफना दिया और नतीजा है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के जमाने में 80 परसेंट ग्रेजुएट, 80 परसेंट इंजीनियर जो बाहर जाते हैं वह कहीं बहाली होने के लायक नहीं हैं । उनमें क्षमता नहीं होती है । यूनिवर्सिटी में आपने बहाल किया, टीचर आपने बहाल किया मैं मुबारकबाद देता हूं लेकिन यूनिवर्सिटी में अभी भी जगह खाली पड़ी है अभी हाल ही में बहाल किया है आपने और यूनिवर्सिटी का जो मामला था यूजीसी के अख्तियारात को भी सरकार ने, केंद्र ने छीन लिया । यूनिवर्सिटी का काम था एजुकेशन की मॉनिटरिंग करना, उनको डेवलपमेंट करना, उनके रिसर्च का काम करना, बिहार में रिसर्च की हालत खराब है महोदय । आज यूनिवर्सिटी में, आज भी यूनिवर्सिटी एडॉप्ट चल रही है महोदय, माइनोरिटी का एक भी वाइस चांसलर कहीं नहीं है महोदय, मगध जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी, मजरूल हक यूनिवर्सिटी में रूटीन वर्क हो रहे हैं यह खेद का विषय है । इसके मायने सरकार एजुकेशन के बारे में गंभीर नहीं है । खुदाबख्स लाइब्रेरी में एनसेंट वर्ल्ड का पूरा बुक है वह बहुत सारे महतुतात हैं वहां पर मशरखी का मरकज है, वहां रवायती तौर पर उर्दू और अरबी का स्कॉलर होता था, वहां से अरबी उर्दू के स्कॉलर को आपने खत्म कर दिया और वहां पर आपने संस्कृत के स्कॉलर को बहाल कर दिया । माइनोरिटी एजुकेशन में आपकी इतनी दुश्मनी है कि उर्दू क्या मुसलमानों की जुबान है, उर्दू प्रेमचंद की भाषा है, उर्दू गालिब की जुबान है, उर्दू महेन्दर सिंह बेदी की जुबान है और उर्दू पर आपने बमबारी की है । 2020 तक उर्दू कंपल्सरी सब्जेक्ट थी लेकिन आपने नया मानक मंडल जो बहाली किया आपने 6+1 का, आपने शिक्षक मैथ का दिया, साइंस का दिया, सोशल साइंस का दिया, हिंदी का दिया, इंगलिश का दिया मेरे बच्चे हिंदी भी पढ़ेंगे...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : बैठे–बैठे नहीं बोलें माननीय सदस्य । आप बैठ जांय ।

श्री अख्तरूल ईमान : लेकिन उर्दू भी पढ़ाना है हमारे बच्चों को, नहीं साहब, हाउस को ऑर्डर में लिया जाय ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जायं । उनको बोलने दिया जाय ।

श्री अख्तरूल ईमान : लेकिन मानक मंडल में 799, 2020 के जरिए से...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : आपकी बारी आयेगी तो आप बोलेंगे ।

श्री अख्तरूल ईमान : आप उर्दू के महत्व को खत्म कर दीजिएगा, बिहार में दूसरी राजभाषा है उर्दू, उर्दू को जिंदा रहने देना है या नहीं देना है, फैसला करना पड़ेगा । किसी ने कहा है कि किसी भी कौम को मारना चाहो, उसकी गर्दन पर तलवार मत चलाओ, उसकी मातृ जुबान छीन लो । मातृ जुबान क्यों छीनना चाहते हैं?

(क्रमशः)

टर्न–19 / मुकुल / 19.02.2026

क्रमशः

श्री अखतरूल ईमान : बिहार की दूसरी राष्ट्रभाषा है, इस पर आप उर्दू को कम्पलसरी सब्जेक्ट के रूप में लाइए, हिन्दी भी पढ़ेंगे बच्चे और उर्दू भी पढ़ेंगे, आप उसको लाइये । मदरसों का हाल आपने बुरा कर रखा है, 2459 प्लस एक है 1637 में से 204 का पेपर जमा है, आप उनको तनख्वाह नहीं दे रहे हैं । 1128 में लैब हैं, लेकिन कोई लैब टेक्निशियन बहाल नहीं किया । जो टीचर रिटायर्ड हो गये हैं उनकी अंतरराशि आपने नहीं दी, मदरसे के बच्चों को आप मिड डे मील नहीं दे रहे हैं । तालीम मरकज और टोला सेवक का ट्रांसफर आपने कर दिया है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके पास बस एक मिनट का समय बचा है ।

श्री अखतरूल ईमान : सर, मेरे समय में तो हाउस आधा डिस्टर्ब ही रहा है । तालीम मरकज को बर्बाद कर दिया, ए0एम0यू0 सेंटर के लिए सरकार प्रस्ताव भेजे, बीएड कॉलेज और लॉ कॉलेजिज खोले जाएं । माइनॉरिटी के हॉस्टल्स में जोकि में पुलिस का कब्जा है, कोचाधामन में बने हुए हैं आज तक स्टार्ट नहीं हुआ है .....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बैठ जाएं ।

श्री अखतरूल ईमान : सर, एक मोहरमारी हाई स्कूल को अपग्रेड किया जाए ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री अखतरूल ईमान : सर, दो–तीन बातें हैं । ईद की छुट्टी सर, चांद पर ईद मनाते हैं हम । ईद के लिए एक दिन छुट्टी दीजिएगा सर, गया में कोई बहाल है सर, चांद आज निकला कि कल निकलेगा वह कैसे करेगा । ईद की छुट्टी

दो दिन किया जाए महोदय । बी0पी0एम0, डी0पी0एम0 की बहाली को निरस्त कर दिया गया, उसको लागू किया जाए ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बैठ जाएं ।

श्री अखतरूल ईमान : टीआरई–4 का इम्तिहान लिया जाए, डोमिसाइल पॉलिसी बंद किया जाए और माइनोरिटी स्कूल में टीचर बहाल किये जाएं और यह सरकार सुनिश्चित करे कि माइनोरिटी को पढ़ने का हक है कि नहीं यह बात करनी पड़ेगी ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री संदीप सौरभ जी । आपके पास एक मिनट का समय है। माननीय सदस्य, ईमान जी अब आप बैठ जाएं ।

(व्यवधान)

श्री संदीप सौरभ : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का जो यह शिक्षा बजट है.....

श्री अखतरूल ईमान : महोदय.....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ईमान जी अब आप बैठ जाएं । माननीय सदस्य, संदीप सौरभ जी आप अपना भाषण शुरू कीजिए ।

(व्यवधान जारी)

श्री संदीप सौरभ : महोदय, सरकार का शिक्षा बजट जो है वह हाथी का दांत है, जो खाने को है और दिखाने को कुछ और है । 20 प्रतिशत बजट का सरकार कह रही है कि हम शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन जब प्रति व्यक्ति खर्च की स्थिति आती है तो देश में सबसे निचले पायदान पर बिहार है । एक व्यक्ति के ऊपर सरकार 3500 रुपये खर्च करती है, राष्ट्रीय आंकड़ा 5 हजार का है । महाराष्ट्र में एक व्यक्ति पर 7 हजार खर्च हो रहा है, लगभग पॉपुलेशन इक्वल है । तमिलनाडु और केरल में लगभग 6 हजार खर्च है तो वहां सरकार फिसड्डी है और उच्च शिक्षण संस्थानों को जिस तरीके से सरकार बर्बाद कर रही है महोदय, नियुक्ति, नियंत्रण और पाठ्यक्रम तीनों स्तरों पर जबरदस्त तरीके से भगवाकरण, सेफनाइजेशन किया जा रहा है । केन्द्र सरकार कर रही है और उसकी मदद से बिहार के अंदर भी इसको किया जा रहा है, फीस वृद्धि, सीट कटौती, स्कॉलरशिप कटौती यह लगातार जारी है और अगर यही स्थिति रही तो देश के अंदर यूनिवर्सिटी का मतलब हो जायेगा गलगोटिया यूनिवर्सिटी, आज कल खूब चर्चित भी है तो सरकार को तय करना चाहिए कि उनको बेहतर सरकारी संस्थान चाहिए कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसे फर्जी संस्थान चाहिए । महोदय, दो मुद्दा हम रखना चाहेंगे, मंत्री जी के सामने भी दो मामला रखना चाहेंगे, एक तो है कि बिहार के तमाम जो छात्र हैं, अभिभावक हैं, टीचर हैं उनकी मांग है कि पहले की भांति सरकारी स्कूलों में शनिवार के दिन हाल्फ टाईम किया जाए, वह बहुत बड़ा सवाल हो चुका है, लोग बहुत परेशान हैं तो उनको हाल्फ टाईम के लिए आपलोग आदेश कीजिए, 2022 तक वह ठीक था, 2022 में अचानक से

के0के0 पाठक जी ने उसका हाल्फ टाईम खत्म कर दिया महोदय, उसको सरकार संज्ञान ले और उसको जल्द से जल्द कर दे । महोदय, मैं अपने क्षेत्र का मैटर एक रख दे रहा हूं ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बैठ जाएं ।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, पालीगंज के चिक्सी पंचायत के चिरैयाटाड़ गांव है, मोहनबिगहा गांव है, दोनों गांव से एक कि0मी0 से ज्यादा दूरी पर स्कूल है प्राथमिक विद्यालय, लेकिन सरकार अभी तक वहां पर प्राइमरी स्कूल नहीं खोली है दोनों गांव में और एक खनपुरा ताड़नपुर पंचायत के अचलटोला गांव में प्राथमिक विद्यालय नहीं है, इन तीनों जगह महोदय सरकार वहां पर प्राइमरी स्कूल खोल दे ताकि गांव के जो बच्चे हैं वे बेहतर तरीके से शिक्षा पाएं ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बैठ जाएं ।

श्री संदीप सौरभ : धन्यवाद महोदय ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार जी । आपके पास एक मिनट का समय है ।

श्री अजय कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा विभाग के बजट पर चर्चा हो रही है और जो कटौती प्रस्ताव लाया गया है मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं । देश के अंदर जो शिक्षा का साक्षरता का जो रेट है उसमें सबसे ज्यादा केरल का है और केरल का सबसे ज्यादा क्यों है इसके बारे में हमें विमर्श करना चाहिए । देश में केरल एक राज्य है जिसने शिक्षा को यू0जी0 से लेकर पी0जी0 तक पूरी तौर पर जो है उसने निःशुल्क किया है और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि 2020 की जो नई शिक्षा नीति लागू की गयी उससे बिहार के अंदर शिक्षा और महंगी हो गयी, 8 समेस्टर हो गये 4 साल में अब वह पूरे होंगे और एक सेमेस्टर फीस एक बच्चे को 3600 रुपये लगेंगे तो निश्चित तौर पर बच्चों की पढ़ाई में उसका ड्रॉप रेट बढ़ेगा, बिहार जैसे गरीब राज्य में यह बहुत मुश्किल होना है । इसीलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आज न सिर्फ जो है हायर एजुकेशन में जो है मेडिकल और टेक्नीकल की शिक्षा जो है उसके प्राइवेट इंस्टीच्युशन बने हैं....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कृपया शांति बनाएं, माननीय सदस्य बोल रहे हैं ।

श्री अजय कुमार : बल्कि उसके अंदर डोनेशन, कैपिटेशन फीस देकर के गरीब बच्चों की पढ़ाई उससे लाजिमी तौर पर दूर हो जा रही है और अब सरकार ने सामान्य शिक्षा प्रणाली में भी प्राइवेट इंस्टीच्युशन को लाने की जो बात कही है उससे और भी ज्यादा महंगी होगी सर । मैं दो–तीन बात कहकर के अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि बिहार के अंदर शिक्षा को हमेशा प्रयोग में बनाकर के क्यों रखे हुए हैं । आप चीन की बात कर रहे थे इधर से विनय जी, चीन की अच्छी बात क्यों नहीं लेते,

चीन में पूरी तौर पर सभी तरह की शिक्षा जो है वहां पर फ्री और मुफ्त है और चीन की जो शिक्षा है वह रोजगारोन्मुख शिक्षा है, वहां से जो बच्चे पढ़कर के निकलते हैं वह किसी के पास नौकरी के लिए हाथ पसारने के लिए नहीं जाते हैं तो बिहार के अंदर भी रोजगारों पर आधारित शिक्षा की व्यवस्था कर दीजिए न ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बैठ जाएं ।

श्री अजय कुमार : अगर हमको एडॉप्ट करना है तो उन सारी चीजों को.....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अजय बाबू आपका समय बीत गया, ज्यादा समय हो गया है ।

श्री अजय कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, बस एक बात कहकर के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा । बिहार के अंदर ट्रांसफर, पोस्टिंग का जो है, माननीय मंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि उसको थोड़ा व्यावहारिक किया जाए । महिलाएं जो हैं उनको आप 400 कि0मी0 दूर पोस्टिंग करते हैं, उनकी मां है, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं । दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि एरियर का जो मसला है, मैं आवेदन भी दिया हूं उसको पूरे बिहार के अंदर कहीं न कहीं उसका निष्पादन कर दिया जाए । यही कहते हुए मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता जी । आपके पास एक मिनट का समय है ।

श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता : धन्यवाद महोदय । सर, हमारे सर पर लिखा हुआ है एक मिनट, इसे हम जानते हैं । सर, मैंने दो दिन पहले माननीय मंत्री जी को कलस्टर किचन के माध्यम से गुणवत्ता खाने पर ध्यान आकृष्ट कराया था, इनका जवाब था सरकार का कि गरमा–गरम खाना और कल ही सर, हमको एक वीडियो आया है खजुरी मध्य विद्यालय, सहरसा से कि सारा खाना फेंका जा रहा है, मैंने उस वीडियो को मंत्री जी को भेजा भी है नंबर वन । Sir, I am not against the arrangement you made, i am simply urging you to take the corrective measure, that is my point. मैं सरकार के किसी चीज पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, आप सिर्फ corrective measure लीजिए That's what I am urging you. दूसरा सर, सहरसा में लगातार 20 वर्ष से एन0डी0ए0 का शासन है, भाजपा के जनप्रतिनिधि रहे हैं लेकिन कौन साजिश के तहत वहां से बीएड कॉलेज बंद, लॉ कॉलेज बंद, पी0एम0 श्री में दो स्कूल हुआ था चालू, वहां मुसलमान की बस्ती है सर, उर्दू मध्य विद्यालय है अभी तक वह पी0एम0 श्री में कवर्ड है लेकिन अभी तक उसको अपग्रेड नहीं किया गया है । एम्स को हटा दिया गया, इंजीनियरिंग कॉलेजिज को जमीन नहीं मिल रही है । सब

सहरसा के साथ ही हो रहा है हुजूर । दूसरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अर्ज करना चाहता हूं कि लाखों बच्चे आधार कार्ड नहीं बनने की वजह से न नामांकन ले पा रहे हैं स्कूल में और न ही उन्हें कोई योजना का लाभ मिल पा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना चालू कियी थी स्कॉलर के लिए पी0एच0डी0 वालों के लिए, नाम था मुख्यमंत्री शोध फेलोशिप योजना, उसमें 15 हजार रुपया महीने देने की बात हुई थी हमने पेपर में पढ़ा था सर, आज तक वह योजना पता नहीं लागू है या नहीं, बच्चे हमारे पास हैं लेकिन उनको मिला नहीं है और सबसे इम्पोर्टेंट माननीय मुख्यमंत्री जी बच्चे मैट्रिक एग्जाम दे रहे हैं.....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बैठ जाएं ।

श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता : सर, एक मिनट, दो मिनट के लिए उनको अंदर नहीं जाने दे रहा है, उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जा रही है, उसकी कोई सप्लीमेंट्री व्यवस्था करवाइये, यह मैं कहना चाहता हूं । बहुत–बहुत धन्यवाद, Thank You very much.

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री सतीश कुमार सिंह यादव जी । आपके पास एक मिनट का समय है ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय । माननीय शिक्षा मंत्री जी को हमारा कुछ सुझाव और मांग है । शारीरिक शिक्षा भी एक विषय है, इन्हें अनुदेशक नहीं शिक्षक के रूप में बहाल किया जाए एवं पूर्व में बहाल जो अनुदेशक हैं उन्हें राज्यकर्मी शिक्षक का दर्जा दिया जाए । साथ ही, राज्य के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा, कला, म्यूजिक एवं योगा के शिक्षकों की बहाली की जाए । राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा विभाग की स्थापना करते हुए इस विषय के प्रोफेसरों की बहाली की जाए । साथ ही, महोदय स्टेम प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए ए0पी0आई0 एकेडमिक परफोर्मेंस इंडिकेटर में शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र को हटाया जाए, क्योंकि बहुत से लोग फर्जी शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर के इसमें शामिल हो गये हैं और नौकरी कर रहे हैं, कई जगहों पर केस भी चल रहा है तो इसको हटाया जाए । साथ ही महोदय, स्टेम प्रोफेसर की बहाली से पहले नेट के तर्ज पर बिहार इलीजिब्लिटी टेस्ट बेट की परीक्षा कराई जाए । राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में वोकेशनल कोर्स में पी0एच0डी0 को शुरू कराया जाए, राज्य के विश्वविद्यालयों में पी0एच0डी0 के नामांकन के लिए पहले पी0ए0टी0 की व्यवस्था थी, पी0एच0डी0 एडमिशन टेस्ट जो अब खत्म कर दी गयी है, सिर्फ नेट वालों को एडमिशन मिल रहा है तो पी0ए0टी0 की व्यवस्था को फिर से लागू किया जाए बिहार के बच्चों के लिए । साथ ही महोदय जो

ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत स्नातक का नामांकन हो रहा है तो बच्चे और बच्चियां, खास करके छात्राओं को.....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बैठ जाएं ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : बगल में कॉलेज है और उनका 40 कि0मी0 दूर चला जा रहा है ।

क्रमशः

टर्न–20 / सुरज / 19.02.2026

(क्रमशः)

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : महोदय, यह पूरे बिहार की समस्या है, इसका निदान किया जाए । साथ ही...

उपाध्यक्ष : अब आप आसन ग्रहण करें ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : बस 30 सेकेंड महोदय । कुछ क्षेत्र की समस्या है । महोदय, हमारे क्षेत्र के प्रखंड–नुआंव में कुछ जगहों पर जैसे–हरियरपुल टोला, कलक का डेरा हो गया, श्रीरामपुर डेरा हो गया, लखनपुरा डेरा हो गया, रघुनाथपुर डेरा हो गया, सिराजपुर डेरा हो गया, वहां पर प्राथमिक विद्यालय नहीं है । कई बार जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखा गया है..

उपाध्यक्ष : अब आप बैठ जाएं माननीय सदस्य ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : जमीन का अभाव बार–बार कहा जाता है । साथ ही, दुर्गावती प्रखंड में कुछ जगह है, जहां पर विद्यालय नहीं है जैसे–सकीलीपुर है.. .

उपाध्यक्ष : अपना आसन ग्रहण करें माननीय सदस्य ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : कलबरिया है, खुटांहा है, बभनपुरा है, सारंगपुर है...

उपाध्यक्ष : अब आप बैठ जाएं माननीय सदस्य । माननीय सदस्य श्री रोमित कुमार जी ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : वहां प्राथमिक विद्यालय खोला जाए । धन्यवाद महोदय ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रोमित कुमार जी । आपके पास चार मिनट का वक्त है ।

श्री रोमित कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं अपने पार्टी हम(से0) के संरक्षक श्री जीतन राम मांझी जी तथा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संतोष सुमन जी का आभार प्रकट करता हूं । साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री और एन0डी0ए0 के सभी शीर्ष नेताओं को धन्यवाद अर्पित करते हुए सरकार के पक्ष में मैं अपना विचार रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यहां दो तरह की शिक्षा का जिक्र जरूरी है । कलम और लाठी का अंतर ।

एक ने बिहार को संवारा, तो दूसरे ने दी बस मजबूरी है ।

वो कहते थे– पढ़–लिखकर क्या करोगे ? बस चरवाहा विद्यालय जाओ,

कलम छोड़ो, हाथ में डंडा थामों और चरने का राग गाओ,

डिग्री तो बस नाम की थी, असली पढ़ाई तो गुंडई और रंगबाजी थी,
वो नेटवर्क नहीं जानते थे, वो रंगदारी का पाठ पढ़ाते थे,
और अपनी अनपढ़ टोली को ही प्रदेश का भविष्य बताते थे ।
नीतीश जी की शिक्षा ने जगाई, फिर से बिहार में नई आशा,
वो इंजीनियर का विजन लाए, वो टेक्नोलॉजी का जुनून लाए,
यहां अब चरवाहा विद्यालय नहीं, चाणक्य और आर्यभट्ट का सम्मान है,
वो गणित सिखाते थे अपनों को, कैसे करोड़ों का चारा डकारना है,
नीतीश जी ने सिखाया कि कैसे बिहार को सात निश्चय से संवारना है।

अध्यक्ष महोदय,

वो तबेले वाली शिक्षा थी, ये टेक्नोलॉजी वाला दौर है,
उनकी डिक्शनरी में विकास का मतलब सिर्फ अपना परिवार था,
नीतीश जी की डिक्शनरी में ये 13 करोड़ बिहारी हैं,

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या बातचीत नहीं करें ।

श्री रोमित कुमार : महोदय,

वो सड़क पर नाचते थे, ये सदन में नीति बनाते हैं,
यही फर्क है कि हम, नीतीश जी को विकास पुरूष कहते हैं ।

महोदय, विकास को नई रफ्तार मिले, इसके लिये मैं सरकार से...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बोल रहे हैं, कृपया शांति बनाये रखें ।

श्री रोमित कुमार : अतरी विधान सभा के कुछ मांगों पर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं –

मोहड़ा पंचायत के गहलौर में गरीबों के प्रेरणाश्रोत पर्वत पुरूष दशरथ मांझी जी के नाम पर महाविद्यालय या शोध केन्द्र की स्थापना की जाए जिससे उन्हें सच्ची श्रद्धांजली मिल सके ।

महोदय, मैं सदन के माध्यम से दो–तीन कोट बोलना चाहता हूं । जब गरीब के बच्चे अगर थोड़ी नकल कर के पास हो जाते हैं तो इसमें हर्ज क्या है ? बड़े लोगों के बच्चे तो ट्यूशन पढ़कर पास होते ही हैं ।

दूसरा, डिग्री जल्द लेकर भी क्या करोगे, चपरासी की भी नौकरी कहां है? पढ़–लिखकर क्या करोगे ? भैंस चराओ और लाठी मजबूत करो ।

महोदय, ये सारा जो स्टेटमेंट है वह जयप्रकाश नारायण यादव और रामचन्द्र पूर्वे जी, जो शिक्षा मंत्री उस समय के थे, उनका है । आप यह कोट देख लीजियेगा । इस पर हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी देते हुये कहा कि शिक्षा बिहार में कब्रिस्तान हो गया है । दूसरा, हाईकोर्ट का टिप्पणी आया कि यह

संवैधानिक विफलता है । एक बार कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि सरकार शिक्षकों को वेतन नहीं दे सकती है, तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिये क्योंकि यह राज्य चलाने में सक्षम नहीं हैं...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य को बोलने दिया जाए, वह कोर्ट का दे रहे हैं ।

श्री रोमित कुमार : हाईकोर्ट ने कहा कि अंधकार युग का राजा है । शिक्षा विभाग की फाइलों के गायब होने और भ्रष्टाचार पर कोर्ट ने सरकार को 'अंधकार युग' का प्रतीक बताया था । महोदय, उस समय अल्पसंख्यकों को केवल वोट बैंक समझा जाता था और...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : हम दिखवा लेंगे इसको ।

श्री रोमित कुमार : उनके मंत्री कहते थे कि मदरसों में कम्प्यूटर की क्या जरूरत है । हमने तुम्हें सुरक्षा दी है, अब और क्या तुम्हें चाहिये ?

नीतीश जी ने आज अल्पसंख्यक कल्याण का मतलब केवल नारा नहीं । हमने मदरसा शिक्षकों को सरकारी वेतन दिया, अल्पसंख्यक छात्रावास बनवाए और रोजगार के लिये ऋण उपलब्ध कराया । सुरक्षा के साथ सम्मान और समृद्धि नीतीश जी की पहचान है ।

90 के दौर में लघु जल संसाधन मंत्रालय का नारा था सिंचाई के नाम पर केवल कागजी घोड़ा दौड़ाते थे और अगर उनसे पूछा जाता था तो भगवान इन्द्र के भरोसे वह छोड़ देते थे ।

मंत्री कई बार स्टेटमेंट दिये हैं कि नहर की मिट्टी तो चूहे खा गए हैं, अब हम क्या करें । आज की सरकार ने महोदय, सात निश्चय के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना हमारा लक्ष्य है । सरकार ने पुराने नलकूपों को चालू किया और सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई पर जोर दिया । 2005 के पहले राशन कार्ड और अनाज वितरण में भारी भ्रष्टाचार था और संवेदनहीन बयानबाजी होती थी...

उपाध्यक्ष : आपका समय समाप्त हो गया माननीय सदस्य ।

श्री रोमित कुमार : वह कहते थे गरीब आदमी ज्यादा खाता नहीं है, वह अनाज का क्या करेगा...

उपाध्यक्ष : अब आप बैठ जाएं माननीय सदस्य ।

श्री रोमित कुमार : मंत्री जी का रूख हुआ करता था राशन और कालाबाजारी पर बयान आता था–अनाज सड़ रहा है तो सड़ने दो...

उपाध्यक्ष : अब आप बैठ जाएं ।

श्री रोमित कुमार : कम से कम चूहे तो खा रहे हैं । नीतीश सरकार में आज पी0डी0एस0 प्रणाली पूरी तरह से कम्प्यूटीरकृत हुआ है । वन नेशन, वन राशन कार्ड लागू हुआ है । गरीबों का उनका हक उनके द्वार पर मिल रहा है...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री रोमित कुमार : किसी बिचौलिए की हिम्मत नहीं है कि उनका अनाज डकार सकते हैं.. .

उपाध्यक्ष : कृपया आप बैठ जाएं ।

श्री रोमित कुमार : मैं सदन के माध्यम से राज्य सरकार के इन एतिहासिक प्रयासों का समर्थन करता हूं...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुजीत कुमार :

श्री रोमित कुमार : और विश्वास दिलाता हूं कि बिहार के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में उनकी पहचान स्थापित करेगा ।

श्री अजय कुमार : महोदय, माननीय जीतन राम मांझी जी की पार्टी से आते हैं तो पिछली बार टेकारी में अनिल बाबू को जीता दिये थे । इस बार भी माननीय जीतन राम मांझी, डी0एम0 साहब को अगर फोन कर देते तो जीत जाते । आज 2005 का यही नजराना है लोकतंत्र का नजराना है । यह जमाना है और 2005 के पहले की बात करते हैं कि क्या था । आज है कि दिन–दहाड़े जीत जाता है आदमी, फोन करिये डी0एम0 को, जीता देगा ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुजीत कुमार जी । गागर में सागर भरें ।

श्री सुजीत कुमार : बहुत आभार उपाध्यक्ष महोदय । शिक्षा के अनुदान बजट पर बोलने का अवसर आपने दिया...

उपाध्यक्ष : कृपया शांति बनाये रखें ।

श्री सुजीत कुमार : मैं आभार व्यक्त करता हूं, मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और अपने राजनगर विधान सभा क्षेत्र की महान जनता का, जिनके आर्शीवाद से मैं इस गरिमामयी सदन में पहुंचा । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब थोड़ी देर में विपक्ष के सदस्य वाक आउट करके जाने वाले हैं क्योंकि उनका समय हो चुका है...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अपनी बात रखें ।

श्री सुजीत कुमार : तो जाने के पहले...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आसन की ओर मुखतिब हों और अपनी बात रखें ।

श्री सुजीत कुमार : अभी जायेंगे आप, थोड़ी देर में, आपका समय हो गया । उनके लिये कह देना चाहता हूं कि...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : टोका–टोकी में आपका समय नष्ट हो जायेगा ।

श्री सुजीत कुमार : महोदय,

जो कल तक सोये रहें अंधेरों की गोद में,
आज उजालों पर सवाल उठा रहे हैं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा बजट पर सरकार के समर्थन में अपनी बात को रखने के लिये खड़ा हुआ हूं । जब शिक्षा के बजट पर बात करना हो तो थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शांति बनाये रखें, बैठे–बैठे न बोलें ।

श्री सुजीत कुमार : महोदय, बिहार केवल एक राज्य नहीं है, यह ज्ञान, तर्क और विश्वगुरू परंपरा की धरती रही है । नालंदा और विक्रमशीला ने दुनिया को बताया कि शिक्षा क्या होती है और सभ्यता कैसे आगे बढ़ती है । जिस धरती ने जग को ज्ञान दिया, उस धरती को अंधेरों में झोंक दिया गया । महोदय, गलती समय की नहीं थी, गलती उस सोच की थी जो उस समय सत्ता में बैठी थी ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम ईमानदारी से इतिहास को देखें तो लालू–राबड़ी जी के शासनकाल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह बदहाली का शिकार हो चुकी थी । स्कूल थे लेकिन पढ़ाई नहीं थी । विश्वविद्यालय थे लेकिन सत्र नहीं चलते थे । डिग्रीयां मिलती थी लेकिन ज्ञान नहीं मिलता था और योग्य छात्र पलायन करने को मजबूर थे...

उपाध्यक्ष : बैठे–बैठे नहीं बोले, माननीय सदस्य को बोलने दें ।

श्री सुजीत कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, कलम हाथ में थी लेकिन डर सिर पर था, कक्षा में सन्नाटा था और सत्ता में अराजकता थी । उपाध्यक्ष महोदय, उस दौर में शिक्षा सरकार की प्राथमिकता नहीं थी बल्कि राजनीति की बलि चढ़ गयी थी और बिहार को पिछड़ेपन का तमगा दे दिया गया था । लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतिहास हमेशा एक सा नहीं रहता । 2005 के बाद बिहार ने करवट ली । मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सिर्फ सरकार नहीं बदली, सोच बदली, शासन की संस्कृति बदली और सिस्टम बदला, और बदला खंडहरों को स्कूल बनाने का हौसला, अराजकता को अनुशासन देने की ताकत । यही सच्चे नेतृत्व की पहचान होती है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा को राजनीति नहीं राज्य और समाज निर्माण का आधार बनाया । महोदय, कोई भी शिक्षा व्यवस्था स्कूल, शिक्षा के बिना मजबूत नहीं हो सकती । विगत वर्षों में विद्यालय और उच्च विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई । लगभग 06 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की गयी। साईकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति और मध्याह्न भोजन जैसी योजनाओं ने नामांकन और उपस्थिति दोनों को बढ़ाया । बालिकाओं की शिक्षा में बिहार ने राष्ट्रीय स्तर पर मिसाल कायम की । इतना बड़ा परिवर्तन केन्द्र सरकार के सहयोग के बिना संभव नहीं था ।

(क्रमशः)

टर्न–21 / धिरेन्द्र / 19.02.2026

....क्रमशः....

श्री सुजीत कुमार : महोदय, इतना बड़ा परिवर्तन केन्द्र सरकार के सहयोग के बिना संभव नहीं था । यही वह दौर है जब देश को मजबूत और निर्णायक नेतृत्व मिला माननीय नरेन्द्र मोदी जी का नेतृत्व, जब दिल्ली मजबूत हुई तब बिहार को नई ताकत मिली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने बिहार को बोझ नहीं सभावनाओं का राज्य माना और नई शिक्षा नीति, 2020 के माध्यम से देश की शिक्षा व्यवस्था को रटंत से रिसर्च, डिग्री से स्किल और नौकरी से नवाचार की ओर मोड़ा गया । माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2005 से पहले बिहार में गिने–चुने इंजीनियरिंग कॉलेज थे । आज स्थिति यह है कि 38 से अधिक नए इंजीनियरिंग कॉलेज, 30 से अधिक पॉलिटेक्निक संस्थान खोले गये । इसका परिणाम हुआ कि अब तकनीकी शिक्षा राजधानी तक सीमित नहीं रही, अब तकनीकी शिक्षा जिलों तक पहुंची है । आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि बिहार में आई॰आई॰टी॰, पटना, आई॰आई॰आई॰एम॰, बोधगया, एम्स, पटना, एन॰आई॰टी॰, पटना, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, दक्षिण बिहार, गया, केन्द्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी, नालंदा विश्वविद्यालय (अंतर्राष्ट्रीय), कुछ सदस्य चर्चा कर रहे थे कि नालंदा विश्वविद्यालय में अब की क्या स्थिति है ? अभी भी आप चले जाइये, जा कर देख आइये, 19 देश के बच्चे आकर...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठे–बैठे नहीं बोलें ।

श्री सुजीत कुमार : महोदय, नालंदा में शिक्षा ग्रहण करते हैं और आक्रांताओं ने बख्तियार खिलजी ने उस समय आकर नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने का काम किया, उसके ज्ञान पर आक्रमण किया लेकिन वर्ष 2005 के पहले के शासन में जो थे वे खिलजी के ही अनुयायी थे जिन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने का काम किया । आई॰आई॰टी॰, भागलपुर जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थान स्थापित हो चुके हैं । जो सपना कभी डर में सिमटा था, वह आत्मविश्वास का उड़ान भरने लगा । महोदय, पहले छात्र बाहर जाते थे, आज संस्थान बिहार आ रहे हैं । महोदय, जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का विजन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सुशासन एक साथ जुड़ा तो बिहार की शिक्षा में ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ । माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार के छात्र यू॰पी॰एस॰सी॰, बी॰पी॰एस॰सी॰, नीट, जे॰ई॰ई॰ जैसी कठिन परीक्षाओं में देश भर में बिहार की डंका बजा रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, यह संयोग नहीं है, यह नीति, नीयत और नेतृत्व का परिणाम है । महोदय, वर्ष 2005 में जहां शिक्षा की बजट करीब 4 हजार करोड़ रुपये थी वहीं आज यह बढ़कर 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विद्यार्थी परिषद् का कार्यकर्त्ता रहा हूँ, मैं छात्र नेता रहा हूँ और जब हमलोग शैक्षणिक विषयों को लेकर आंदोलन करते थे तो नारा लगाते थे–

मांग सही है, शत प्रतिशत,
शिक्षा व्यय हो दस प्रतिशत ।

हमलोग उस समय सरकार से मांग करते थे कि पूरे बजट का 10 प्रतिशत शिक्षा का बजट होना चाहिए । आज मैं सौभाग्य से इस सदन का सदस्य हूँ और बिहार में हमारी सरकार है जो पूरे बजट का 20 प्रतिशत राशि शिक्षा पर खर्च कर रही है । महोदय, यह सरकार की नीति को स्पष्ट करती है । शिक्षा बजट की वृद्धि यह दर्शाती है कि शिक्षा अब केवल घोषणा नहीं है बल्कि निवेश की प्राथमिकता बन चुकी है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि उपलब्धियों के बावजूद चुनौतियां शेष हैं, शिक्षा की गुणवत्ता, शोध और नवाचार, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों तक समान अवसर पहुंचे । यह सरकार की आने वाले समय में प्राथमिकता में होनी चाहिए । अब विपक्ष सवाल करता है तो मैं उनसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिनके दौर में किताबें रोती थीं, वे आज ज्ञान पर भाषण कैसे दे सकते हैं, जिन्होंने अतीत को अंधेरे में छोड़ा, वे भविष्य पर सवाल कैसे उठा सकते हैं ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सच्चाई साफ है कि विपक्ष को शिक्षा की चिंता नहीं, सरकार की सफलता से परेशानी है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आग्रहपूर्वक, मंत्री जी जा रहे थे इंगलैंड, जापान घुमा रहे थे उनको बताना चाहिए कि बिहार में वर्ष 2005 से पहले का शासन । मैं दलित परिवार से आता हूँ और हमारा गांव है कसियोना, वहां चार सौ बस्ती हैं, आंकड़ों में मैं नहीं जाना चाहता हूँ जो प्रत्यक्ष हमने देखा, वर्ष 1995 का हमारा जन्म है महोदय और उस दौर में हमने जो देखा है, वर्ष 2005 से पहले तीन सौ से चार सौ परिवार की आबादी में मैट्रिक पास हुआ करते थे, आज स्थिति है कि लगभग साढ़े तीन सौ परिवार में स्नातक उत्तीर्ण छात्र हैं और आई॰आई॰टी॰, एन॰आई॰टी॰ जैसे संस्थान में दलित परिवार के बच्चे पढ़ रहे हैं, यह मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सुशासन में हुआ है । आपने तो जंगल राज खोलवा दिया, आपने तो चरवाहा विद्यालय खोलवा दिया, आप चरवाहा विद्यालय के प्रोडक्ट हैं...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठे–बैठे नहीं बोलें ।

श्री सुजीत कुमार : महोदय, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पियेगा, उतना दहाड़ेगा लेकिन आपने क्या किया, आपने चरवाहा विद्यालय खोलकर गरीब, दलितों को शिक्षा से वंचित करने का काम किया । आपको कभी भी आने वाले समय में एक गरीब दलित छात्र और उनके परिवार माफ नहीं करेंगे...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री सुजीत कुमार : महोदय, वर्ष 2001 में, ये केरल से तुलना कर रहे थे साक्षरता दर की...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बोल रहे हैं, आप बैठ जाएं । माननीय सदस्य, अपने मन से मत खड़ा हों ।

श्री सुजीत कुमार : महोदय, केरल से तुलना कर रहे थे साक्षरता दर की, वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार 47 प्रतिशत साक्षरता दर उस समय बिहार की थी....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जाएं, आपका समय हो गया ।

श्री सुजीत कुमार : महोदय, उस समय केरल की साक्षरता दर कितनी थी 90.2 प्रतिशत थी शिक्षा दर । आज जब आप देखेंगे वर्ष 2025 में हमारी सरकार है तो 47 प्रतिशत से ऊपर आकर बिहार की शिक्षा दर 74 प्रतिशत हो गई है...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बैठ जाएं ।

श्री सुजीत कुमार : महोदय, ज्यों–ज्यों साक्षरता दर बढ़ रही है, इनका कुमड़ा सीमट रहा है और....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती कोमल सिंह जी ।

श्री सुजीत कुमार : महोदय, मैं भविष्यवाणी करता हूँ आज इस सदन में कि बिहार की साक्षरता दर जब तक बढ़ेगी...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जाएं, आसन ग्रहण करें । माननीय सदस्या श्रीमती कोमल सिंह जी, अपना भाषण प्रारंभ कीजिये ।

श्रीमती कोमल सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाएं ।

श्रीमती कोमल सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आज आपने मुझे इस सदन में उस विभाग पर बोलने का अवसर दिया जो किसी भी राज्य की आत्मा होती है और किसी भी व्यक्ति के ग्रोथ में अहम भूमिका निभाती है । एक बच्चे के जन्म के समय से ही, अगर उस बच्चे के माता–पिता को अगर अपने बच्चों की सबसे ज्यादा चिंता होती है तो उसके शिक्षा की चिंता होती है और हर माता–पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले और वह बड़ा होकर अच्छी नौकरी या नाम कमा सके । रोटी, कपड़ा, मकान जितना जरूरी है शिक्षा का अधिकार भी उतना ही जरूरी है । महोदय, जब हम शिक्षा के ज्ञान की बात करते हैं, Not only in India, Bihar Education system was Globally recognized. यह भगवान बुद्ध और महावीर की धरती है, जिन्होंने अहिंसा और करूणा का पाठ पढ़ाया लेकिन महोदय, मैं यह सदन को याद दिलाना चाहती हूँ कि यह केवल दर्शन की भूमि नहीं है, यह विज्ञान की भी जननी है । इसी पाटलीपुत्र की मिट्टी पर बैठ कर महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने दुनिया को शून्य और डेसीमल सिस्टम दिया । महोदय, अगर बिहार ने शून्य नहीं दिया होता तो आज चांद और मंगल पर जाने की बात तो दूर, आज का यह डिजिटल युग और कंप्यूटर के कैल्कुलेशन भी संभव नहीं होते । यह नालंदा विश्वविद्यालय की पवित्र भूमि है जिस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आज दुनिया बड़े अदब से लेती है

उसकी स्थापना से 500 साल पहले हमारा नालंदा दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दे रहा था । यहां 10 हजार छात्र और 02 हजार शिक्षक दुनियाभर से आकर ज्ञान की साधना करते थे लेकिन एक कहावत है–'चिराग तले अंधेरा', जिस बिहार ने पूरी दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दिया, बड़े ही शर्म की बात थी कि उसी बिहार के बच्चों को पढ़ाई के लिए पलायन करना पड़ता था और उसकी वजह थी आर॰जे॰डी॰ का जंगलराज । जिस तरह 1190 के दशक में बख्तियार खिजली ने नालंदा को जलाया था, ठीक उसी तरीके से विपक्ष के कुशासन ने 90 के दशक में बिहार की प्रतिभा को जला दिया । इतिहास कहता है कि ज्ञान का मंदिर तीन महीने तक जलता रहा । खिजली ने सिर्फ किताबें नहीं जलायी, उसने हमारी सभ्यता को जलाने की कोशिश की, ठीक उसी तरीके से.. ..

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठे–बैठे नहीं बोलें, माननीय सदस्या को बोलने दें ।

श्रीमती कोमल सिंह : महोदय, और मैं इस सदन में पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ कि खिजली ने सिर्फ, कि जिस तरीके से खिजली ने...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, उनको बोलने दें ।

श्रीमती कोमल सिंह : महोदय, हमारी सभ्यता को जलाने का काम किया आर॰जे॰डी॰ के जंगलराज में बिहार के बच्चों के भविष्य को और उनकी शिक्षा को आग लगाने का काम किया । खिजली तो विदेशी थे, आपने तो अपने घर को जलाने का काम किया । जिन हाथों में कलम होनी चाहिए थी, उन हाथों में आपने कट्टा थमाने का काम किया । जहां स्कूलों में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान पढ़ाया जाना चाहिए था, वहां इन्होंने जातिवाद और अपहरण का पाठ पढ़ाने का काम किया...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, शांति बनायें, महिला सदस्या बोल रही हैं, इनको बोलने दिया जाय ।

श्रीमती कोमल सिंह : महोदय, लेकिन कहते हैं कि अंधेरा गहरा होता है तब सवेरा और करीब होता है । जिस तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुराने गौरव को...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप शांति बनायें ।

श्रीमती कोमल सिंह : महोदय, दोबारा स्थापित किया, ठीक उसी तरह उन्होंने बिहार की ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था को भी रिवाईज करने का काम किया, क्योंकि Right to Education is the Fundamental Right और इसकी इंपोर्टेंस को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भली–भांति समझा और बिहारियों के इस अधिकार को उन तक पहुँचाने का काम किया । हमारे मुख्यमंत्री जी का नाम ही नीतीश है, नीति के देवता, उन्होंने अपनी नीतियों से बिहार की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी है । वर्ष 2005 में बिहार में सरकारी स्कूलों की संख्या मात्र 54 हजार

थी वह बढ़कर 76 हजार हो गयी है । हमारी सरकार ने सिर्फ स्कूल ही नहीं बनाया, आई॰आई॰टी॰, पटना, आई॰आई॰आई॰एम॰, बोधगया, नये इंजीनियरिंग कॉलेजेज, मेडिकल कॉलेजेज और पॉलिटेक्निक कॉलेजेज बनाने का भी काम किया ।

....क्रमशः....

टर्न–22 / अंजली / 19.02.2026

(क्रमशः)

श्रीमती कोमल सिंह : मैं एक महिला हूं, इसलिए इस बात को और गहराई से महसूस करती हूं कि वर्ष 2006 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री साइकिल योजना शुरू की, तो वह सिर्फ एक योजना नहीं थी, वह एक सामाजिक क्रांति थी । नौवीं कक्षा की लड़कियों को पहले 2000 रुपए नगद और बाद में सीधे बैंक खातों में राशि दी गई, इस योजना का असर यह हुआ कि स्कूलों में लड़कियों की संख्या बढ़ी और ड्रॉपआउट दर कम हो गया । मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ साइकिल नहीं दी, उन्होंने बिहार की बेटियों के पैरों में गति दी, उन्होंने सपनों को उड़ान दी और बीस साल बाद वही बेटियां जब बड़ी हुईं, तो उन्होंने नीतीश कुमार जी को वोट दिया यह है सच्चा बदलाव । महोदय, आज बिहार अपने कुल बजट का...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, शांति बनाए रखें । टोका–टोकी नहीं करें ।

श्रीमती कोमल सिंह : 21.7 परसेंट शिक्षा पर खर्च कर रहा है जबकि देश के अन्य राज्यों का औसत मात्र 14.5 परसेंट है, यह साबित करता है कि हमारी प्राथमिकता क्या है ? बी0पी0एस0सी0 के माध्यम से तीन चरणों में 2 लाख 27 हजार 195 शिक्षकों को निष्पक्ष नियुक्ति की गई है । 28748 प्रधान शिक्षक और 4699 हेडमास्टर की बहाली हुई । केंद्र सरकार ने भी हमारे प्रयासों को सराहा है और राज्य में 17 केंद्रीय विद्यालयों को स्वीकृति दी है । उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना वरदान साबित हुआ है । 4 लाख रुपए तक का लोन इंट्रेस्ट फ्री दिया जा रहा है, अब तक 52616 आवेदनों के विरुद्ध 1812 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं और 1 हजार 2 करोड़ रुपए बच्चों के खातों में जा चुके हैं, यही कारण है कि आज बिहार विश्वविद्यालय परीक्षा समिति के सुधारों को Prime minister's awards for Excellence in Public Administration से नवाजा गया है, जो बोर्ड कभी लेट–लतीफ के लिए जाना जाता था, आज वह देश में सबसे पहले रिजल्ट दे रहा है । महोदय, अवसर बढ़े, आगे पढ़े के संकल्प के साथ आज बिहार के सभी 38 जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज और 46 पॉलिटेक्निक संस्थान चल रहे हैं । महोदय, समय कम है और उपलब्धियां अपार है, आज बिहार दौड़ रहा है, बिहार उड़ रहा है, हमारी सरकार ने जंगल राज के अंधेरों को चीरकर...

उपाध्यक्ष : अपना भाषण अब कंक्लूड करें माननीय सदस्या ।

श्रीमती कोमल सिंह : सुशासन का सूरज उगाया है । नेता प्रतिपक्ष एक दिन कह रहे थे और आज भी यहां पर बैठे एक सदस्य कह रहे थे कि हमारा बिहार फिसड्डी हो गया है, तो मैं उनको कहना चाहूंगी कि बिहार बिहारियों का स्वाभिमान है, इसलिए न बिहार कल फिसड्डी था, न बिहार आज फिसड्डी है और न बिहार कभी फिसड्डी होगा, फिसड्डी आपकी सोच है, जो बार–बार आप बिहार को उसी दलदल में घसीटने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिहार की युवा और बिहार की महिला आज दीवार बनकर आपके सामने खड़े होने का काम कर रही है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शांति–शांति । अब आप बैठ जाएं ।

श्रीमती कोमल सिंह : हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बिहार की मिट्टी को माथे का तिलक...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, अब आप बैठ जाएं । आपका समय हो गया ।

श्रीमती कोमल सिंह : बिहार की मिट्टी को माँ और बिहारियों को अपना परिवार समझ अपना पूरा जीवन बिहार को आगे बढ़ाने में समर्पित कर दिया । यह सरकार न रुकने वाली है, न झुकने वाली है, न थकने वाली है और हम आपको यह बता दें कि हम बिहार के खोए हुए गौरव को सिर्फ लौटाएंगे...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया आसन ग्रहण करें ।

श्रीमती कोमल सिंह : बल्कि इसे नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे, इसलिए विपक्ष की बेचैनी बढ़ रही है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा बिहार मुस्कुरा रहा है, इसलिए मैं विपक्ष को भी कहना चाहूंगी, जरा मुस्कुराइए, आप आज के बिहार में हैं । अंत में मैं चंद कविता कहकर अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगी–

''नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं,
जमीन पर चांद–सितारों की बात करते हैं,
जो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले,
भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं,
बड़ा हसीन है उनकी जुबां का जादू,
लगाकर आग बहारों की बात करते हैं,
मिली कमान, तो अटक गई नजरें खजानों पर,
नदी सुखाकर किनारों की बातें करते हैं ।''

बहुत–बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय ।

उपाध्यक्ष : अब आप आसन ग्रहण करें ।

श्री मनोज विश्वास : अध्यक्ष महोदय...

उपाध्यक्ष : बोलिए माननीय सदस्य ।

श्री मनोज विश्वास : महोदय, हम एक मिनट का समय लेंगे । हमारे यहां सरकार की जो स्कीम थी वह बहुत अच्छी थी, नवसृजित विद्यालय पूरा बिहार में चालू हुआ था, जो 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर में दो साल पूर्व में उसको दूसरा स्कूल में मर्ज किया गया है और वहां के जो बच्चे हैं वह सही टाइम पर स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, उस पर भी शिक्षा मंत्री जी ध्यान दिया जाए ।

उपाध्यक्ष : अब बैठ जाएं ।

श्री मनोज विश्वास : दूसरा, अभी पूरे बिहार में जो प्राइवेट स्कूल है, उसकी जो फी है, जो 200 रुपया से अधिक 6000 रुपया तक हो गया है,...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जाएं । आप काफी कुछ बोल चुके हैं ।

श्री मनोज विश्वास : उस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता जी ।

श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

आप घबराइए नहीं, अभी से आप बेचैन हो गए । आपकी बेचैनी अभी से बढ़ गई है हम समझ सकते हैं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना भाषण जारी रखिए । उधर मत देखिए । माननीय सदस्य, आसन की ओर मुखातिब हों । आपका समय बीत रहा है माननीय सदस्य ।

श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझको शिक्षा विभाग के वाद–विवाद में भाग लेने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं । साथ ही साथ, मैं अपने नेता एल0जे0पी0आर0 के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी एवं सदन में हमारे नेता राजू तिवारी जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं । महोदय, सदन में शिक्षा विभाग पर बहुत देर से वाद–विवाद हो रहा है । मैं आपको कुछ चीजें याद दिलाना चाहूंगा कि जब वर्ष 2005 में एन0डी0ए0 की सरकार बनी...

(व्यवधान)

अभी से बेचैन हो गए, जैसे ही हमने कहा, जब 2005 में एन0डी0ए0 की सरकार बनी, इनकी बेचैनी बढ़ गई । वर्ष 2005 में जब एन0डी0ए0 की सरकार बनी, तो आपको मालूम होगा कि यह चाणक्य की धरती है और जब इस चाणक्य की धरती पर दूसरे चाणक्य ने यहां की बागडोर संभाली तो शिक्षा को एक विभाग के रूप में और एक राजनीति के रूप में नहीं देखा, उसने शिक्षा को बिहार के विकास का नींव बनाने का काम प्रारंभ किया, वहां से यह सफर उन्होंने चालू किया, उसके पीछे मैं नहीं जाना चाहता हूं कि किस प्रकार से बिहार की शिक्षा की नीति थी और बिहार में क्या शिक्षा के विषय में हो रहा था, यहां सदन में बार–बार उसका जिक्र हो चुका है और उसका ही एक प्रतिफल

है कि यहां बड़े से बड़े लोग भी शिक्षा में नौवां पास नहीं कर पाते थे, ऐसी स्थिति बिहार में थी और शिक्षा को...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन की ओर मुखातिब हों । समय का अभाव है आपके पास में ।

श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता : महोदय, हम खड़े हुए और उन लोगों की बेचैनी बढ़ गई....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, टोका–टोकी नहीं करें ।

श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता : हम सोचे थे कि कुछ उन लोगों को बता दें । बता दें कि उन लोगों की क्या स्थिति थी । महोदय, वर्ष 2005 में जब नीतीश जी ने शिक्षा को चालू किया, शासन चालू किया, तो उन्होंने सबसे पहले बच्चियों को वर्ष 2006 में साइकिल और पोशाक देने का काम किया । आधी–आबादी जो हमारी शिक्षा से वंचित हो जाया करती थी, उसको विद्यालय कैसे लाया जाए और उसको किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जाए, ताकि हमारी आधी–आबादी पढ़ सके, उसके लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने शिक्षा में साइकिल और पोशाक देकर उन बच्चों को स्कूल में ले जाने का काम किया । मध्याह्न भोजन देकर, ये गरीबों की बात करते हैं, गरीब के बच्चे स्कूल आएं और वहां पढ़ें, इसके लिए उनलोगों ने मध्याह्न भोजन लागू किया और उनको मध्याह्न में भोजन मिला, जिससे वे बच्चे, गरीब के बच्चे स्कूल आना प्रारंभ किए और स्कूल जब आना प्रारंभ किए और जब शिक्षा में बढ़ोत्तरी होने लगी, तो हमारा जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर था, जर्जर था, संसाधनविहीन था वह कम पड़ने लगा और तब हमको जाकर माध्यमिक विद्यालयों को उच्च विद्यालय में परिणत करना पड़ा । हमने लगातार माध्यमिक विद्यालयों को उच्च विद्यालय में परिणत किया और जब उच्च से भी काम नहीं चला तो उच्च विद्यालय को हमने प्लस–2 में परिणत करने काम किया, यह हमारे काम का स्तर है और वहां भी हम रुके नहीं, पी0एम0 श्री0 ले आकर प्राइवेट स्कूल को टक्कर देने के लिए हमने अपने विद्यालयों का फिर से पुनः सृजन करना चालू किया और जब प्लस–2 पास करके बच्चे निकलने लगे और महाविद्यालयों की कमी होने लगी तो हमने संकल्प लिया कि पूरे प्रखंडों में हम डिग्री कॉलेज खोलने का काम करेंगे, यह है हमारे काम करने का तरीका और यह है हमारे काम करने का स्तर । महोदय, हम शिक्षा कैसे पहुंचा सकें, इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं । हमने प्रोत्साहन नीति लागू किया...

उपाध्यक्ष : अब आप बैठ जाएं ।

श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता : अभी तो भाषण चालू किए हैं ।

उपाध्यक्ष : टोका–टोकी नहीं करिए ।

श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता : प्रोत्साहन नीति ला करके बता रहे थे । दस हजार, पांच हजार...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य को बोलने दिया जाए । इनका समय समाप्त होने जा रहा है ।

श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो सुझाव देकर के अपनी बात समाप्त करूंगा । अब चूंकि आपका आदेश लगातार हो रहा है, एक सुझाव शिक्षा मंत्री जी को यह है कि जो आधारभूत संरचना से हम पहले स्कूल बाउंड्री, छोटे–छोटे शौचालय को स्कूल के स्तर पर निर्माण करा लिया करते थे, आधारभूत संरचना में उसका अब ग्लोबल, बड़ा टेंडर हो रहा है । जिससे वह ससमय नहीं हो पा रहा है । इसलिए इस पर एक बार विचार करने की आवश्यकता है और इसको फिर छोटे स्तर पर ले आने की आवश्यकता है । महोदय, दूसरा सुझाव क्योंकि लघु सिंचाई मंत्री जी बहुत देर से बैठे हुए हैं और उनके विभाग के बारे में कुछ बात नहीं हो रही है । मेरा एक आग्रह है लघु सिंचाई मंत्री जी से, क्योंकि खेती में पटवन के लिए नलकूप लगा कर के बिजली के माध्यम से लगातार सिंचाई हो रही है, जिससे सभी लोगों को सिंचाई उपलब्ध हो रही है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को भी और आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं । लेकिन आपसे आग्रह करना चाहता हूं..

उपाध्यक्ष : अब आप बैठ जाएं ।

श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता : महोदय, एक मिनट महोदय दिया जाए ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : आप शांति बनाये रखें ।

श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता : मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं चूंकि लगातार भू–जल गर्भ का दोहन हो रहा है, जिससे लगातार गर्मी के दिनों में जल का संकट उत्पन्न हो जा रहा है । आपसे आग्रह है कि वितरणी और उप–वितरणी जो भी अभी बंद पड़े हैं ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अब आप बैठ जाएं । माननीय सदस्य आपका समय हो गया है।

श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता : वितरणी और उप–वितरणी को चालू कराया जाए ताकि प्राकृतिक जल से सिंचाई का काम हो सके । बहुत–बहुत धन्यवाद । जय हिंद।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या सुश्री मैथिली ठाकुर ।

सुश्री मैथिली ठाकुर : सबसे पहले उपाध्यक्ष जी को आभार, आपने मुझे आज बोलने का समय दिया । अलीनगर की देवतुल्य जनता के हमर बहुत–बहुत धन्यवाद जे हमरा आशीर्वाद देलखिन और अपन खूब–खूब आशीर्वाद द क हमरा जिता क ई सदन के हिस्सा बनैलखिन ।

आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत–बहुत धन्यवाद, उन्हीं की प्रेरणा से मैंने राजनीति में अपना कदम रखा । हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही बिहार को संवारने में समर्पित किया, उनको बहुत–बहुत धन्यवाद ।

आज इस विधानसभा में खड़े होकर बोलना मेरे लिए बहुत, बहुत बड़ी बात है । यह सिर्फ एक भाषण नहीं है, यह उस बेटी का सपना है जो बिहार की मिट्टी में, मिथिला की मिट्टी में पली–बढ़ी, खेली–कूदी । मैं जानती हूं कि इस सदन में मुझसे कहीं अधिक अनुभवी, कहीं अधिक वरिष्ठ और कहीं अधिक परिपक्व नेता विराजमान हैं । विपक्ष के वे दिग्गज नेता, जिनकी राजनीतिक उम्र मेरी पूरी उम्र से बड़ी होगी, उन सभी के सामने बोलना भी मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है ।

अध्यक्ष जी, आज शिक्षा बजट पर चर्चा हो रही है तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं कि वह बिहार सभी को याद है, जब मैं उस समय को याद करती हूं तो मुझे महाभारत के धृतराष्ट्र का हस्तिनापुर याद आता है । जो बहुत बड़े वरिष्ठ और बहुत ही अनुभवी नेता रहे, बहुत ही अनुभवी राजा रहे, लेकिन वे अंधे थे और उससे भी बड़ी बात है कि वे देखना भी नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें हस्तिनापुर की चिंता नहीं, बल्कि दुर्योधन की चिंता लगी रहती थी। जब इस धरती की बेटियां स्कूल जाने से डरती थीं, जब सरकारी स्कूल के नाम पर सिर्फ टूटी–फूटी दीवारें, जब शिक्षक वेतन के लिए दर–बदर भटकते रहते थे, जब दोपहर का खाना नहीं मिलता था तो बच्चे भूखे पेट पढ़ने जाते थे और ज्यादातर तो जाते भी नहीं थे । जनता चिल्लाती रहती थी कि स्कूल में शिक्षक नहीं हैं, तो कानों पर पट्टी । जनता रोती रहती थी कि बेटी पढ़ नहीं पा रही है, तो आंखों पर पट्टी । जनता कहती रहती थी कि बिहार पिछड़ रहा है, तब भी इनका दिल नहीं पसीजा ।

बिहार में 2005 से पहले ऐसा ही अंधेरा था । स्कूल में ताले, पढ़ाई–लिखाई नहीं होती थी, बजट आता था लेकिन बच्चों तक पहुंचता नहीं था । रिपोर्ट में विद्यालय थे लेकिन जमीन पर घास उगती रहती थी । हमारे विपक्ष के माननीय साथी जो आज बड़ी गंभीर मुद्रा में यहां बैठे हुए हैं, आप सभी उस दौर के साक्षी रहे हैं । मैं यह भी कह सकती हूं कि आप सहयोगी भी रहे हैं । लेकिन हम उन्हें दोष नहीं देते हैं । हम तो बस इतना कहना चाहते हैं कि जो बीत गई सो बात गई, लेकिन इतिहास गवाह है । भले ही

बिहार की भोली–भाली जनता वह दौर भूल जाए, लेकिन इतिहास कभी नहीं भूल सकता है, न ही वह कभी माफ करेगा ।

वर्ष 2005 में एक नवोदय हुआ । नया सूरज उगा । माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, 2005 में बिहार की जनता ने एक ऐतिहासिक फैसला किया । उस फैसले का नाम था नीतीश कुमार । महाभारत में जब युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठे तो उनके राज में धर्म की स्थापना हुई, न्याय आया और प्रजा सुखी हुई । ठीक उसी तरह, जब नीतीश कुमार जी ने बिहार की बागडोर संभाली तो यहां सुशासन आया । जब मैं यहां इस विधानसभा में खड़ी हूं तो मेरे मन में एक श्लोक गूंज रहा है– तमसो मा ज्योतिर्गमय, अर्थात् अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो । यही बिहार रहा है, अंधकार से प्रकाश की ओर। भय से आत्मविश्वास की ओर । अपमान से सम्मान की ओर और जंगलराज से सुशासन की ओर ।

उपाध्यक्ष जी, नीतीश कुमार जी ने एक ऐसी योजना शुरू की जिसने पूरे देश को चौंका दिया । मुख्यमंत्री साइकिल योजना, जिसके बारे में सभी ने बात की है और मैं खासकर इसीलिए बोलना चाहती हूं क्योंकि मेरी आंखों देखी कहानी है । मेरे खुद के गांव में, जहां स्कूल के नाम पर कोई बात ही नहीं होती थी, और एकाएक साइकिल योजना जब शुरू हुई तो मेरे गांव की अड़ोस–पड़ोस की सभी दीदियों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया । विपक्ष के लोग तो इस योजना का मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन आज वही योजना पूरे देश के लिए एक मॉडल है ।

(व्यवधान)

सुनने में सरल लगती है, लेकिन इस साइकिल ने क्या किया, यह जरा सोचिए ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या बोल रही है । आप बैठ जाइये, आपको इनके भाषण के बाद बोलने के लिए वक्त दिया जाएगा ।

सुश्री मैथिली ठाकुर : बिहार के गांव में एक बाप था जो सोचता था कि बेटी को हम दूर दराज कैसे भेजें, स्कूल कैसे भेजें, रास्ता बहुत लंबा है, खतरा है, पैसे नहीं हैं। उस बाप की चिंता को नीतीश कुमार जी ने समझा और बेटी के हाथ में साइकिल थमा दी । उस साइकिल पर पहियों ने सिर्फ सड़क नहीं नापी, उन्होंने लाखों बेटियों का भविष्य नापा । ड्रॉपआउट दर गिरी, नामांकन बढ़ा और बिहार की बेटी ने कहा, हम भी पढ़ेंगे और हम भी आगे बढ़ेंगे ।

मैं भी उदाहरण स्वरूप बिहार के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में आज आप सभी के बीच में खड़ी हूं । अगर मैं 2005 को देख करके ध्यान करके 2005 से पहले की बात करूं, तो संभावना भी नहीं थी कि मैं यहां पर खड़ी होती या फिर कोई ऐसी उम्मीद मेरे अंदर जगती ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य शांति बनाये रखें ।

सुश्री मैथिली ठाकुर : बालिका साक्षरता 33 प्रतिशत मतलब तीन में से दो बच्चियां हमारी अनपढ़ रहा करती थीं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : टोका–टोकी नहीं करिए । माननीय सदस्या को बोलने दिया जाए ।

सुश्री मैथिली ठाकुर : उस दशकों की अव्यवस्था के कारणों ने न जाने कितनों की जवानी छीन ली, आप सभी तो उसके खुद साक्षी रहे हैं । लगभग दो दशक बिहार शिक्षा से वंचित रहा । कई पीढ़ियां इसका दंश आज भी झेल रही है ।

(व्यवधान)

बी0डी0ओ0 साहब आप खुद अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए कि मैं जो बोल रही हूं क्या वह झूठ है ? आप दिल पर हाथ रख के बोलिए । आप खुद अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : आप बैठ जाएं । बिना आसन की अनुमति के नहीं बोलिये ।

सुश्री मैथिली ठाकुर : उपाध्यक्ष जी, पढ़ाई तब भी होती है जब सुरक्षा होती है । हमारे नीतीश कुमार जी ने समझा कि बिहार के बच्चों को किताब के साथ–साथ सुरक्षा भी चाहिए । आप जानते हैं मैं एक कलाकार भी रही हूं । मैं जब पहले आती थी तो पहले की कहानियां सुनती थी, अरे बौआ पांच–छह बजे के बाद गाड़ी से नहीं जाय के छै, कतय जेबै, कार्यक्रम नहीं भ सकै छै । लेकिन अभी बिहार में हम रात–रात भर घूमते हैं, रात के तीन बजे मैं खुद दरभंगा से आई और पटना में अपने घर में पहुंची, बहुत सुरक्षित । महोदय, शराबबंदी से लेकर महिला सुरक्षा के लिए बड़े–बड़े कानून तक, हर कदम पर नीतीश कुमार जी ने. ..

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठे–बैठे नहीं बोलिये ।

सुश्री मैथिली ठाकुर : आप सुन तो लीजिए मेरी बात । बेटियों के पक्ष में खड़े होकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है । महोदय, आज जब मैं बिहार के सबसे युवा विधायकों में से एक इस सदन में खड़ी होकर के बोल रही हूं तो न जाने आपको क्यों इतनी दिक्कत हो रही है ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, अब मैं आज के बजट पर आती हूँ । मैं यहां पर बात करूंगी उस डबल इंजन की, जिसने बिहार की शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, अब आप अपना भाषण समाप्त करें ।

सुश्री मैथिली ठाकुर : महोदय, मुझे आंकड़ों पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे सभी साथियों ने बहुत ही जोरदार तरीके से ऑलरेडी अपनी बातें रख दी हैं । लेकिन मैं अपने क्षेत्र के कुछ जो स्कूल हैं, उसके ऊपर ध्यान देना दिलाना

चाहूंगी क्योंकि हमारे क्षेत्र के जितने भवन स्कूल में बने हैं, अब तो तेजी से इतने सारे स्टूडेंट्स रोल–इन कर रहे हैं कि हमारे लिए भवन की भी कमी हो रही है । इसीलिए मैं चाहूंगी कि जिस तरीके से शिक्षा के ऊपर बच्चों का भी इतना आकर्षण बढ़ते जा रहा है, लगातार सब लोग अपना दाखिला करवाते आ रहे हैं तो उस हिसाब से भवन के कमरे भी और बढ़वाए जाएं । जैसे कि किरतपुर में प्राथमिक विद्यालय, गड़ौल कन्या विद्यालय, कुमरौल विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय महथौर, मुसहरी, प्राथमिक विद्यालय पकड़ी, उच्च माध्यमिक विद्यालय महथौर हरिजन, ग्राम श्रीरामपुर टोले के दरगाह में जो कमरे हैं उन्हें और बढ़ाया जाएं ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, अब आप बैठ जाएं ।

सुश्री मैथिली ठाकुर : सकतपुर का विद्यालय, लगमा प्राथमिक विद्यालय ।

उपाध्यक्ष : कृपया अपना आसन ग्रहण करें ।

सुश्री मैथिली ठाकुर : बहुत–बहुत धन्यवाद ।

टर्न–24 / हेमन्त / 19.02.2026

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री नचिकेता जी।

श्री नचिकेता : बहुत–बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। सर्वप्रथम बिहार के मुख्यमंत्री जी, बिहार के वित्तमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि बिहार का यह शानदार बजट आप लोग लेकर आये हैं। किसी भी आदर्श राज्य के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य में वह राज्य कितना खर्च करता है, यह मानक होता है उस राज्य के विकास का। आज वित्तीय वर्ष 2026–27 में शिक्षा विभाग में 60,204 करोड़ और उच्च शिक्षा विभाग में 8,012 करोड़ रूपये, जो कि हमारे बजट का लगभग 20 प्रतिशत है। ये इन्होंने पेश करके एक मिसाल कायम की है कि बिहार की सरकार बिहार में शिक्षा के लिए कितनी कृत संकल्पित होकर काम कर रही है। हमारे साथियों को हमेशा बड़ा दर्द रहता है, ये बोलिए और ये नहीं बोलिए, 2005 से पहले मत बोलिए। जो करिएगा वो तो सुनना पड़ता ही है। हम लोगों को 2005 में जो बिहार मिला था, जो उजड़ा हुआ बिहार आपके नेता ने दिया। शिक्षा के नाम पर जो भद्दा मजाक करके आप लोग गए, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा में बिहार सबसे निचले पायदान पर हुआ करता था। हमारे यहां,...

(व्यवधान)

अरे बैठ जाइए, सुनिए पहले।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठे–बैठे नहीं बोलें।

श्री नचिकेता : पहले हमारे यहां प्राइमरी में ड्रॉपआउट रेट 12 प्रतिशत था और आज की तारीख में वो मात्र 1.72 प्रतिशत रह गया है, इस प्रकार से हम लोगों ने काम किया।

(व्यवधान)

सुन लीजिए, सब बर्बाद आप ही लोग करके गए हैं और उसका सुधार हम लोग कर रहे हैं और जादू की छड़ी किसी के पास नहीं हैं।

(व्यवधान)

सुन लीजिए, सब जवाब मिल जाएगा।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन की ओर मुखातिब हों।

श्री नचिकेता : उच्च शिक्षा के अंदर भी जो ड्रॉपआउट रेट था, उसको कम करने के लिए सरकार ने पूरी नीयत के साथ काम किया। 5 लाख शिक्षकों की बहाली की गई, उच्च शिक्षा संस्थानों के अंदर भी शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा रहा है। जनता के अंदर विश्वास कायम हो रहा है कि उच्च शिक्षा के अंदर भी बिहार के अंदर अच्छी शिक्षा दी जा सकती है और बच्चे उसमें लगातार बढ़ रहे हैं, और आने वाले समय में, आप दो से तीन साल में देखेंगे कि उच्च शिक्षा संस्थानों के अंदर भी हमारा ड्रॉप आउट रेट सबसे कम रहेगा। निश्चित रूप से,..

(व्यवधान)

अरे, अभी तो बहाली शुरू हुई है। आपको 15 साल मिले थे, 15 साल तो बर्बाद करने में लगाये।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप आसन की ओर मुखातिब होकर बोलें, उलझें नहीं।

श्री नचिकेता : एक काम बढ़िया नहीं किये, तो उसको फिर ठीक करने में भी समय लगता है। हमने अपने...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी खड़े हैं।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्य प्रथम बार जीत कर आए हैं, सदन में बोल रहे हैं और इधर भी प्रथम बार जीतकर आये हैं, वह भी बैठे–बैठे इतनी चर्चा करते रहते हैं। अगर आपके पास ज्ञान है, तो जब आपको बोलने का समय पार्टी देती है, तब अपने ज्ञान का परिचय दीजिए और बैठे–बैठे इस तरह से मत बोलिये। संदीप जी तो हमारे दूसरे टर्म के विधायक हैं, वह भी बैठे–बैठे बोलते हैं। चर्चा करने का आपको मौका मिलता है, तो चर्चा कीजिए और अपना ज्ञान माननीय उपाध्यक्ष महोदय को सुनाइये। बैठे–बैठे अपने ज्ञान का परिचय देकर माननीय सदस्य का समय बर्बाद मत कीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : बैठ जाइये, बैठ जाइये। बैठे–बैठे नहीं बोलना चाहिए। आप बिना आसन के आदेश के नहीं बोलें। आप समय बर्बाद मत कीजिए। अब बैठ जायें।

(व्यवधान)

कुछ सीखें इनसे। यह आपके सीनियर लीडर हैं।

श्री नचिकेता : उपाध्यक्ष महोदय, 1947 से लेकर 2005 तक बिहार के अंदर मात्र 54,000 विद्यालय थे और नीतीश जी के शासनकाल के अंदर, 20 वर्षों के अंदर वह 76,000 विद्यालय बने हैं, यह हमारी संकल्पता दिखाती है कि किस प्रकार से विद्यालय के अंदर शिक्षा का विकास करने का काम हमने किया है। 2005 में नीतीश जी जब गद्दी पर बैठे और बिहार के अंदर जो सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट था वह प्राइमरी स्कूल के अंदर से ही हम लोग देखते थे कि बच्चियां जो हैं, स्कूल छोड़कर चली जाती हैं, वह नहीं पढ़ती हैं। नीतीश जी की चिंता यह थी कि बच्चे किस प्रकार से स्कूल के अंदर आएंगे। उन्होंने खास कर ध्यान दिया कि बच्चियां सबसे ज्यादा स्कूल को छोड़ देती हैं और इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री साइकिल योजना शुरू की। उसका परिणाम दिखा, आप जाकर देखिए, इस बिहार के अंदर जहां बच्चियों की मात्र 63 प्रतिशत की पासिंग स्टेटस था, वह 91 प्रतिशत तक पहुंचा। यह नीतीश जी कुमार जी का काम करने का तरीका है।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपना भाषण कंक्लूड करें। आसन के पास समय का अभाव है।

श्री नचिकेता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं जानता हूं कि सरकार को भी अपना वक्तव्य देना है।

उपाध्यक्ष : एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री नचिकेता : शिक्षा विभाग को मैं बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस नई पारी के अंदर जो काम शुरू किए हैं, लोग इंतजार करते थे कि प्रखंड स्तर पर भी कॉलेजों का निर्माण हो और वह सरकार ने इस बार तय किया। आपने प्रखंड स्तर पर डिग्री कॉलेजों का निर्माण का काम तय किया है। यह सबसे बड़ा काम है।

उपाध्यक्ष : अब आप बैठ जायें।

श्री नचिकेता : आज हमारी बच्चियां इंटरमीडिएट करने के बाद भी हायर एजुकेशन के लिए कहीं नहीं जा पाती थीं, उनको छोड़ना पड़ता था। इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं मांग करता हूं, मैंने अपने क्षेत्र की कुछ मांगों को आपके सामने रख दिया है कि धरहरा के अंदर के0आर0एस0 प्लस टू विद्यालय में डिग्री कॉलेज खोला जाए। बहुत–बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती संगीता कुमारी। संक्षिप्त में अपनी बात रखें, समय का अभाव है।

श्रीमती संगीता कुमारी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार द्वारा लाए गए बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं और विपक्ष द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ी हुई। बहुत–बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपका बहुत–बहुत आभार, मुख्य सचेतक महोदय को

बहुत–बहुत आभार और माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपको बहुत–बहुत धन्यवाद दूंगी कि आपने वक्त दिया मुझे बोलने के लिए। मैं बहुत–बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मोहनिया विधानसभा की देवतुल्य जनता का, जिन्होंने मुझे इस सदन में भेजा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2005 में जब नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने सत्ता संभाली थी, तब स्कूल के बच्चों का ड्रॉप आउट रेट बढ़ गए था, शिक्षकों का मनोबल गिरा हुआ था, शासन प्रशासन की लचर व्यवस्था थी, अभिभावक डरे हुए थे, लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे थे, यह एक ऐसी कुरीति थी। उस समय एक ही कारण था, जो बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे थे, इसका मुख्य कारण यही था, अपहरण। यह एक ऐसी कुरीति थी जो बिहार की सभ्यता और संस्कृति को और शिक्षा को गर्त में धकेल रही थी। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सत्ता की, शासन की बागडोर संभाली, तब उन्होंने शासन और प्रशासन को चुस्त–दुरुस्त किया। विभिन्न योजनाएं चलाकर एक ऐसी व्यवस्था चलाई जिसने सकारात्मक माहौल बनाया। स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ गई। फिर बिहार की विरासत को बचाने के लिए निकल पड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी जानते थे कि शिक्षा को हथियार बनाए बिना बिहार की उन्नति असंभव है। संस्कृत में एक श्लोक कहना चाहूंगी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

''येषां न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः।
ते मर्त्यलोके भुविभारभूता, मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति।''

इसका अर्थ जिनको समझना है, वो समझ गए होंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, The symbol of knowledge Dr B.R. Ambedkar said- ''शिक्षा, वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा, वह दहाड़ेगा।'' किताबें खुद चुप रहती हैं, लेकिन जिसने पढ़ लिया, उसने लाइफ में बोलना और लड़ना सीख लिया। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का शिक्षा बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के उज्ज्वल भविष्य का रोड मैप है। शिक्षा विभाग राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं विद्यार्थियों के समग्र विकास हेतु प्रतिबद्ध है। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से राज्य के सरकारी, प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों में तीन चरणों में 227,195 विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की गई है। हजारों प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विश्वविद्यालयों के सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति से शिक्षा व्यवस्था को एक नई मजबूती मिली है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कक्षा एक से आठ तक के एक करोड़ 19 लाख बच्चों को निशुल्क पुस्तकें और अगले सत्र में 12 करोड़ 50 लाख पुस्तकों का वितरण किया जा रहा है। विभिन्न सरकार की बहुप्रतीक्षित योजनाएं –

छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल, प्रोत्साहन योजनाओं के तहत 2 करोड़ 20 लाख से अधिक लाभार्थियों को 4,755.21 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय 8,000 से 16,000 किया गया है। रात्रि प्रहरियों का मानदेय 5,000 से 10,000 किया गया है। माध्यमिक विद्यालयों में, मध्याह्न भोजन योजना के तहत कार्यरत रसोइयों का 3300 रूपया प्रतिमाह किया गया है। कहने का मतलब यह है कि सरकार किस तरह से सरकारी विद्यालयों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कर रही है। बिहार राज्य की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों को अधिकतम 4 लाख रूपये तक ब्याज रहित शिक्षा ऋण दिया जा रहा है। पटना विश्वविद्यालय, पटना और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को मॉडल विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने हेतु 100–100 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सात निश्चय–3 के तहत उन्नत शिक्षा, उज्ज्वल भविष्य का उल्लेख किया गया है।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, अपना भाषण कन्क्लूड करें।

श्रीमती संगीता कुमारी : प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलना, आदर्श विद्यालय खोलना।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये वही बिहार है जहां के महान शिक्षक चाणक्य ने खंड–खंड भारत को अखंड भारत बनाने का सपना देखा था और अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से अखंड भारत बनाया था।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

मैं एक चित्रण करना चाहती हूं पूरे बिहार का कि–

''चाणक्य की नीति हूं, आर्यभट्ट का आविष्कार हूं मैं,
महावीर की तपस्या हूं, बुद्ध का अवतार हूं मैं।
सीता की भूमि हूं, विद्यापति का संसार हूं मैं,
जनक की नगरी हूं, मां गंगा का श्रृंगार हूं मैं।
दिनकर की कविता हूं, रेणु का सार हूं मैं,
नालंदा का ज्ञान हूं, पर्वत मंदार हूं मैं।
वाल्मीकि की रामायण हूं, मिथिला का संस्कार हूं मैं,
पाणिनी का व्याकरण हूं, ज्ञान का भंडार हूं मैं।
राजेंद्र का सपना हूं, गांधी की हुंकार हूं मैं,
और गोविंद सिंह का तेज हूं, तो कुंवर सिंह की ललकार हूं मैं
जी, बिहार हूं मैं।''

बहुत–बहुत आभार।

अध्यक्ष : श्री ललित नारायण मंडल, आपको दो मिनट में अपनी बातों को रखना है ।

श्री ललित नारायण मंडल : धन्यवाद, आदरणीय अध्यक्ष महोदय । यहां पर शिक्षा विभाग द्वारा जो बजट है, उसके समर्थन में और कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने का मौका हमको मिला है । मैं इसके लिए अध्यक्ष जी आपका, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उपमुख्यमंत्री द्वय महोदय का, शिक्षा मंत्री का, श्रवण बाबू का और जल संसाधन मंत्री विजय बाबू का मैं शुक्रगुजार हूं कि हमको बोलने का मौका मिला । अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि बहुत पुराने समय से कॉलेज में हूं और देख रहा हूं उस जमाने को, हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री बोल रहे थे कि समय पर वेतन मिलता है । हमलोगों ने देखा है उस जमाने को जब 6–6 महीना दरमाहा नहीं मिलता था तो कॉलेज के जो शिक्षक थे, उनके बाल–बच्चे जो पढ़ते थे दिल्ली में, वे अपना सब चीज लेकर घर चले आए थे कि पैसा नहीं है तो कहां से पढ़ेगे और उस वक्त अणे मार्ग से जब हमलोग हड़ताल करते थे तो अणे मार्ग से कहा जाता था 'माल महाराज का, मिर्जा खेले होली' ये शब्द हमलोगों को सुनाया जाता था, हम शिक्षकों को, उच्च शिक्षा के शिक्षकों को सुनाया जाता था । हमारे जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, उस वक्त भी शिक्षक रहे हैं, उनको पता होगा । हम कहना चाहते हैं 2005 के लगभग में जो शिक्षा विभाग का बजट था, वह लगभग था 4 हजार 3 सौ 66 करोड़ का और आज का बजट जो है, वह लगभग 70 हजार करोड़ का है, कितना अंतर है । बजट जब रहेगा, तब शिक्षा का विकास होगा, तब बिहार का विकास होगा, तब जनता का विकास होगा । आप इसी बजट से अंदाजा कर सकते हैं । अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

बी0डी0ओ0 साहब, हम आपको टोकते नहीं हैं, आप हमको मत टोकिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया बैठकर मत बोलिए, संजय जी, संजय बाबू...

(व्यवधान)

आपलोग भी शांत रहें ।

श्री ललित नारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, अभी झारखंड में जो सरकार चल रही है, उनका शिक्षा के बजट में खर्च है मात्र 12 परसेंट, पंजाब में भी है 12 परसेंट और बिहार में हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा प्रतिशत खर्चा शिक्षा बजट पर 20 परसेंट वह बिहार में है, इसके लिए हम माननीय शिक्षा मंत्री को और अपने मुख्यमंत्री को और वित्त मंत्री को इसके लिए हमलोग धन्यवाद देते हैं कि आपने सचमुच में...

श्री चन्द्रशेखर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य प्रोफेसर रहे हैं...

श्री ललित नारायण मंडल : आप भी प्रोफेसर रहे हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति, शांति बनाए रखें ।

श्री ललित नारायण मंडल : आप सर बायलोजी के प्रोफेसर रहे हैं, हम जानते हैं । सर, आप बॉटनी के प्रोफेसर रहे हैं, हम फिजिक्स के प्रोफेसर रहे हैं इसलिए हमलोग एक–दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं । सर, आज हमारे शिक्षा मंत्री ने क्या नहीं किया, हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारे वित्त मंत्री ने क्या नहीं किया बिहार की शिक्षा के लिए । आज जाइए, पहले हमलोग अपने बचपन की याद करते हैं, हमारे गांव में मात्र चौथा तक की पढ़ाई होती थी स्कूल में और जब चौथा क्लास पास करते थे तो पांचवां क्लास में नाम लिखाते थे, 5 किलोमीटर दूर वहां मीडिल स्कूल हुआ करता था, जब सातवां पास करते थे तो वहां से फिर जाते थे 7 किलोमीटर हाई स्कूल की पढ़ाई करने के लिए, कितना कष्ट होता था बरसात में, धूप में, कभी–कभी जानवर हम बच्चों को रपेटते थे तो किसी तरह से हमारा जान बचा है, ऐसी–ऐसी घटनाएं घटी हैं । रास्ते में कभी सांप–बिच्छा मिल जाता था, उस जमाने को हमलोगों ने देखा है । आज हमारे शिक्षा मंत्री ने, हमारे मुख्यमंत्री ने क्या किया है, हर प्रखंड में, हर प्रखंड की बात छोड़ दीजिए, हर पंचायत में प्लस–टू स्कूल की स्थापना किया है। हम प्लस–टू स्कूल जाकर पढ़ते थे भागलपुर में...

अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें ।

श्री ललित नारायण मंडल : अपने यहां से 30 किलोमीटर दूरी पर । आज हमारे बच्चे 2 किलोमीटर नहीं, 1 किलोमीटर नहीं 50 मीटर की दूरी पर प्लस–टू की पढ़ाई करते हैं, ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं, ये हमारे मुख्यमंत्री हैं सर इसीलिए हम और ये कहना चाहते हैं, नियुक्ति की बात बहुत सारी बातें हुईं, नियुक्ति की बात तो हुई है, शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है और स्कूल में आज तो यह स्थिति है कि प्राइवेट स्कूल में अच्छा सा टीचर नहीं मिलता है, जो अच्छे टीचर प्राइवेट स्कूल में थे, सभी सरकारी स्कूल में आ गए हैं क्योंकि यहां पर वेतन मिलता है और हर पहली तारीख को वेतन मिलता है और प्राइवेट स्कूल वाले कहते हैं कि हमको कि सर, हमको टीचर नहीं मिलता है, आप पुराने विद्यार्थी को बताइए, किससे हम फिजिक्स पढ़ायें, किससे हम मैथमेटिक्स पढ़ावें, आज यह स्थिति कर दिया हमारे शिक्षा मंत्री ने, हमारे नीतीश कुमार ने, हमारे वित्त मंत्री ने ऐसा स्थिति कर दिया है बिहार में शिक्षा का । हम और कहना चाहते हैं, बहाली की बात तो बहुत हुई है, उस पर हम नहीं कहना चाहते हैं, मानदेय में भी वृद्धि हुई है । शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय 8 हजार से बढ़ाकर 16 हजार कर दिया है । हम अपने क्षेत्र में सुल्तानगंज, भागलपुर जिला की बात करते हैं तो लगभग विद्यार्थी सब हमारे विद्यार्थी हैं और मिलने आते हैं, कहते हैं सर, आपकी सरकार में तो हमको 8 हजार से बढ़ाकर 16

हजार कर दिया, हमारा घर का खर्चा चलता है इसके नीचे, इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री को और माननीय शिक्षा मंत्री को और वित्त मंत्री को बधाई देते हैं, वहां से हमको धन्यवाद देते हैं, हम अपने मंत्री जी को सुनाना चाहते हैं. ..

अध्यक्ष : कृपया आप समाप्त करें । कृपया समाप्त करें ।

श्री ललित नारायण मंडल : मध्याह्न रात्रि प्रहरियों का भी मानदेय 5 हजार से बढ़ाकर 10 हजार कर दिया गया । मध्याह्न भोजन के रसोइयों का वेतन मानदेय 1650 से बढ़ाकर 3300 कर दिया गया...

अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें मंडल जी ।

श्री ललित नारायण मंडल : जी सर । बहुत सारी बातें हैं जो आपको बताया गया है, हम उस समय थोड़ा सा...

अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें ।

श्री ललित नारायण मंडल : एक मिनट महोदय । हर प्रखंड में अब एक कॉलेज की स्थापना की बात हुई है । हम अपनी बात थोड़ा सा हम अपने शिक्षा मंत्री से करना चाहते हैं सर । आप हमेशा हमको मदद किए हैं । हमारे कॉलेज में, जहां पर हम शिक्षक रहे हैं, आपने कॉमर्स की पढ़ाई शुरू की है, वहां ऑनर्स की पढ़ाई शुरू हुई है और उसका फायदा आपको मिला है, एन0डी0ए0 को मिला है, हमको फायदा मिला है और क्षेत्र की जनता कहती है कि आपका शिक्षा मंत्री ऐसा है कि हमारे यहां साईंस का और आर्ट्स की पढ़ाई होती थी, आपने कॉमर्स की पढ़ाई करा दिया और गरीब लड़के अब कॉमर्स की पढ़ाई वहां पर करते हैं, शिक्षक बहाल हो गया, इसके लिए हम बहुत–बहुत आपको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं सर...

अध्यक्ष : श्री अरूण कुमार ।

श्री ललित नारायण मंडल : हम कहना चाहते हैं सर कि पी0जी0 की पढ़ाई मुरारका कॉलेज में शुरू हो जाए और फायदा होगा, हमारे शाहकुंड प्रखंड में एक अंगीभूत कॉलेज खोला जाए और...

अध्यक्ष : बैठ जाइए अब, सारी बातें आ गईं ।

श्री ललित नारायण मंडल : सर, एक अंतिम बात कहना चाहते हैं कि अंगिका हमलोगों की बोलचाल की भाषा है, अगर संभव हो तो हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि अगर संभव हो तो अंगिका को आठवीं अनुसूची में डालने का कोशिश कीजिएगा और अंत में सबको बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं । जय बिहार ।

अध्यक्ष : श्री अरूण कुमार ।

श्री अरूण कुमार : अध्यक्ष महोदय जी, धन्यवाद करते हैं अपने प्रधानमंत्री जी का, धन्यवाद करते हैं अपने शिक्षा मंत्री जी का, धन्यवाद करते हैं अपने मुख्यमंत्री जी का, धन्यवाद उपमुख्यमंत्री सम्राट जी का, धन्यवाद करते हैं अपने उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी का, धन्यवाद करते हैं शिक्षा मंत्री जी का, धन्यवाद करते हैं

विजय चौधरी जी का एवं धन्यवाद करते हैं पूरे एन0डी0ए0 का, जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं । मैं धन्यवाद देता हूं अपने विधायक दल के नेता को, राजू तिवारी जी को मैं धन्यवाद देता हूं, बड़े भइया रितुराज जी को मैं धन्यवाद देता हूं । सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की देवतुल्य जनता को जिन्होंने मुझे इस सदन में एक–एक वोट देकर पहुंचाने का काम किया ।

...क्रमश...

टर्न–26 / यानपति / 19.02.2026

(क्रमशः)

श्री अरूण कुमार : अध्यक्ष महोदय, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा देनेवाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं जो हमें इस सदन में पहुंचाने का काम किए हैं । अध्यक्ष महोदय जी, शिक्षा विभाग पर बोलने का मौका मिला, शिक्षा विभाग पर खुला खजाना बिहार सरकार ने पेश किया इतिहास का सबसे बड़ा बजट । इस बजट में 3.47 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रावधान किया गया है जिसमें शिक्षा विभाग के लिए 68216 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं । इस बजट का मुख्य उद्देश्य बिहार को एक विकसित राज्य बनाना है । इस उम्मीद और विश्वास के साथ इस बजट का समर्थन करता हूं । अध्यक्ष महोदय जी, शिक्षा केवल एक विभाग नहीं है बल्कि समाज निर्माण की नींव है और आज मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमारी एन0डी0ए0 सरकार ने बिहार में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम उठाये हैं । अध्यक्ष महोदय जी, सरकार द्वारा विद्यालय में भवन निर्माण, अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, शौचालय, पेयजल, बिजली, स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय जैसी बुनियादी सुविधाओं में...

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें ।

श्री अरूण कुमार : में तेजी से किया गया है । अध्यक्ष महोदय जी...

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें । श्री आलोक कुमार सिंह ।

श्री आलोक कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हूं । सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, उपमुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, अब 2005 से पहले नहीं कहना है, मुझे यह कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के शासनकाल के पहले, माननीय महोदय, हम सब जानते हैं कि 2005 से पहले बिहार की शिक्षा व्यवस्था किस हालत में थी । उस दौर में स्कूलों में शिक्षक नहीं थे, भवन नहीं थे, बच्चों के हाथ में किताबें नहीं थीं और सबसे बड़ी बात व्यवस्था में विश्वास नहीं था । बी0डी0ओ0 साहब को

हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने, आपको जब बोलना हो तो एक बार पूरा दिन सदन का ले लीजिए, बीच में बोलने से बहुत नहीं बन जायेंगे । सदस्य, अगर पहली बार आप भी जीतकर आए हैं...

अध्यक्ष : आलोक जी, आप बोलिए ।

श्री आलोक कुमार सिंह : हम भी पहली बार जीतकर आए हैं । अगर आपको समय मिले तो बोलिए ।

अध्यक्ष : आप सीधे बोलिए, सदन में ।

श्री आलोक कुमार सिंह : उस समय बिहार में शिक्षा व्यवस्था की पहचान कई जगहों पर स्कूल से नहीं बल्कि तथाकथित चरवाहा विद्यालय से होती थी । जहां बच्चों की पढ़ाई की बजाय सिर्फ नामांकन की सूची में होते थे और शिक्षा का स्तर मजाक बनकर रह गया था । यह वही दौर था जब गरीब परिवार का बच्चा सोचता था पढ़ भी लें तो क्या होगा । आज का बिहार शिक्षा का नया युग, अध्यक्ष महोदय, आज बिहार बदल चुका है । आज शिक्षा व्यवस्था का अर्थ है स्कूलों में सुधार, तकनीक का उपयोग, छात्राओं को प्रोत्साहन और युवाओं के लिए शिक्षा के नये अवसर । यह परिवर्तन केवल योजनाओं से नहीं, राजनीतिक इच्छाशक्ति, माननीय नीतीश कुमार जी की देन है कि 2005 के बाद शिक्षा में बहुत परिवर्तन हुआ । बजट 2026–27 की प्रमुख घोषणा शिक्षा विभाग, माननीय अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा विभाग का गठन राज्य में उच्च शिक्षा को गुणवत्तापूर्वक बनाने हेतु एक नया उच्च शिक्षा विभाग बनाया गया है । स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आज हर परिवार, गरीब परिवार के भी बच्चे, छात्र, नौजवान जो पढ़ने के लिए आर्थिक स्थिति से मजबूर रहते थे, आज उनको स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत पैसा मिलने के कारण, माननीय मुख्यमंत्री जी का यह था, जिससे कि आज बिहार में चाहे एम0बी0ए0 हो या मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, सब डिपार्टमेंट में आज इस योजना का लाभ मिलता है । विश्वविद्यालयों का आधुनिकीकरण, पटना विश्वविद्यालय, मिथिला विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों का मॉडल विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने की दिशा में नई पहल की गई है । सात निश्चय–3 के तहत हर प्रखंड में आदर्श विद्यालय, नये कॉलेज और शिक्षा संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने की योजना आगे बढ़ रही है । बालिका शिक्षा और महिला सशक्तीकरण में आज बिहार की बेटियां केवल स्कूल नहीं जा रही हैं, ये बिहार का भविष्य लिख रही हैं । बालिका प्रोत्साहन योजना के माध्यम से हजारों करोड़ की सहायता सीधे छात्राओं तक पहुंची है, यह एक सामाजिक परिवर्तन है । कई साथियों ने, पूर्व के साथियों ने यह बोला कि 2006 में माननीय मुख्यमंत्री जी की जब साईकिल योजना की शुरूआत हुई तो आज कई बेटियां, हजारों बेटी की संख्या बढ़ी और बिहार का एक नया कीर्तिमान लिखा और समापन में मैं अपने विधान

सभा दिनारा विधान सभा में शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हाई स्कूल में, सात वर्ष पुराना स्कूल है, इस स्कूल में हिमांशु नाम का लड़का 2020 में मैट्रिक में टॉपर स्टुडेंट हुआ था पूरे बिहार में । स्कूल का आधे से ज्यादा कमरा 60 साल से पुराना, खपरे से बना हुआ है । माननीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इसपर जरूर ध्यान दें और बिल्कुल आपका काम भी हर दिनारा विधान सभा में, मैंने हर स्कूल में, चूंकि वहां के स्थानीय विधायक हाई स्कूल के अध्यक्ष होते हैं तो राज्य की सरकार का सराहनीय कार्य भी हुआ है, उसमें छूटा हुआ है, दूसरा आज लघु सिंचाई, जल संसाधन विभाग का भी इसमें वाद–विवाद कर, मैंने देखा तो लघु सिंचाई मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि गिरधरिया दिनारा प्रखंड में गिरधरिया गांव है उसके अगल बगल में करीब 20 गांव में एन0एच0 के बन जाने से वहां नदी में पुल नहीं बना जिसके कारण 2 हजार बीघा आज भी जमीन वहां पानी से भर जाता है इसलिए लघु सिंचाई मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उसको विशेष रूप से देख लें ।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें ।

श्री आलोक कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, अंत में राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से शिक्षा बजट के अनुदान की मांग को मैं समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री रामविलास कामत ।

श्री रामविलास कामत : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में शिक्षा के बजट पर जो सरकार के द्वारा लाई गई है उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । आपने मुझे समय दिया आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बात रखने के लिए समय दिया है । मैं अपने नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, मैं अपने आदरणीय नेता वित्त मंत्री श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव जी का, माननीय मंत्री श्रवण जी का और एन0डी0ए0 के सभी नेताओं के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं । अध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात कहने का मुझे मौका मिला है । मैं अपने विधान सभा पिपरा की महान जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं उनको भी प्रणाम करना चाहता हूं जिन्होंने दूसरी बार मुझे इस सदन में भेजने का काम किया है ।

अध्यक्ष : अपना सुझाव संक्षिप्त में रखिए ।

श्री रामविलास कामत : महोदय, शिक्षा के बजट के बारे में जो हमारे माननीय वित्त मंत्री जी बजट पेश किए हैं इस बार तो उस बजट में जिस तरह से शिक्षा और 20 प्रतिशत से अधिक की राशि बजट में प्रावधान किया गया है यह सरकार की मानसिकता को दर्शाता है, सरकार की सोच और उनके क्रियाकलाप को दर्शाता है, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं वित्त मंत्री जी के प्रति जिन्होंने शिक्षा पर इतने बजट को उन्होंने स्वीकृति दी है । महोदय, चर्चा हो रही है

शिक्षा विभाग पर और शिक्षा विभाग में बहुत सारे काम हुए हैं, प्राथमिक विद्यालय से लेकर के मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय और अन्य शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हुए हैं, उनके आंकड़े में मैं नहीं जाना चाहता, मैं कुछ बातें जो इस बजट में अभी वित्त मंत्री जी के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया था महोदय, उसमें पांच मूल मंत्र बताए गए थे । वो पांच मूल मंत्र जिसको मनन करने से चिंतन करने से इस बजट के महत्व को समझा जा सकता है । पहला मंत्र हमारे वित्त मंत्री जी बताए थे कि यह जो बजट है...

अध्यक्ष : अपना सुझाव दे दीजिए आप ।

श्री रामविलास कामत : वह बजट ज्ञान का बजट है, विज्ञान का बजट है, ईमान का बजट है, यह बजट अरमान का बजट है, सम्मान का बजट है ।

(क्रमशः)

टर्न–27 / मुकुल / 19.02.2026

क्रमशः

श्री रामविलास कामत : बजट में पांच मूल बातें हैं ज्ञान, विज्ञान । अगर महोदय, इन बातों पर चर्चा की जाए कि ज्ञान के लिए क्या आवश्यक है किस तरह से बिहार के बच्चों का ज्ञानवर्धन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको बेहतर शिक्षा व्यवस्था देने के लिए किस तरह से वैज्ञानिक तरीके से उनको पढ़ने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या–क्या उपाय किये जा सकते हैं, इन सारी बातों को इस बजट में प्रावधानित किया गया है अध्यक्ष महोदय । मैं अगर अभी चर्चा करूं प्राथमिक विद्यालय के बारे में हमारे विरोधी दल के बहुत सारे सदस्य अपनी बात बोले हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में बोलें क्योंकि सरकार का उत्तर भी होगा ।

श्री रामविलास कामत : महोदय, एक–दो बातें जो जरूरी महसूस होती है, ये विरोधी दल के नेता अभी कुछ दिन पहले 2025 के नवंबर में हमलोग चुनाव में गये थे, 17वीं विधान सभा का जो अंतिम सत्र महोदय चल रहा था उस सत्र में जो हमलोगों ने देखा, जो महसूस किया था कि किस तरह से एस0आई0आर0 के नाम पर इस सत्र में विरोध जताया जा रहा था, किस तरह के कारनामे किये जा रहे थे वह किसी से छुपा हुआ नहीं है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपलोग जो हमेशा कहा करते हैं कि इस बार लोकतंत्र में लोक हार गया और तंत्र जीत गया, इसी को मैं बताना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में बता दीजिए ।

श्री रामविलास कामत : महोदय, जब एस0आई0आर0 का मुद्दा सदन में चल रहा था, बहुत थोड़ा, थोड़ा सा समय हम लेना चाहते हैं महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बता दीजिए ।

श्री रामविलास कामत : और यहां से जब 17वीं विधान सभा का अंतिम सत्र समाप्त हुआ तो ये लोग चले गये रोड पर, रोड शो करने के लिए गये थे एस0आई0आर0 का मुद्दा लेकर के । राहुल गांधी जी दिल्ली से आये थे, प्रियंका जी आयी थीं सभी लोग यहां रोड पर घूमने के लिए आ गये थे लेकिन महोदय इन लोगों को लोगों से भेंट नहीं हो रहा था । लोगों को यू0पी0 से बुलाना पड़ रहा था, झारखंड से लोगों को लाकर के रोड पर खड़ा करना पड़ रहा था । महोदय, यह देखी हुई बात है । लोग इनलोगों के पास नहीं थे और ये लोग कहते हैं कि लोक हार गया और तंत्र जीत गया । अरे तंत्र आप खोजते रह जाइयेगा, आपको मौका मिलने वाला नहीं है । महोदय, चर्चा होती है न अभी, चुनाव की अगर चर्चा करें चुनाव के वक्त में एक गाना हिट हुआ था....

अध्यक्ष : आप गाना गा दीजिए ।

श्री रामविलास कामत : वह गाना था कि मोदी और नीतीश जी की जोड़ी हिट हो गयी । महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब यह गाना किसी दलित, महादलित, अत्यंत पिछड़ा के मोहल्ले में बजना शुरू होता था महोदय तो सभी महिलाएं, पुरुष, बच्चे निकलकर के नाच करना शुरू कर देते थे महोदय, कई वीडियो क्लिप हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जब किसी दलित, महादलित के मोहल्ले में जाते थे तो लोग इनसे भेंट नहीं करते थे, सन्नाटा छा जाता था महोदय, देखी हुई बात है । लोकतंत्र में लोगों से मिलने की आदत डालिए, लोगों से स्नेह करने की आदत डालिए तब आप तंत्र को खोजिएगा । महोदय, एक बात जो 2006 से जो माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा के क्षेत्र में साइकिल देकर के...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया आप अपना भाषण समाप्त कीजिए ।

श्री रामविलास कामत : पोशाक देकर के, बेटियों को बढ़ावा देकर के जिस तरह से आगे बढ़ाया उसका नजारा तो इस बार महोदय दिखाई पड़ा चुनाव में ।

अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें ।

श्री रामविलास कामत : महोदय, हमलोग जिस मोहल्ले में जाते थे, गरीबों के मोहल्ले में तो कई महिलाएं जब समझती थीं कि ये एन0डी0ए0 के उम्मीदवार हैं तो महोदय, बाहर निकलकर के आती थीं, कुर्सी लेकर के बैठते थे और वे महिलाएं बताया करती थीं कि आज से 20 वर्ष पहले जब हम 10वीं क्लास में पढ़ते थे, 11वीं क्लास में पढ़ते थे, नीतीश जी किस तरह से हमको आगे बढ़ने का मौका दिये थे किस तरह हम आगे बढ़कर के यहां तक पहुंचे हैं, नौकरी में आये हैं, दरोगा बने हैं, पुलिस बने हैं, सरपंच बने हैं, मुखिया बने हैं सभी महिलाएं बैठकर के बताया करती थीं महोदय । यह नीतीश जी के नेतृत्व का, नीतीश जी की नीति का और शिक्षा को बढ़ावा देने का ही संकल्प है कि आज महिलाएं आगे बढ़ी हैं और आगे बढ़कर अपना अधिकार भी ले रही हैं, लड़ना भी सीख रही हैं और लड़कर के आगे बढ़ना भी सीख रही हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाएं ।

श्री रामविलास कामत : यह बिहार की शिक्षा नीति का कमाल है तो महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं इस बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं ।

सरकार का उत्तर

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री शिक्षा विभाग।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम शुक्रगुजार हैं आपके प्रति कि आपने हमें बजट से संबंधित बातों को सदन में रखने का मौका दिया । हम माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी अपना आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने हमें दोबारा शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है और भोरे की जनता के प्रति भी अपना आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने दोबारा अपने प्रतिनिधि के रूप में हमें इस सदन में भेजा है । अध्यक्ष महोदय, सभी चर्चा के दौरान मैं सभी की बातों को गौर से सुन रहा था और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने सकारात्मक अपने विचार रखें, हम उम्मीद करते थे कि विपक्ष के हमारे साथी और कुछ सकारात्मक बातें कहेंगे लेकिन शायद उनकी कुछ मजबूरियां हैं, आदतें हैं, संख्या भी इनकी बहुत कम है । महोदय, 2005, नवंबर में जब सूबे की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी को जिम्मेदारी दी तब उन्होंने सुशासन का और न्याय के साथ विकास की मजबूत आधारशिला रखी और उनका मानना है कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे समाज में आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और बौद्धिक विकास किया जा सकता है और इसी सोच के साथ उन्होंने महात्मा गांधी से प्रेरणा लेते हुए और समाजवादी की सोच के विचारधारा के पुरोधा होते हुए उन्होंने सुनिश्चित किया कि शिक्षा की लो सूबे के हर कोने तक जाए और साथ ही साथ समाज के हर वर्ग तक शिक्षा की लो जाए, पहुंच सके शिक्षा जिन्हें आज तक शिक्षा नहीं मिल रही थी, विशेषकर के उन सभी गांव में, कस्बों में वंचित समाज के बच्चों में जो अभी तक शिक्षा से महरूम थे और शिक्षा विभाग ने तो प्रगति की है, शिक्षा की नीति और कल्याणकारी योजनाओं के कारण आज हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं । साथ ही साथ नवाचार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे हमारे बच्चों को आगे चलकर के नौकरी मिले, रोजगार शुरू कर सके, स्टार्ट–अप शुरू कर सके हम सभी क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं । महोदय, इतिहास गवाह है कि किस तरीके से नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जितना नाम था, उतना ही नाम मिथिलांचल में वेद के ज्ञान की भी आस्था और वहां पर भूमि रही है । हमलोग भी चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है, एन0डी0ए0 की सरकार चाहती है कि हम शिक्षा को उन ऊंचाइयों तक ले जाएं और निश्चित रूप से हम सभी जानते हैं कि कल जरूर आयेगा यह तय है महोदय लेकिन कल का स्वरूप क्या होगा, शिक्षा का स्वरूप क्या होगा यह बहुत महत्वपूर्ण है और माननीय

मुख्यमंत्री जी की, हमारी सरकार की जो सोच है और जो योजनाएं हैं उन्हें सुनिश्चित करेंगे कि हमारे छात्र–छात्राओं का भविष्य उज्ज्वल हो, इसी सोच के साथ कि उन्नत शिक्षा–उज्ज्वल भविष्य को लेकर के हम सभी सात निश्चय–3 के साथ आये हैं जिसमें समावेश किया गया है कि हर, जैसा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी अपने बजटीय भाषण में कहा था कि किस तरीके से हर ब्लॉक में मॉडल स्कूल हो, हर ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज होगा, उच्च शिक्षा विभाग को अलग किया गया, सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनेगा, एजुकेशन सिटी का निर्माण होगा ।

क्रमशः

टर्न–28 / सुरज / 19.02.2026

(क्रमशः)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, इन सभी सोचों के साथ हमलोग आगे बढ़ रहे हैं । हम सभी जानते हैं कि पूर्व में शिक्षा की क्या स्थिति थी । हमारे सदस्यों ने बताया और बिहार की जनता भी जानती है कि किस तरीके से स्कूलों की कमी थी, शिक्षकों की कमी थी, आधारभूत संरचना की कमी थी और सबसे बड़ी कमी थी एक शैक्षणिक माहौल की । जो इको सिस्टम था वह इस लायक नहीं था कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकें । इसके लिये सबसे जरूरी था कि हमारे पास पर्याप्त धन हो, राशि हो । जहां 2005 में 04 हजार 400 करोड़ का बजट हुआ करता था और जैसा कि आप जानते हैं कि आज अगर शिक्षा और उच्च शिक्षा को मिला दिया जाए तो हमारा बजट पूरे जो वार्षिक बजट का 20 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत करीब 14 प्रतिशत का है और हमें बताते हुये यह खुशी हो रही है और सदन को सूचित करते हुये कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है यह एनुअल बजट का हिस्सा । महोदय, चूंकि स्कूलों की कमी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित किया कि हर एक किलोमीटर पर प्राईमरी स्कूल होंगे, तीन किलोमीटर पर सेकेंडरी स्कूल होंगे और उसके बाद प्लस टू के स्कलों को भी हर पंचायत में इजाद किया गया । इसके अतिरिक्त यह भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा कि बहुत से ऐसे टोले हैं, बहुत से ऐसे कस्बे हैं, छोटे गांव हैं, वंचित समाज के लोग हैं जो स्कूल नहीं जाया करते हैं । इसी वजह से टोला सेवक की, तालिमी मरकज की जो इजाद किया, उन्होंने इन पदों को जिनकी संख्या आज 26 हजार से ज्यादा है उनके मानदेय को दुगुना किया गया । ये बहुत बड़ा कारण था जिसके कारण गांव और कस्बे से, सभी जगहों से बच्चे आने लगे स्कूलों में । इसका पूरे हिंदुस्तान में दूसरा कोई मिसाल नहीं है, इस तरह की व्यवस्था का और आज भी टोला सेवक और हमारे तालिमी मरकज अच्छे से काम कर रहे हैं । शिक्षकों की कमी को देखते हुये माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हम बी0पी0एस0सी0 के माध्यम से

शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे । अगर हम टी0आर0ई–1, टी0आर0ई–2, टी0आर0ई–3 और जो प्रधान शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, इनकी संख्या जोड़ ली जाए तो 02 लाख 60 हजार से ज्यादा सीधी नियुक्तियां हुई हैं । पूरे देश में इस तरह की नियुक्ति किसी राज्य में नहीं हुई है और 02 नवम्बर, 2023 का वह ऐतिहासिक दिन सबको याद होगा, जब गांधी मैदान से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और जिलों में जो नियुक्ति पत्र बांटे गये 01 लाख 20 हजार शिक्षकों का, उसका भी कोई दूसरा मिसाल आपको हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा ।

महोदय, इसके अतिरिक्त जो हमारे स्थानीय निकाय से शिक्षक आये थे उनको भी सहुलियत दी गयी और एक छोटे से इम्तेहान के बाद आज ढ़ाई लाख स्थानीय निकाय से जो हमारे शिक्षक–शिक्षिकायें हैं, वह भी सरकारी सेवक बन चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो अनुकंपा आधारित हमलोगों ने साढ़े पांच हजार नियुक्तियां की और हम सदन को बताना चाहेंगे कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने लिये हमलोगों ने 07 हजार से ज्यादा रिक्तियों की अधियाचना बी0पी0एस0सी0 को भेजी है और आने वाले समय में हमलोगों ने अपनी अधियाचना टी0आर0ई–4 के माध्यम से हमलोग 45 हजार से ज्यादा शिक्षक–शिक्षिकाओं की नियुक्ति करना चाहते हैं । एक बहुत ही सुनहरा अवसर है बिहार के युवा पीढ़ी के लिये ।

महोदय, इसके अतिरिक्त शिक्षा का स्तर और बेहतर हो सके, हम अनुश्रवण कर सकें ठीक से, इसलिये 935 पोस्ट असिस्टेंट एडुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर की, इसकी भी अधियाचना हमलोगों ने बी0पी0एस0सी0 में भेजी है । अनुश्रवण ठीक से रहे, इसके लिये हमारा जो पोर्टल है, उस पर सारी बातें आती हैं शिक्षा कोष की, लोग भी उस पर शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और हमारी जो नीतियां हैं स्थानांतरण हों या अन्य जो भी विसंगतियां हों, उस पर हमलोगा बहुत ही सहानुभूति से विचार कर रहे हैं । हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि उन्हें तनख्वाह में विलंब होता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शिक्षकों को तनख्वाह देने में कोई विलंब नहीं होता है । उन्हें ससमय पांच तारीख से पहले 05 लाख 87 हजार से ज्यादा शिक्षक–शिक्षिकाओं को तनख्वाह मिलते हैं । एच0आर0एम0एस0 (ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल है हमारा जिसके थ्रू डी0बी0टी0 के माध्यम से ये सारे कुछ किये जाते हैं । यह देखा गया, एन0डी0ए0 सरकार ने देखा कि हमारे छात्र–छात्राओं को गरीबी की वजह से समस्याएं अधिक हैं इसलिये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल्याणकारी योजनाएं शुरू की और उसमें जो छात्रवृत्ति योजना की, यह बताते हुये हमें बहुत संतोष हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कक्षा–1 से लेकर कक्षा–12 तक, जो छात्रवृत्ति की राशि है उसको दोगुना कर दिया है । आने वाले समय में और हम कहना चाहेंगे कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में वर्ग–1 से 12 तक कुल 07 लाख 62 हजार 917 छात्र–छात्राओं को डी0बी0टी0 के माध्यम से

इसका लाभ मिला है । उसी तरह से बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना में भी उन्हें करीब 04 लाख 67 हजार 253 छात्राओं को फायदा हुआ है । जो पोशाक योजना शुरू की गयी, जिसकी चर्चा हमारे सदस्य कर रहे थे और पूरा बिहार जानता है पोशाक योजना, साईकिल योजना के बारे में । पोशाक योजना में भी क्लास–1 से 12 वर्ष 2025–26 में 01 करोड़ 06 लाख 72 हजार 142 छात्र–छात्राओं को डी0बी0टी0 के माध्यम से राशि स्थांतरित की गयी । साईकिल योजना, यूं कहें महोदय कि यह गेम चेंजर साबित हुआ । जिस तरह की परिदृश्य ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिले, शहरों में देखने को मिले कि छात्र–छात्राएं साइकिल से स्कूल जाते हैं और सदन को हम यह भी बताना चाहेंगे कि इसका जो स्टडी है, एक अध्ययन किया यूनाइटेड नेशन के प्रोफेसर ने और इसकी जब रिपोर्ट सब्मिट की, उन्होंने अपने मुख्यालय में तो इसको दो देशों में माले और जाम्बिया में इसी तरह की साइकिल योजना, वहां पर बालिकाओं के लिये शुरू की गयी और वहां भी इसके बहुत बेहतरीन नतीजे देखने को आए । हमलोगों ने सुनिश्चित किया है कि मध्याह्न भोजन ससमय बच्चों को मिले, पौष्टिक भोजन बच्चों को मिले और विपक्ष के सदस्यों को हम बताना चाहेंगे कि ...

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय...

अध्यक्ष : अभी सरकार का जवाब हो रहा है ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : कि यह कोई आसान काम नहीं है । जिस दिन स्कूल चलता है औसतन 01 करोड़ 03 लाख बच्चों को मध्याह्न भोजन दिये जाते हैं । यह खुद में एक बहुत बड़ी चुनौती है....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपको बोलने का मौका मिला था न ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय...

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, शिक्षा की गुणवत्ता को नहीं बढ़ा सकता, वोट को बढ़ा सकता है । बड़ी संख्या में जो निरक्षर हैं, कम पढ़े–लिखे हैं वैसे लोगों को...

श्री सुनील कुमार, मंत्री : आगे आप हमारी बात सुनने का धैर्य रखें । आगे चलकर उसको भी बतायेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्या कर रहे हैं....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : पूरी बात सुन लीजिये । माननीय मंत्री जी आप बोलिये ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : हमलोगों ने थर्ड पार्टी एवेल्युशन भी रखा है और कुछ सदस्यों की प्रश्नकाल में चिंता थी...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपने अपनी बात रख ली है ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : भोजन का स्तर अच्छा नहीं है तो वैसे चार...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : पूरी बात सुनिये न ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : एन0जी0ओ0 को भी हमने रद्द किया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : पूरी बात सुननी चाहिये, पूरी बात सुन लीजिये ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : हमलोगों ने निश्चित किया है कि...

(व्यवधान)

आप जाने का कष्ट करें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया शांति बनाये रखें । सरकार का उत्तर सुनना चाहिये । पूरी बात सुन लीजिये । आप बोलिये माननीय मंत्री जी ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : हमने शुरू में ही कहा कि आप आदत से लाचार हैं । टेक्सट बुक कॉरपोरेशन से भी हमलोगों ने 01 करोड़ 11 लाख बच्चों को टेक्सट बुक दिया है और सुनिश्चित किया है कि हमारे जो 05 लाख 87 हजार टीचर जो कार्यरत हैं, एन0सी0आर0टी0 जो नोडल एजेंसी है, उसके माध्यम से कम से कम साल में दो बार उनकी ट्रेनिंग की जाए और वहां पर नये–नये तरीके से प्रयोग किये जा रहे हैं जैसे प्रोजेक्ट बेस लर्निंग हो रहा है या इस तरह की सारी कार्रवाई हमलोग कर रहे हैं । हमारी माननीय सदस्या भी बोल रहीं थी कि किस तरह से हमलोगों ने साफ–सुथरे एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने का फैसला लिया ।

(क्रमशः)

टर्न–29 / धिरेन्द्र / 19.02.2026

...क्रमशः....

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, और काफी सुधार हुआ है एग्जामिनेशन के प्रणाली में जो बिहार स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड है, पूरे हिन्दुस्तान में पिछले वर्ष सत्र में सबसे पहला वह बोर्ड था जिसने मैट्रिक की परीक्षा और प्लस टू की परीक्षा का रिजल्ट दिया और उसमें एक भी शिकायत नहीं आयी, यह हमारी उपलब्धि है महोदय और उन्हें जैसा कि बताया गया कि Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration भी मिला । इस साल भी 13 लाख से ज्यादा हमारे विद्यार्थी इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हैं । आधारभूत संरचना को मजबूत करना बहुत जरूरी है । 78 हजार हमारे स्कूल हो चुके हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं । बिहार स्टेट एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से हमलोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि चहारदीवारी बनायें, आने वाले समय में गर्मी का समय होगा, सबमर्शिबल पम्प, चहारदीवारी, बेंच, डेस्क इत्यादि जो भी जरूरतें हैं उसको हमलोग शीघ्र आपूर्ति करेंगे । उसकी भी लिस्ट हमलोगों ने बना ली है प्रायोरिटी पर और उस पर भी कार्रवाई करेंगे । हम केन्द्र सरकार

को और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे इस सदन के माध्यम से, क्योंकि पी॰एम॰ श्री जो स्कूल बने हैं बहुत सारे आई॰सी॰टी॰ लैब बने हैं जो तकनीकी फायदे हमलोगों को हो रहे हैं कई स्कूलों में, खासकर जो गांधी स्मारक जो स्कूल हैं जहाँ कन्याएं पढ़ती हैं, उसमें भी उनका सहयोग केन्द्र सरकार का रहा है । हमारे पास जैसा कि हमने कहा कि चुनौतियां बहुत हैं, स्कूल बहुत हैं, 76 हजार से ज्यादा स्कूल हैं, 05 लाख 87 हजार से ज्यादा हमारे टीचर हो गए हैं, इसके अतिरिक्त अब हम हर जगह मॉडल स्कूल और कॉलेज बनाने जा रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी हमलोगों ने जितनी मेहनत की एन॰डी॰ए॰ की सरकार ने और विभाग के पदाधिकारियों ने, कर्मियों ने और जनता का सहयोग मिला, इसके बहुत अच्छे परिणाम भी हैं । हमारे दोस्त चले गए विपक्ष के, जो पूर्व में उनके समय स्कूल के बाहर रहने वाले छात्र–छात्राओं का प्रतिशत 12 था, आज 01 प्रतिशत से कम छात्र–छात्राएं स्कूल से बाहर हैं, उसमें भी आगे ऊंचे स्कूलों में भी हमलोग कोशिश करेंगे । उसी तरीके से चूंकि शिक्षकों की संख्या बढ़ गई है जो पूर्व में छात्र और शिक्षक अनुपात 65 और 01 का था, वह आज 29 और 01 का, 29 छात्र पर 01 शिक्षक, उसमें भी बहुत फायदा हुआ है और इस पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि साक्षरता दर महिलाओं का वर्ष 2001 में करीब 34 प्रतिशत था और वर्ष 2023 के आंकड़ें बताते हैं कि यह 74 प्रतिशत बढ़ गया और इसका असर साक्षरता का प्रजनन दर पर भी पड़ा है और यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि अच्छी शिक्षा के कारण हुई है । महोदय, इस व्यवस्था के अतिरिक्त भी हमलोगों की और स्कूली व्यवस्थाएं हैं जैसे हमारे सैनिक स्कूल हैं, सैनिक स्कूल, नालंदा, सैनिक स्कूल, गोपालगंज वहां भी हमलोगों ने डायट को बढ़ाया, उनके ऑफिस एक्सपेंस को बढ़ाया है और वहां के बच्चे–बच्चियां भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, एन॰डी॰ए॰ वगैरह में जा रहे हैं । केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या, उसमें निर्माणाधीन है, अब 72 हो गए हैं, उसमें भी बहुत इजाफा हुआ है । किलकारी जैसी संस्थाएं भी शिक्षा विभाग देख रहा है जहाँ प्रतिभाओं को आर्ट्स में, फाइन आर्ट्स में, डांस में, म्यूजिक में उन्हें काम करने का अवसर मिल रहा है, उसका भी हम सर्टिफिकेशन जल्द से जल्द करेंगे । उसी तरीके से हमलोगों ने कई एन॰जी॰ओ॰ के साथ, कुछ कॉरपोरेट सेक्टर के साथ भी जो समझौते किए हैं MoU किये हैं जिसे Memorandum of Understanding कहते हैं, उसकी वजह से निश्चित रूप से उनके कैरियर प्रोग्रेशन में भी काफी सहायता मिलेगी ।

महोदय, उच्च शिक्षा के बारे में एक तो विभाग अलग किया गया, वहां भी नई नियुक्तिया होंगी ताकि विभाग अच्छे से चल सके । अब जाकर हमारे पास, पहले यूनिवर्सिटीज की संख्या कम थी, राज्य के विश्वविद्यालय की, अब 15 हो गए हैं और निजी विश्वविद्यालय जो पहले शून्य थे अब 08 हो गए

हैं । साथ ही साथ, हम यह कहना चाहेंगे कि पूरे सदन की हमेशा से चिंता रही है बिहार में, अभी छात्र–छात्राओं को कि कैसे सेशन समय पर हो तो हम खुद भी गए थे जे॰पी॰ यूनिवर्सिटी, वहां जाकर हमने समीक्षा की थी और यह बताते हुए बहुत खुशी है कि माननीय राज्यपाल का भी बहुत सहयोग रहा है और मात्र 02 विश्वविद्यालय ऐसे हैं इस 15 में जहां, जो हमारा सेशन है बहुत थोड़े कुछ महीनों से पीछे है, बाकी सभी जगह सेशन करीब–करीब समय पर आ चुका है ।

महोदय, उच्च शिक्षा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम की शुरूआत की इसका भी और बिल्कुल ब्याजरहित इंटरेस्ट फ्री, आज साढ़े चार लाख विद्यार्थी जो ऑल इंडिया इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साईंस में, आई॰आई॰टी॰ में है, कई मैनेजमेंट स्कूल में है, बिहार में है तो इसका भी कोई दूसरा उदाहरण पूरे देश में नहीं है । यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे सरकार की, एन॰डी॰ए॰ की है कि किस तरीके से हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा में मदद मिल रही है । वहां भी हमलोगों ने जो माननीय सदस्य कह रहे थे कि किस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर की कमी है तो कमीशन के द्वारा भी वहां पर करीब–करीब पौने तीन हजार नियुक्तियां हो चुकी हैं, आने वाले समय में हम और उसमें नियुक्ति करेंगे । हमलोग पारदर्शिता लाना चाहते हैं और एक सामर्थ मॉडल है जिसके बारे में हम सदन को सूचित करना चाहेंगे, वह मॉडल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यू॰जी॰सी॰ के द्वारा इजात किया गया है, अगर वह मॉडल पोर्टल पर आ जाता है तो हमलोगों के बच्चों को एडमिशन में, उनका मार्क–सीट डाउनलोड करने में, डिग्री डाउनलोड करने में बहुत सहूलियत होगी ।

महोदय, उसी तरह से जो हमलोग का साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी, टेक्निकल एजुकेशन की बात है...

(व्यवधान)

आप अलग से मिल लीजियेगा । बोलते हैं कि आपको मौका बहुत मिलता है।

साईंस एण्ड टेक्निकल एजुकेशन में, अब जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि वहां भी जो पहले स्थिति थी, उसमें बहुत सुधार हुआ है, जहां नगण्य संस्थाएं थीं, वहां आज 38 इंजीनियंरिंग कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक की संख्या 46 है, माननीय मुख्यमंत्री हमारे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं और वहां का जो प्लेसमेंट रेट है, जो नौकरियां मिल रही हैं बच्चों को, वह बहुत अच्छा है और साईंस एण्ड टैक्नोलॉजी के द्वारा जो प्लेनेटोरियम है दरभंगा में और पटना में, इसके अतिरिक्त दो और प्लेनेटोरियम बनाने का प्रस्ताव है । साईंस सिटी जो राजेन्द्र नगर स्टेडियम के बगल में है वह भी देखने योग्य है । अब्दुल कलाम साईंस सिटी, वहां भी बहुत काम हो रहा है लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय

पर जरूर बोलना चाहूंगा इस विभाग के बारे में महोदय कि आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा और आज दिल्ली में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, इम्पैक्ट समिट चल रहा है । हमलोगों ने जनवरी के माह में ही NASSCOM के साथ एक Memorandum of Understanding की है जिसके तहत आर्टिफिशियल बेस्ड जो सब्जेक्ट्स हैं, वह इंजीनियरिंग कॉलेजेज में पढ़ाये जायेंगे जो निःशुल्क होंगे । इससे हमारे जो बच्चे हैं वे स्किल्ड होंगे और आगे चल कर उन्हें प्लेसमेंट में बहुत सहायता मिलेगी । यह बहुत ही जरूरी था कि हम आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस

(व्यवधान)

मेरी बात सुन लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुन लीजिये उनकी बात को ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : जहां तक माननीय सदस्य को बताना चाहेंगे । माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहिए अपने वक्तव्य में....

अध्यक्ष : अखतरूल ईमान जी, सुनिये । सुनना चाहिए ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य को यह नहीं भूलना चाहिए कि मदरसों का टेक ओवर किसने किया, मदरसों के शिक्षकों को किसने सरकारी सेवक बनाया, मदरसा के शिक्षकों को कौन हर माह तनख्वाह देता है, नीतीश कुमार की सरकार देती है । इसको भी मेंसन कीजिये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपलोग बैठ जाइये । ईमान जी, बैठिये । माननीय मंत्री, आप बोलते रहिये, अपना भाषण जारी रखिये ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, कई बार कई सदस्यों ने शिक्षा विभाग की कमियों के बारे में भी अपनी बातें रखी हैं, वहां भी भ्रष्टाचार के प्रति...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शांति से बैठिये ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, भ्रष्टाचार के प्रति हमलोग जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाये हुए हैं । हमलोगों ने जब जरूरत पड़ी है तो विजलेंस का सहारा लिया है, लोग सस्पेंड हुए है, बर्खास्त हुए हैं तो मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा और कहना भी चाहूंगा कि जीरो टॉलरेंस की हमारी पॉलिसी है, भ्रष्टाचार के प्रति कोई भी सदस्य ऐसी बात हमारे संज्ञान में लाते हैं तो निश्चित रूप से उस पर हमलोग कार्रवाई करेंगे । साथ ही साथ, कई अवसरों पर जो हमारे मेधावी छात्र–छात्राएं हैं, उनको शिक्षक दिवस के दिन, बिहार दिवस के दिन, सभी को हमलोग पुरस्कार से नवाजते हैं ताकि वे लोग आगे बढ़ सकें । हम तो सभी सदस्यों से आग्रह भी करेंगे कि हमारा बिहार दिवस 22 मार्च से शुरू होने वाला है, उसमें आप सभी आमंत्रित हैं, उसमें आप जरूर आइयेगा, काफी अच्छे तरीके से हमलोग उसे मना रहे हैं, काफी मेहनत की जा रही है शिक्षा विभाग के द्वारा

....क्रमशः.....

टर्न–30 / अंजली / 19.02.2026

(क्रमशः)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, We are dreaming big and we are realising your dreams we are attaining our goals. और हमारे कदम मजबूत हैं, एन0डी0ए0 सरकार माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ, साथ ही साथ, जो उनकी सोच है, उनकी दूरदर्शिता है और उनका जो संकल्प है, यह सुनिश्चित करेगा कि आने वाले समय में एक शिक्षित और विकसित बिहार के सपने को हम जरूर साकार करेंगे । आपका बहुत–बहुत धन्यवाद ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर ए॰आई॰एम॰आई॰एम॰ के माननीय सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्य से हम कटौती प्रस्ताव वापस लेने का अनुरोध करते हैं और साथ ही, मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2026–2027 हेतु मांग संख्या–21 में प्रस्तावित 60204,60,95,000 / – (साठ हजार दो सौ चार करोड़ साठ लाख पंचानवे हजार) रुपए के उपबंध को स्वीकृत करने की कृपा करें । जय हिंद, जय बिहार ।

(माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के वक्तव्य का अंश– परिशिष्ट द्रष्टव्य)

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''इस शीर्षक की मांग 10 / – रुपए से घटाई जाय ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''शिक्षा विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 60204,60,95,000 / – (साठ हजार दो सौ चार करोड़ साठ लाख पंचानवे हजार) रुपए से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक–19 फरवरी, 2026 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या–63 (तिरसठ) है । अगर सदन की सहमति हो, तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक–20 फरवरी, 2026 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

दिनांक : 19.02.2026

माननीय अध्यक्ष महोदय,

- हम आपके शुक्रगुज़ार है कि आपने हमें **आज शिक्षा एवं उससे संबंधित विषयों पर प्रस्तावित माँग संख्या–21** पर सदन में अपना वक्तव्य रखने का मौका दिया है।

I. आभार

- **हम माननीय मुख्यमंत्री** के प्रति अपना अभार प्रकट करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें **पुनः शिक्षा विभाग की ज़िम्मेदारी दी है।**
- मैं अपने **विधान सभा क्षेत्र (भोरे) की सम्मानित जनता का भी शुक्रगुज़ार हूँ,** जिन्होंने दोबारा अपना विश्वास प्रकट करते हुए मुझे निर्वाचित कर इस सदन में भेजा।

II. शिक्षा विभाग से सम्बंधित चर्चा के दौरान जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार एवं सुझाव रखें है उन पर निश्चित तौर पर गंभीरतापूर्वक अध्ययन कर विचार करेंगे।

III. उद्देश्य

1. बिहार की जनता ने जब से माननीय मुख्यमंत्री जी को राज्य की बागडोर सौंपी है, तब से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार ने **न्याय के साथ विकास** की एक नई पहचान बनाई है एवं **राज्य में सुशासन** की मज़बूत आधारशीला स्थापित हुई है।
2. **माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि शिक्षा** सुशासन का एक महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि यही **बौद्धिक, आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति का सबसे प्रभावी साधन है।**
3. **माननीय मुख्यमंत्री जी** का प्रयास रहा है कि राज्य में **समावेशी, सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण** शिक्षा दी जाये और साथ ही **कौशल विकास एवं नवाचार पर अधिक ज़ोर दिया गया है।**
4. **राज्य में तकनीक आधारित शिक्षा पर विशेष ज़ोर दिया जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों को स्टार्ट–अप एवं रोज़गार के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकें।**

IV. पृष्ठभूमि

शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है, जो प्राचीन काल में ज्ञान, विज्ञान और दर्शन का विश्व केन्द्र था। **नालंदा और विक्रमशिला जैसे अन्तराष्ट्रीय विश्वविद्यालय बौद्धिक शक्ति के स्तंभ** थे, जहाँ आर्य जैसे विद्वानों ने शिक्षा प्राप्त की वहीं मिथिला के क्षेत्र वैदिक ज्ञान और दर्शन के लिए प्राचीन काल से प्रसिद्व हैं। **एनडीए सरकार का प्रयास है कि बिहार पुनः ज्ञान और विज्ञान का केंद्र बनें।**

V. **7 Nischay–3** "उन्नत शिक्षा : उज्ज्वल भविष्य" का दस्तावेज है।

1. 7 निश्चय बिहार का विशेषकर कर शिक्षा के उज्जवल भविष्य का दस्तावेज है।

2. निश्चय–1 एवं निश्चय–2 के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित लक्ष्यों पर केंद्रित एवं सुनियोजित कार्यों के परिणामस्वरूप राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति हासिल की। इसी को आगे बढ़ाते हुए सात निश्चय–3 (2025–30) अंतर्गत चतुर्थ निश्चय – "उन्नत शिक्षा : उज्ज्वल भविष्य" के तहत निम्न कार्य किये जाने हैं–

(क) प्रत्येक प्रखण्ड में आदर्श विद्यालय की स्थापना करना।

- वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए सात निश्चय–3 के अन्तर्गत मॉडल स्कूल की स्थापना करने हेतु 800.00 करोड़ रूपये एवं पुराने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने हेतु 200.00 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

(ख) प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलना।

- राज्य सरकार द्वारा सात निश्चय–3 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 से राज्य के **वैसे सभी 213 प्रखंडों में डिग्री महाविद्यालयों की स्थापना कराने का निर्णय लिया गया है, जिन प्रखंडों में पूर्व से डिग्री महाविद्यालय** स्थापित नहीं है।

(ग) नए उच्च शिक्षा विभाग का गठन

- नये उच्च शिक्षा विभाग के गठन से संबंधित अधिसूचना जारी की जा चुकी है तथा विभाग के स्थायी पदों का सृजन भी किया जा चुका है

(घ) पुराने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करना।

- राज्य सरकार द्वारा सात निश्चय–3 के अंतर्गत राज्य के प्रतिष्ठित महाविद्यालयों/सस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की योजना है। वित्तीय वर्ष 2026–27 में इसके अंतर्गत 31 महाविद्यालयों को विकसित करने की योजना है।

(ड़) एक नये एजुकेशन सिटी का निर्माण करना।

- राज्य में एक नये "एजुकेशन सिटी" के निर्माण हेतु विस्तृत कार्य योजना तैयार करने का कार्य किया जा रहा है।

VI. पूर्व की स्थिति

- वर्ष 2005 से पूर्व बिहार में शिक्षा की स्थिति किसी भी सूरत में अच्छी नहीं थी। फिर चाहे वह बजट उपबंध हो, स्कूलों की या शिक्षकों की संख्या हो, साक्षरता दर हो विशेषकर महिलाओं की साक्षरता दर बहुत कम थी तथा उच्च शिक्षा की भी स्थिति खराब थी।

VII. उठाये गये सकारात्मक कदम

1. बजट में वृद्धि :–

	2005-06	2026-27
शिक्षा पर व्यय	4438.80 करोड़ (चार हज़ार चार सौ अड़तीस करोड़ अस्सी लाख रूपये)	60204.60 करोड़ (साठ हजार दो सौ चार करोड़ साठ लाख)

- राज्य के कुल बजट का लगभग 20 प्रतिशत शिक्षा व्यय पर उपबंध करते हुए बिहार को शिक्षा में नई पहचान दी गई है। यह अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है एवं राष्ट्रीय स्तर से बहुत अधिक है।

2. शिक्षा का विस्तार–

I. माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने शिक्षा का विस्तार करते हुये सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक 01 किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय, 03 किलोमीटर पर मध्य विद्यालय एवं प्रत्येक पंचायत में उच्चतर माध्यमिक

विद्यालय तक की शैक्षणिक व्यवस्था तथा प्रत्येक प्रखण्ड स्तर पर डिग्री महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है।

II. टोला सेवक एवं तालिमी मरकज सेवक

- कुल शिक्षा सेवकों (तालीमी मरकज सहित) की संख्या–26,355 (छब्बीस हजार तीन सौ पचपन)
- मानदेय को दोगुना कर दिया गया है।
- पहले बच्चों की विद्यालय से बाहर रहने की संख्या अत्याधिक थी परन्तु माननीय मुख्यमंत्री के नवाचार प्रयास जिसमे **टोला सेवक एवं तालिमी मरकज सेवकों की बहाली की गयी।** यह एक सराहनीय पहल है, जो शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। **ऐसी व्यवस्था अन्य किसी राज्य में नहीं है, जो बिहार सरकार की समर्पित एवं दूरदर्शी नीतियों को दर्शाती है।**

3. नियुक्ति :–

a) माननीय सदस्यों को याद होगा कि बिहार सरकार ने एक ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व कदम उठाते हुए नई नियुक्ति करने में कीर्तिमान स्थापित किया, जब 2 नवंबर 2023 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान सहित राज्य के विभिन्न जिलों में आयोजित भव्य कार्यक्रमों के माध्यम से 1,20,336 (एक लाख बीस हजार तीन सौ छत्तीस) नवनियुक्त शिक्षकों को दिन में नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए, जो राज्य के शैक्षिक इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो गया।

b) राज्य सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों में बिहार लोक सेवा आयोग पटना के माध्यम से तीन चरणों में 2,27,224 (दो लाख सत्ताईस हजार दो सौ चौबीस) शिक्षकों की नियुक्ति कर ऐतिहासिक समय में योगदान करा दिया गया है, जो देश के लिए एक मिसाल है और राज्य को गौरवान्वित करता है।

TRE-1 नियुक्ति शिक्षक	1,02,907 (एक लाख दो हजार नौ सौ सात)
TRE-2 नियुक्ति शिक्षक	70,212 (सत्तर हजार दो सौ बारह)
TRE-3 नियुक्ति शिक्षक	54,105 (चौवन हजार एक सौ पाँच)

c) बिहार में कुल शिक्षकों में 44 प्रतिशत शिक्षक महिलाएँ हैं, जो सशक्तिकरण की नई मिसाल है।

d) प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक

BPSC के माध्यम से नियुक्त कुल प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक- 33,474 (तैंतीस हजार चार सौ चौहत्तर)

BPSC के माध्यम से प्रधान शिक्षक की नियुक्ति	28,773 (अट्ठाईस हजार सात सौ तिहत्तर)
BPSC के माध्यम से प्रधानाध्यापक की नियुक्ति	4,701 (चार सात सौ एक)

e) इस प्रकार BPSC के माध्यम से कुल शिक्षकों (प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक सहित) की नियुक्ति - 2,60,698 (दो लाख साठ हजार छह सौ अट्ठानवे) की गई है।

f) चतुर्थ चरण (**TRE-4**) में राज्य के सरकारी प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में 45,198 (पैंतालीस हजार एक सौ अट्ठानवे) शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अधियाचना **BPSC** को भेजी जा चुकी है।

g) अनुकंपा के आधार पर 5,236 (पाँच हजार दो सौ छत्तीस) लिपिक एवं 582 परिचारी (कुल 5,818 - पाँच हजार आठ सौ अठारह) की नियुक्ति की गई है।

h) राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में नामांकित दिव्यांग अथवा विशेष आवश्यकता वाले छात्र/छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 7,279 (सात

हजार दो सौ उन्यासी) विशेष विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

i) बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 10 पंचायतों पर एक सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी **(Assistant Education Development Officer (AEDO))** की कुल 935 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

j) भविष्य में शिक्षा विभाग द्वारा लाइब्रेरियन के संबंधित पदों पर नियुक्ति किए जाने पर भी विचार किया जा रहा है।

k) कुल 2,53,961 स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों को दो चरणों में आयोजित सक्षमता परीक्षा उपरांत राज्य कर्मी का दर्जा दिया गया है।

- सक्षमता 3 एवं 4 में कुल 12,819 (बारह हजार आठ सौ उन्नीस) अभ्यर्थी सफल घोषित हुए है। जिसमें अधिकांश की काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है। जल्द इन्हें भी भी राज्य कर्मी का दर्जा मिल जायेगा ।
- सक्षमता परीक्षा (पंचम) के लिए ऑनलाईन आवेदन प्राप्त कर लिया गया है जिसकी परीक्षा शीघ्र ही आयोजित की जायेगी।
- स्थानीय निकाय के शिक्षक जो प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय अध्यापक के रूप में चयनित होकर कार्यरत हैं, को विशिष्ट शिक्षक की भाँति वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
- स्थानीय निकाय शिक्षक (नियोजित शिक्षक), विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक की आपसी वरीयता से संबंधित आदेश निर्गत कर दिया गया है।

VIII. <u>शिक्षकों के स्थानांतरण</u> :–

- ई–शिक्षाकोष पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा कुल 1,27,240 शिक्षकों का स्थानांतरण (पारस्परिक स्थानांतरण सहित) किया गया है, जिसमें असाध्य रोग से ग्रसित 690 शिक्षकों का स्थानांतरण सम्मिलित है।

IX. अनुश्रवण व्यवस्था :–

- शिक्षा विभाग अन्तर्गत सम्पादित किये जा रहे गतिविधियों के ऑन लाईन अनुश्रवण हेतु **e-Shikshakosh** पोर्टल एवं माबाईल ऐप विकसित कराया गया है। राज्य के सभी सरकारी प्रारंभिक एवं माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों/शिक्षकों की तकनीकि आधारित प्रतिदिन उपस्थिति **e-Shikshakosh** मोबाईल ऐप के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। साथ ही इस पोर्टल पर किसी भी प्रकार के छुट्टी एवं स्थानांतरण का आवेदन अपलोड किया जा रहा है।
- पंचायतों पर एक सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी **(Assistant Education Development Officer (AEDO))** की नियुक्ति किये जाने से अनुश्रवण और बेहतर हो सकेगा।

X. कल्याणकारी योजना

1. छात्रवृत्ति योजना :–

- आज मुझे गर्व के साथ यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कक्षा 1 से 12 तक के हमारे बच्चों को मिलने वाली सभी छात्रवृत्ति राशि पहले से दोगुनी कर दी गई है ।
- वित्तीय वर्ष 2025–26 में वर्ग I से XII तक के कुल 7,62,917 (सात लाख बासठ हजार नौ सौ सत्रह) छात्र–छात्राओं को डी.बी.टी. के माध्यम 846 करोड रुपये की राशि उनके बैंक खाते अंतरित की जा रही है ।

कक्षा वर्ग	दी जाने वाली राशि दर	
	पहले	वृद्धि के बाद
वर्ग 1 से 4	600	1200
वर्ग 5 से 6	1200	2400

वर्ग 7 से 8	1800	3600
वर्ग 9 से 10	1800	3600
वर्ग 11 से 12	1800	3600

2. मुख्यमंत्री बालिका (इन्टरमीडिएट प्रोत्साहन) योजना :–

- वित्तीय वर्ष 2025–26 में **4,67,253** (चार लाख सड़सठ हजार दो सौ तिरपन) छात्राओं को डी.बी.टी. के माध्यम से **11,68,13,25,000** (ग्यारह अरब अड़सठ करोड़ तेरह लाख पचीस हजार रूपये) रुपये की राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की जा रही है ।
- वित्तीय वर्ष 2018–19 से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इन्टरमीडिएट की परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त सभी कोटि के अविवाहित छात्राओं को इस योजना के तहत प्रति छात्रा **₹25,000** (पच्चीस हजार रूपये) उपलब्ध करायी जाती है।

3. मुख्यमंत्री बालिका/मुख्यमंत्री पोशाक/शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना :–

- वित्तीय वर्ष 2025–26 में वर्ग I से XII तक के कुल **1,06,72,142** (एक करोड़ छह लाख बहत्तर हजार एक सौ बयालीसे) छात्र–छात्राओं को डी. बी.टी. के माध्यम से **1251.07 करोड** (एक हजार दो सौ इक्यावन करोड़ सात लाख) रुपये की राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की जा रही है ।

4. मुख्यमंत्री बालिका/बालक साईकिल योजना :–

- वित्तीय वर्ष 2007–08 में योजना शुरू की गयी ।
- वित्तीय वर्ष 2025–26 में से **9वीं कक्षा के** छात्र–छात्राओं **को प्रति** छात्र–छात्रा **3,000/–(तीन हजार रूपये) की दर से** कुल **7,44,401** (सात लाख चवालीस हजार चार सौ एक) छात्र–छात्राओं को डी.बी.टी. के माध्यम से **2,23.32 करोड़ (दो सौ तेइस करोड़ बत्तीस लाख रूपये)** रुपये की राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की जा रही है ।

- माननीय मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच के तहत शुरू की गई साइकिल प्रोत्साहन योजना की प्रभावशीलता इतनी उल्लेखनीय रही कि इसका अध्ययन अमेरिका के एक प्रोफेसर द्वारा किया गया और इसे विश्व बैंक में प्रस्तुत किया गया। इस अध्ययन के निष्कर्षों ने विश्व बैंक को इतना प्रभावित किया कि उसने **जाम्बिया और माले जैसे दो देशों में शिक्षा सहायता राशि** में वृद्धि की, ताकि वहाँ भी अधिक से अधिक छात्राएँ साइकिल के माध्यम से विद्यालय तक पहुँच सकें। **यह न केवल बिहार सरकार की योजनाओं की प्रभावशीलता और दूरगामी सोच को प्रमाणित करता है, बल्कि महिला सशक्तिकरण और शिक्षा तक सहज पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना को भी दर्शाता है।**

XI. पी०एम० पोषण योजना (मध्याह्न भोजन योजना) :–

- बिहार राज्य में पी०एम० पोषण योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में **औसतन प्रतिदिन 1,03,83,675 छात्र/छात्राओं को पोषणयुक्त आहार उपलब्ध** कराने में **कुल 2452.53 करोड़** की राशि व्यय की गई है।
- **मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत कार्यरत रसोइयों की संख्या 2,05,000 (दो लाख पाँच हजार) है। जिनका मानदेय ₹1,650 से बढ़ाकर ₹3,300 कर दिया गया है।**
- गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु किये जा रहे मुख्य कार्य
  - <u>मध्याह्न भोजन का सैम्पल जाँच</u>–विद्यालयो में बनाये जा रहे मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता जाँच हेतु NABL प्रमाणित संस्था का चयन करते हुए राज्य के 02 प्रतिशत विद्यालयों में बनाये जाने रहे पके–पकाये भोजन की गुणवत्ता जाँच कराया जा रहा है।
  - **<u>Third Party Evaluation</u>** – मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य/केन्द्र के प्रतिष्ठित संस्थानों के

माध्यम से कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं के केन्द्रीयकृत रसोईघर का Third Party Evaluation प्रत्येक वर्ष कराया जाता है।

- ○ प्रशिक्षण एवं पाक कला प्रतियोगिता– होटल प्रबंधन संस्थान के माध्यम से भी प्रत्येक जिला के चयनित रसोईयों को प्रशिक्षण एवं पाक कला प्रतियोगिता कराया जाता है। इसके अतिरिक्त जिला एवं प्रखंड स्तर पर भी रसोईयों को एवं पाक कला प्रतियोगिता कराया जाता है।

- छात्रों के Feedback एवं मूल्यांकन के आधार पर C श्रेणी प्राप्त करने वाले 06 केन्द्रीयकृत रसोईघर यथा– मशरख तथा परसा (सारण), खगड़िया (खगड़िया), बहादुरगंज (किशनगंज), नावानगर (बक्सर) तथा चकाई (जमुई) का अवधि विस्तार नहीं दिया गया अर्थात उक्त केन्द्रीयकृत रसोईघर से मध्याह्न भोजन की आपूर्ति बंद कर दी गई है।

XII. निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक (Textbook Corporation) :–

शैक्षणिक सत्र 2025–26 में निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक		
वर्ग	छात्र–छात्राओं की संख्या	निःशुल्क पुस्तक एवं स्कूल डायरी की संख्या
वर्ग–1 से 8	1.11 करोड़	11.50 करोड़

- **शैक्षणिक सत्र 2026–27 में कक्षा 01 से 08 तक के विद्यार्थियों हेतु लगभग 12. 50 करोड़ पाठ्यपुस्तकों एवं स्कूल डायरी के निःशुल्क वितरण का लक्ष्य** निर्धारित है, जिसके **अंतर्गत 12.02.2025 तक लगभग 95 प्रतिशत पाठ्यपुस्तकें एवं स्कूल डायरियाँ प्रखंड स्तर तक पहुँचा दी गई हैं**, जबकि शेष 5 प्रतिशत पाठ्यपुस्तकें एवं स्कूल डायरियाँ फरवरी माह के अंत तक उपलब्ध करा दी जाएँगी।

XIII. शिक्षक प्रशिक्षण (SCERT):–

- राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, पटना के माध्यम से सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों/शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष रिफ्रेशर कोर्स अन्तर्गत गणित एवं विज्ञान विषय से संबंधित प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग

कार्यक्रम का प्रशिक्षण एवं दीक्षा माइक्रो इम्प्रुवमेंट प्रोजेक्ट का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। **वित्तीय वर्ष 2025–26 में अब तक लगभग 3.00 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।**

- **वित्तीय वर्ष 2026–27 में लगभग 6.00 लाख शिक्षकों का प्रशिक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।**
- **AI**- SCERT के माध्यम से भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पर ज़ोर दिया जा रहा है AI की सहायता से विभिन्न शैक्षिक एवं जागरूकता आधारित वीडियो विकसित किए गए हैं।
- **प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग (PBL)** - राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, बिहार, पटना के द्वारा राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के सतत् व्यावसायिक विकास (CPD) अंतर्गत प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग (PBL) आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

XIV. बोर्ड एवं परीक्षा संचालन :–

1. पिछले कुछ वर्षों से समिति देश में सबसे पहले इंटर और मैट्रिक की वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम जारी कर रही है, जो लाखों विद्यार्थियों के हित में है।

माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 का परीक्षाफल

परीक्षा	कुल सम्मिलित विद्यार्थी	कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी	कुल उत्तीर्णता
माध्यमिक	**1558077** (पंद्रह लाख अट्ठावन हजार सतहत्तर)	**1279294** (बारह लाख उन्नासी हजार दो सौ चौरानवे)	**82.11%**
इन्टरमीडिएट	**1280211** (बारह लाख अस्सी हजार दो सौ ग्यारह)	**1107330** (ग्यारह लाख सात हजार तीन सौ तीस)	**86.50%**

2. सदन को यह अवगत कराने में मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिनका महिला सशक्तिकरण एवं महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान है, उनकी इस पहल के कारण **इन्टरमीडिएट परीक्षा में पिछले वर्षो की तरह इस वर्ष भी छात्रों की अपेक्षा छात्राओं के उर्तीण होने का प्रतिशत अधिक है।**
3. **इस वर्ष 2026 में इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, हेतु कुल 13,17,846 परीक्षार्थियों ने फॉर्म भरा है जिसके लिए कुल 1762 परीक्षा केंद्र बनाये गए हैं एवं मैट्रिक वार्षिक परीक्षा हेतु कुल 15,12,963 परीक्षार्थियों ने फॉर्म भरा है जिसके लिए कुल 1689 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।**
4. **परीक्षा प्रणाली में सुधार:** परीक्षा समिति ने **मॉडर्न टेक्नोलॉजी** का उपयोग कर परीक्षा प्रणाली और कार्य प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलावों को अंगीकार किया है।
5. **प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार:** बिहार विद्यालय परीक्षा समिति देश का पहला बोर्ड बना जिसे **"नव प्रयोगों और परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधारों"** के लिए **Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration** से भी सम्मानित किया गया है।
6. **अन्य बोर्ड के विद्यार्थियों द्वारा बिहार बोर्ड में नामांकन लेने में वृद्धि :–** बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की उत्कृष्ट प्रणाली ने न केवल राज्य के छात्रों का विश्वास जीता है, बल्कि अन्य बोर्डों, यहां तक कि सीबीएसई के छात्रों को भी आकर्षित किया है। बिहार बोर्ड की यह प्रगति शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों की ओर संकेत करती है।

XV. <u>असैनिक कार्यों का क्रियान्वयन</u> (BSEIDC):–

1. बिहार के विद्यालयों एवं उच्च शैक्षणिक संस्थानों में आधारभूत संरचना का विकास तेजी से किया जा रहा है और यहाँ सुनिश्चित किया जा रहा है कि

- सभी स्कूल में कक्षाएँ अच्छी अवस्था में हों,
- बच्चों के लिए बेंच–डेस्क उपलब्ध हों,
- पेयजल, पुस्तकालय, प्रयोगशाला की सुविधा हों,
- छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग–अलग शौचालय की उपलब्धता हों,

- विशेष श्रेणी के बच्चों (Child With Special Need) के लिए शौचालय की उपलब्धता हो,
- रंग–रोगन, चहारदीवारी, विद्युत कनेक्शन, पंखा, ट्यूब लाईट एवं बल्ब की उपलब्धता हो,
- वित्तीय वर्ष 2025–26 में 2245.11 करोड़ रूपये का आवंटन आधारभूत संरचना विकास हेतु आवंटित किया गया है।
- शिक्षा विभाग अंतर्गत दिनांक 20.09.2025 को 958.79 करोड़ की लागत से 259 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं 72 योजनाओं का शिलान्यास **माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से किया गया था**
- वित्तीय वर्ष 2026–27 में प्रारंभिक विद्यालयों में निर्माण कार्य हेतु 210.00 करोड़ तथा जीर्णोद्धार एवं मरम्मति कार्य हेतु 194.50 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य हेतु 150.00 करोड़ तथा जीर्णोद्धार एवं मरम्मति कार्य हेतु 150.45 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया हैं।

2. <u>तकनीकि आधारित शिक्षा (ICT Lab/Smart Class) :–</u>

आज शिक्षा का आधार ज्ञान, सूचना और अनुभव का समन्वय है, जिसमें आधुनिक तकनीकी और संसाधनों का उपयोग भी शामिल है।

- प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में नामांकित छात्र–छात्राओं को तकनीकी आधारित शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 2107 सरकारी मध्य विद्यालयों एवं 627 कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय में Smart Class के रूप में विकसित कर संचालन का कार्य किया जा रहा है।
- विद्यालयों में ICT लैब की स्थापना से अध्ययनरत छात्रों के ज्ञानवर्धन, डिजिटल शिक्षा तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वातावरण विकसित होता है। वर्तमान में राज्य के कुल 5277 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं 627 केजीबीवी में ICT लैब की स्थापना की जा रही है।

- **PM-SHRI**– 836 विद्यालयों (यथा– 47 प्रारंभिक एवं 789 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय) के लिए भारत सरकार द्वारा योजना स्वीकृत।
- वर्ष 2024–25 में राज्य के 4,621 तथा वर्ष 2025–26 में 3,991 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में Integrated Math with Science Lab अधिष्ठापन के लक्ष्य के विरुद्ध क्रमशः 4575 एवं 3387 विद्यालयों में लैब संचालित हो रहे हैं।
- कक्षा 7 के लिए कंप्यूटर (ICT) विषय की पाठ्यपुस्तक का विकास किया गया है।

XVI. चुनौतियाँ (Challenges) :–

- बिहार राज्य में स्कूली शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा से +2 तक) हेतु **कुल 76,117 (छिहत्तर हजार एक सौ सत्रह) सरकारी विद्यालय** है। इनमें **नामांकित छात्रों की संख्या–1.75 करोड़ (एक करोड़ पिछत्तर लाख)** है
- **कुल शिक्षकों (प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक सहित) की संख्या–5.85 लाख** (पाँच लाख पचासी हजार) है।
- **बिहार राज्य में** पी०एम० पोषण योजना अन्तर्गत औसतन प्रतिदिन **1,03,83,675 (एक करोड़ तीन लाख तिरासी हजार छह सौ पचहत्तर)** छात्र/छात्राओं को पोषणयुक्त आहार उपलब्ध कराया जाता है।
- **करोंडो बच्चो को विभिन्न कल्याणकारी योजना अंतर्गत लाभांवित किया जा रहा है।**
- **प्रत्येक प्रखंड में डिग्री खोला जाना है एवं उसमें पदों का सृजन किया जाना है.**
- **2005 में हमारी सरकार आयी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा को प्राथमिकता के आधार पर विकसित करने का निर्णय लिया एवं शिक्षा के विकास हेतु कई सकारात्मक प्रयास किये, जिसका परिणाम है :–**

Part- II सकारात्मक प्रभाव (Positive Impact) :–

1. वर्ष 2005 में 12.5% बच्चे विद्यालय से बाहर थे। उन विद्यालय से बाहर के बच्चों को उम्र सापेक्ष कक्षा में पहुँचाने हेतु विभिन्न केन्द्रों यथा–उत्प्रेरण केन्द्र, उन्नयन केन्द्र, प्रयास केन्द्र, उत्थान केन्द्र, तालिमी मरकज एवं विद्यालय चलें केन्द्र की शुरूआत की गयी। जिसके फलस्वरूपः–

	2005	2024
Out of School Children	**12%**	**1%** से भी कम

2. वर्ष 2005 से 2024 के मध्य सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में व्यापक पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति के बाद अध्यापकों की संख्या में 187 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

	2005	2025
शिक्षकों की संख्या	**2.04** लाख	**5.85** लाख

3. विद्यालीय शिक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात

छात्र शिक्षक अनुपात	2005	2025
	65:1	**29 :1**

4. साक्षरता दर

	2001 की जनगणना		2011 की जनगणना		2023 जाति जनगणना	
साक्षता दर	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
	60. 32%	33.57%	71.20%	51.50%	84.91%	73.91%

5. प्रजनन दर –बिहार में महिलाओं को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के अत्यंत सकारात्मक एवं दूरगामी परिणाम सामने आए हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य में कार्यभार संभाला था, उस समय बिहार की प्रजनन दर लगभग 4.2 थी, किंतु महिलाओं की शिक्षा में निरंतर सुधार के फलस्वरूप **Sample Registration System Statistical Report** 2023 के अनुसार यह दर

अब घटकर 2.8 पर आ गई है। जिस हिसाब से महिलाओं के उत्थान हेतु निरंतर कार्य हो रहा है यह शीघ्र ही 2.0 तक आ जायेगा।

6. बिहार में उच्च शिक्षा में लिंग समानता सूचकांक **(Gender Parity Index)**, जो वर्ष 2015–16 में 0.80 था, वह 2021–22 में बढ़कर 0.92 हो गया है। यह वृद्धि राज्य में महिला शिक्षा को सशक्त करने और लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है।

Part- III

I. सैनिक स्कूल **(DIET मद में राशि की वृद्धि एवं स्थापना मद दो गुना)**

- सैनिक स्कूल गोपालगंज एवं नालंदा में स्थापना मद की राशि को डेढ़ करोड़ रुपये प्रति विद्यालय प्रति वर्ष से बढ़ाकर तीन करोड़ रुपये प्रति विद्यालय प्रति वर्ष कर दिया गया है। इसके साथ ही पोषाहार मद में भी वृद्धि की गई है, जिससे कैडेट्स को अधिक पोषणयुक्त एवं गुणवत्तापूर्ण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, विद्यालयों में भौतिक अवसंरचना विकास, छात्रावास एवं शैक्षणिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु आवश्यक कार्य किए जा रहे हैं।

II. केंद्रीय विद्यालय :–

केंद्रीय विद्यालय स्वीकृति की संख्या	2005	2026
	35	72

- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 में स्वीकृत नवीन 19 केंद्रीय विद्यालय (17 असैनिक क्षेत्र एवं 02 अर्द्धसैनिक क्षेत्र) के स्थाई भवन हेतु भूमि चिन्हित है।

III. **MoU** विद्यालयी से लेकर उच्च शिक्षा तक की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हेतु राज्य सरकार द्वारा 20 से अधिक विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाओं एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ सहकार्यात्मक समझौते **(MoU)** किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से छात्रों को अध्ययन, प्रशिक्षण, डिजिटल संसाधनों, नवाचार एवं शैक्षणिक सहयोग के व्यापक अवसर प्राप्त हो रहे है।

Part- IV

उच्च शिक्षा विभाग

1. **सात निश्चय–3** के अंतर्गत उच्च शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया गया है।

2. **नये पदों का सृजन–** उच्च शिक्षा विभाग के कार्यों के सुचारु संचालन हेतु विभागीय सचिवालय के अंतर्गत पदस्थापित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कुल 161 (एक सौ इकसठ) पदों का सृजन किया गया है तथा शिक्षा निदेशालय से संबद्ध पदों के स्थानांतरण सहित वर्तमान स्वरूप में उच्च शिक्षा विभाग को अंगीकृत करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

3. विश्वविद्यालय की स्थापना

संस्थानों की संख्या	विश्वविद्यालय	2005	2025
	राजकीय विश्वविद्यालय	10	15
	निजी विश्वविद्यालय	0	8

4. **अकादमिक सत्र–** राज्य के अधिकांश विश्वविद्यालयों में अकादमिक सत्र अब लगभग समयबद्ध हो चुके हैं। केवल दो विश्वविद्यालयों में ही वर्तमान में अकादमिक सत्र कुछ विलंब से संचालित हो रहा है, जिसे अगले शैक्षणिक सत्र से पूर्णतः समयानुकूल करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

5. बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजनाः–

- अबतक इस योजना के अन्तर्गत कुल 4,50,945 आवेदकों के लिए ₹13765.96 करोड़ की राशि स्वीकृत की जा चुकी है।
- यह योजना **2 अक्टूबर 2016 को "7 निश्चय योजना"** के अंतर्गत शुरू की गई थी।
- इसका लक्ष्य बिहार के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिसके तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकतम **₹4 लाख** तक का **ब्याज–मुक्त शिक्षा ऋण** उपलब्ध कराया जाता है।

- स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अपनी लोकप्रियता और प्रभावशीलता के कारण बिहार के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हुई है। इस योजना के तहत अब तक आईआईएम् में अध्ययनरत 66 छात्र, **आईआईटी में अध्ययनरत 1,325** छात्र तथा देश के विभिन्न **मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कर रहे 2,696 छात्र लाभान्वित** हो चुके हैं।

6. <u>मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना</u> मुख्यमंत्री कन्या (स्नातक) प्रोत्साहन योजना बिहार सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि उनकी पढ़ाई में कोई बाधा न आए और वे आत्मनिर्भर बन सकें।

   - वित्तीय वर्ष 2025–26 में **1,80,000 (एक लाख अस्सी हजार)** छात्राओं को डी.बी.टी. के माध्यम से **990 करोड़ (नौ सौ नब्बे करोड़)** रुपये की राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की जा रही है ।

7. <u>नियुक्ति –सहायक प्राध्यापक एवं प्रधानाचार्य</u>

राज्य के सभी विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों में नियुक्ति	
सहायक प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति	प्रधानाचार्य के पदों पर नियुक्ति
2450	114

8. **उच्च शिक्षा में 25.00 लाख (पचीस लाख) से अधिक छात्र/छात्राएँ नामांकित हैं।**

9. विश्वविद्यालय कर्मियों को **वेतन एवं पेंशन** का भुगतान **प्रति माह ससमय** हो रहा है।

10. **भाषायी निदेशालय का गठन** – उच्च शिक्षा विभाग के तहत पहले से स्थापित **7 अकादमियों** (मैथिली अकादमी, मगही अकादमी, बिहार राज्य संस्कृत अकादमी, दक्षिणी भारतीय भाषा संस्थान, बिहार बंगला अकादमी, अंगिका अकादमी, भोजपुरी अकादमी) को बिहार स्थानीय भाषा संस्थान के तहत इनका एकीकरण किया जाएगा । एक साझा संस्थागत ढाँचे के अंतर्गत निदेशालय का गठन करते हुये इसके प्रशासनिक प्रक्रियाओं का सरलीकरण,

निर्णय–निर्माण में गति, तथा मानव व वित्तीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। इससे दोहराव कम होगा, लागत–प्रभावशीलता बढ़ेगी और भाषाई कार्यक्रमों का क्रियान्वयन अधिक पारदर्शी एवं परिणामोन्मुख हो सकेगा।

11. <u>वित्तीय पारदर्शिता एवं वित्तीय अनुशासन</u>– विश्वविद्यालयों में वित्तीय पारदर्शिता एवं बेहतर वित्तीय अनुशासन हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं।

12. **<u>Samarth ERP</u>**

- समर्थ एक डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म या ERP सिस्टम है जिसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2019 में शुरू किया गया था,जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) को एक डिजिटल ढांचे के माध्यम से : –
  - छात्र–छात्राओं के नामांकन की प्रक्रिया आसान होगी।
  - परीक्षा–फल प्रकाशन प्रक्रिया आसान होगी।
  - सभी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का वेतन/पेंशन भुगतान ऑनलाइन हो सकेगा।
  - शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों में और अधिक पारदर्शिता आयेगी।
  - प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य (अभिलेखों के संधारण सहित) ऑनलाइन एवं पारदर्शिता के साथ हो सकेंगे।
  - बजट की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जायेगी।
- राज्य के विभिन्न विश्ववद्यालयों में Samarth ERP लागू किया जा रहा है। अभी केवल Purnea University ने SAMARTH के माध्यम से admission लिया है। अन्य विश्वविद्यालयों को भी इसका पालन किया जाना अपेक्षित है।

Part- V

विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

विज्ञान और प्रावैधिकी विभाग को वर्ष 1978 में उद्योग विभाग से अलग एक स्वतंत्र विभाग के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 2023 में विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग नामित किया गया।

1. **संस्थानों की संख्या में बढ़ोत्तरी**– राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005 से वर्ष 2026 की अवधि में विभिन्न प्रकार के नये विश्वविद्यालयों/संस्थानों एवं महाविद्यालयों की स्थापना की गई है।

	विश्वविद्यालय	2005	2026
संस्थानों की संख्या	अभियंत्रण विश्वविद्यालय	0	01
	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय	2	38
	राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान	13	46

2. **नियमित शैक्षणिक सत्र** –विभागान्तर्गत बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय एवं राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद द्वारा नियमित शैक्षणिक सत्र का संचालन किया जाता है।
3. **Placement**–विभागान्तर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में Campus Placement की व्यवस्था की गई है, जिसमें गत 05 वर्षो (2020–2025) तक कुल–30700 छात्रों को देश की प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में नियोजन संभव हुआ है। इन 30700 में राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के कुल–18394 एवं राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों का कुल–12306 छात्र–छात्राओं का नियोजन किया गया है।
4. **AI** – बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय, राज्य के इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) एवं कौशल–आधारित कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नेस्कॉम (NASSCOM) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) किया गया है। इस पहल के अंतर्गत NSQF–

फ्यूचरस्किल्स पाठ्यक्रमों को शैक्षणिक कार्यक्रमों में समाहित एवं एम्बेड किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों को AI एवं अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित आधुनिक कौशल प्राप्त होंगे। इससे छात्रों की रोजगार–योग्यता में वृद्धि होगी तथा उन्हें उद्योग की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप रोजगार प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी।

5. <u>साईंस सिटी</u> – इसी क्रम में **डा0 ए0 पी0 जे0 अब्दुल** कलाम साईंस सिटी का उद्घाटन दिनांक–21.09.2025 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा किया गया।

6. **<u>Planetarium</u>** – जन.मानस में विज्ञान के प्रति अभिरुचि बढ़ाने एवं खगोलीय घटनाओं को रोचक बनाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा पटना सहित राज्य के अन्य जिलों में अत्याधुनिक तारामंडलों का निर्माण कराया गया है। पटना स्थित इंदिरा गाँधी विज्ञान परिसर के तारामंडल का वर्ष 2024 में नवीनीकरण कर आधुनिक प्रोजेक्शन प्रणाली के साथ 3-डी शो प्रारंभ किए गए हैं, जबकि दरभंगा तारामंडल में 2023 से 2-डी एवं 3-डी शो संचालित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त जमुई, पूर्वी चम्पारण एवं पूर्णियाँ में डिजिटल तारामंडल/स्पेस एवं एस्ट्रोनॉमी एजुकेशन सेंटर की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹39.00 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

7. **<u>Online Evaluation</u>**–

- बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की परीक्षा नियमित रूप से करवाई जाती है। बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन AI-IntelliExams के डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। परीक्षा के बाद, छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन करके सुरक्षित रूप से सिस्टम में अपलोड किया जाता है।
- ऑन–स्क्रीन टूल्स की मदद से कॉपी कर जॉच, अंकन और अंक दर्ज किया जाता है।
- मूल्यांकन पूर्ण होने के बाद, अंकों का स्वचालित संकलन (Automatic Compilation) हो जाता है, जिससे मैनुअल त्रुटियों की संभावना कम होती है और प्रक्रिया तेज हो जाती है।

- यह डिजिटल पद्धति तेज परिणाम, फैकल्टी के लिए अधिक सुविधा, तथा मूल्यांकन प्रक्रिया में सटीकता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करती है।
- इसी प्रकार राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद (SBTE) राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान के छात्र–छात्राओं की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन द्वारा OSM (On Screen Marking) प्रणाली से किया जाता है।

IV. शून्य सहिष्णुता (Zero Tolerance) की नीति

माननीय सदस्यों को यह स्पष्ट रूप से अवगत कराना चाहता हूँ कि राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता (Zero Tolerance) की नीति है, और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने वाले कर्मियों अथवा पदाधिकारियों के विरुद्ध नियमों के अनुरूप सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है –

- बिहार शिक्षा सेवा के 70 पदाधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गई है।
- 14 पदाधिकारियों को गंभीर आरोपों के लिए तत्काल निलंबित किया गया है।
- अनुशासनिक कार्यवाही में 25 पदाधिकारियों को दंडित किया गया है।
- एक पदाधिकारी को सेवा से बर्खास्त करने का दण्ड भी विनिश्चित किया गया है।

V. पुरस्कार

शिक्षा विभाग उत्कृष्ट कार्य करने वाले एवं राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले छात्रों, शिक्षकों, पदाधिकारियों एवं कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न अवसरों, जैसे बिहार दिवस, मेधा दिवस, शिक्षक दिवस एवं अन्य महत्वपूर्ण आयोजनों पर उन्हें सम्मानित करता है। इंटर एवं मैट्रिक परीक्षाओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को क्रमशः 2 लाख, 1.5 लाख एवं 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त इंटर के चौथे–पाँचवें तथा मैट्रिक के चौथे से दसवें स्थान

तक आने वाले विद्यार्थियों को भी नकद पुरस्कार के साथ लैपटॉप, प्रशस्ति–पत्र एवं मेडल प्रदान किए जाते हैं। यह पहल न केवल कार्य की गुणवत्ता को बढ़ावा देती है, बल्कि समर्पित अधिकारियों, कर्मियों एवं छात्रों का मनोबल भी ऊँचा करती है।

VI. बिहार दिवस का आयोजन

माननीय सदस्यों को यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि पिछले वर्षों की भाँति इस वर्ष भी बिहार दिवस का भव्य एवं उत्कृष्ट आयोजन 22 मार्च से 24 मार्च तक किया जाना है। इस अवसर पर बिहार की गौरवशाली परंपरा, समृद्ध संस्कृति और विकास यात्रा का स्मरण करते हुए हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं ऐतिहासिक धरोहर का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाता है। बिहार दिवस के माध्यम से राज्य की शिक्षा, तकनीकी नवाचार, आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, कृषि एवं पर्यावरण संरक्षण सहित विभिन्न क्षेत्रों में हुए सकारात्मक परिवर्तनों और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस आयोजन में राज्य के छात्र–छात्राओं के साथ–साथ स्थानीय एवं राष्ट्रीय कलाकारों, शिल्पकारों तथा कारीगरों को मंच प्रदान किया जाता है। इस अवसर पर आप सभी माननीय सदस्यों को सादर आमंत्रित करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

यह समस्त उपलब्धियाँ माननीय मुख्यमंत्री जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति, दूरदर्शी नेतृत्व एवं शिक्षा–केंद्रित विकास दृष्टि का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। Hon'ble Speaker Sir, We have big dreams and we are realizing our dreams as well. हमारी नीति और नियत बेहतरीन है। हम एक शिक्षित और विकसित बिहार के सपनों को जरूर साकार करेगें।

माँग विवरण

माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्तावों के संबंध में सविनय निवेदन है कि शिक्षा को आगे बढ़ाने और राज्य के भविष्य को सशक्त करने के उद्देश्य से वे अपने कटौती प्रस्तावों पर पुनर्विचार करते हुए उन्हें वापस लेना चाहेंगे।

अतः, मैं सदन से निवेदन करता हूँ कि आप सभी माननीय सदस्य शिक्षा विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु माँग संख्या– 21 (शिक्षा विभाग) में प्रस्तावित कुल ₹6,02,04,60,95,000/– (छः सौ दो अरब चार करोड़ साठ लाख पंचानबे हजार रूपये) के उपबंध को स्वीकृत करने की कृपा करें।

***